सिविल सर्विसेस मासिक

— जुन 2020

सिविल सर्विसेस परीक्षाओं के सभी समाधान एक स्थान पर

- सिविल सर्विसेस बोर्ड (सीएसबी)
- लिंग परीक्षण नियमों का स्थगन
- आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी)
- 'उद्भव देश का नाम' GeM प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
- एक्सट्रीम हीलियम स्टार (EHe)
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी (GPAI)
- डोप सबमर्जेंस रेस्क्यु व्हिकल (डीएसआरवी) कॉम्प्लेक्स
- भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन
- हल्द्वानी जैव विविधता पार्क
- राजा परबा त्योहार
- वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020
- भारत ने 2021–22 में UNSC का गैर–स्थायी सदस्य चुना गया
- भारत में चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया
- रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (IDSA)
- योजना – जुलाई 2020

विषय–सूची

प्रारंभिक परीक्षा

नीति एवं शासन

राष्ट्र के नाम से संबंधित याचिका 1
अटॉर्नी जनरल को पुर्ननियुक्त किया गया 1
सिविल सेवा बोर्ड (सीएसबी) 2
लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994 2

अर्थव्यवस्था

आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन 3
पीएम फॉर्मलाईज़ेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएम एफएमई) योजना 4
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) 5
पीएम स्वानिधी 6
पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एएचआईडीएफ) 7
GeM प्लेटफॉर्म 'उद्भव देश' का नाम अंकित होना अनिवार्य 8
विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 8
इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) 9
पीके मोहंती समिति 11

समाज एवं स्वास्थ्य

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 12
कोवैक्सिन 12
शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना (SPARC) 13
'नए सामान्य' को नेविगेट करना 13
वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 14
युक्ति 2.0 15
फेबीफ्लू 16
आरोग्यपथ 17
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 17

विज्ञान एवं तकनीक

अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 18
अनन्या, कीटाणुनाशक स्प्रे 19
एक्सट्रीम हीलियम स्टार (EHe) 19
सत्यभामा 20
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी (GPAI) 20
प्रकृति सूचकांक 2020 21

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

नेपाल–भारत मैत्री 21
नाविक दिवस 2020 22
फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण एजेंसी (UNRWA) 22
कोविड–19 सक्रिय प्रतिक्रिया एवं व्यय समर्थन कार्यक्रम 23
चीन पर अंतर–संसदीय गठबंधन 23

आंतरिक सुरक्षा

मारीच 25
डीप सबमर्जेंस रेस्क्यु व्हिकल (डीएसआरवी) परिसर 25
मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया शामिल 26

भूगोल एवं पर्यावरण

सूर्य का कोरोना 27
भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन 27
मनी लॉन्ड्रिंग एवं अवैध वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट 28
यूपी में हर्बल सड़क योजना 28
सोकोट्रा द्वीप 29
संक्रांति के उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29
मरुस्थलीकरण एवं सूखे से लड़ने का वैश्विक दिवस 30
ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय मंच 31
हल्द्वानी जैव विविधता पार्क 31
विश्व पर्यावरण दिवस 32

कला एवं संस्कृति

लाल–बाल–पाल की भावना को पुनर्जीवित करता पुणे का एनजीओ 33
अगुआडा फेनिक्स 34
रजा पर्व 35

मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन I

कोडुमानल खुदाई 35
ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 36
व्यभिचार 37

सामान्य अध्ययन II

भारत–ऑस्ट्रेलिया आभासी मुलाकात 38
भारत 2021–22 में UNSC का गैर–स्थायी सदस्य बना 39
वंशधारा नदी जल विवाद 41
आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं 42

सामान्य अध्ययन III

असम गैस रिसाव 43
एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली – मुंबई 44
भारत ने चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाया 46
एमएसएमई सेक्टर 47

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) 47

योजना जुलाई 2020 51

प्रारंभिक परीक्षा

नीति एवं शासन

राष्ट्र के नाम से संबधित याचिका

समाचार –

- एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था, 'इंडिया' विदेशी मूल का नाम है। नाम का उद्गम ग्रीक शब्द 'इंडिका' से हुआ है।
- याचिका संविधान के अनुच्छेद 1 में एक संशोधन की मांग करती है, जिसमें कहा गया है कि 'इंडिया, जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा'।
- याचिका के अनुसार शब्द 'इंडिया' को अनुच्छेद से हटा दिया जाए। यह इस देश के नागरिकों को औपनिवेशिक अतीत से बाहर निकलने एवं हमारी राष्ट्रीयता में गर्व की भावना पैदा करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
- इससे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कठिन लड़ाई से प्राप्त आजादी को भी सही ठहराया जा सकेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिका को अभ्यावेदन में बदल दिया जाए एवं उचित निर्णय के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाए।
- कोर्ट ने कहा, "भारत एवं इंडिया दोनों संविधान में दिए गए नाम हैं। इंडिया को पहले से ही संविधान में 'भारत' कहा जाता है।

संविधान क्या कहता है? –

- **अनुच्छेद 1** – भारत के क्षेत्र में निम्न शामिल होंगे – राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश एवं कोई भी क्षेत्र जिसे अधिग्रहित किया जा सकता है।
- प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं यूनियनों के नामों का वर्णन किया गया है। इस अनुसूची में यह भी कहा गया था कि राज्यों एवं क्षेत्रों की चार श्रेणीयाँ होंगी – भाग A, भाग B, भाग C एवं भाग D.
- 1956 में, संविधान के सातवें संशोधन द्वारा भाग A एवं भाग B के राज्यों के मध्य अंतर समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया।

उच्च न्यायालयों में आधिकारिक भाषा

समाचार –

- वकीलों ने 2020 की हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम को चुनौती दी है, जिसके अंर्तगत असंवैधानिक एवं मनमाने ढंग से हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में पूरे हरियाणा की निचली अदालतों में इस्तेमाल किया जा रहा है।

विवरण –

- वकीलों ने तर्क दिया है कि निचली अदालतों के न्यायिक कार्यों में अधिवक्ताओं द्वारा अंग्रेजी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- हिंदी को एकमात्र भाषा के रूप में लागू करने से उन वकीलों के बीच एक अनुचित वर्गीकरण हो जाएगा जो हिंदी में धाराप्रवाह हैं एवं जो नहीं हैं।
- वे कहते हैं कि संशोधन समानता, गरिमा एवं पसंद के पेशे को चुनने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

संवैधानिक प्रावधान –

- अनुच्छेद 348 (1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा सुविधा प्रदान नहीं करती है।
- अनुच्छेद 348 (2) के तहत, राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति की पिछली सहमति के साथ, उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा या राज्य के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी अन्य भाषा को अधिकृत कर सकते हैं, बशर्ते कि उस राज्य में, ऐसे उच्च न्यायालयों की प्रमुख पीठ, द्वारा पारित निर्णय या आदेश अंग्रेजी में होंगे।
- आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7, के अनुसार उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय आदि, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या राज्य की आधिकारिक भाषा का उपयोग भारत के राष्ट्रपति की सहमति से, राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
- राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही में हिंदी के वैकल्पिक उपयोग का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।

अटॉर्नी जनरल पुर्ननियुक्त

समाचार –

- हाल ही में केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल के कार्यकाल को एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया है। के. के. वेणुगोपाल के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कार्यकाल का भी तीन वर्ष के लिये विस्तार किया गया है।
- जून 30, 2017 को के. के. वेणुगोपाल को, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के स्थान पर, 3 वर्ष के कार्यकाल के लिये भारत का 15 वाँ अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था।

के. के. वेणुगोपाल –

- के. के. वेणुगोपाल का जन्म वर्ष वर्ष 1931 में हुआ था एवं उन्होंने एक अधिवक्ता के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1954 में की थी।
- गौरतलब है कि के. के. वेणुगोपाल को एक अधिवक्ता के तौर पर 50 से भी अधिक वर्षों का अनुभव है एवं उन्हें संवैधानिक मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है।

विवरण –

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत का अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है एवं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- भारत सरकार के मुख्य कानून सलाहकार होने के नाते अटॉर्नी जनरल सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त भारत का अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है।
- अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिये आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का पाँच वर्षों का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो।

- संविधान में अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, अटॉर्नी जनरल के पारिश्रमिक का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

कार्य एवं शक्तियाँ	अधिकार
●भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। ● विधिक स्वरूप वाले ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। ● उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना। ● भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। ● संविधान अथवा किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किये गए कृत्यों का निर्वहन करना।	●केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होता है। ● वहीं अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने अथवा कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बिना भाग लेने का भी अधिकार होता है। ● एक संसद सदस्य की तरह अटॉर्नी जनरल को सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं।

संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

समाचार –

- संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जून 30, 2020 को मनाया गया।
- वर्ष 2020 की थीम 'महामारी के समय में संसद' है।
- यह दिन संसदों के लिए स्टॉक लेने, चुनौतियों की पहचान करने और उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने के तरीको की पहचान करने के लिए एक अवसर हैं।
- यह दिवस उन तरीकों को मनाता है जिससे सरकार की संसदीय प्रणाली दुनिया भर के लोगों के दिन–प्रतिदिन के जीवन को बेहतर बनाती है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव में, राष्ट्रीय योजनाओं एवं रणनीतियों में संसदों की भूमिका एवं राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तरों पर अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की मान्यता दी।
- यह तारीख 1889 में भी है, जिस पर अंतर–संसदीय संघ (IPU), वैश्विक संगठन संसदों, की स्थापना की गई।
- आईपीयु को संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- यह संसदों के लिए एक समय है कि वे कुछ प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति की समीक्षा करें।
- यह समय उनके साथ आगे बढ़ने, अधिक महिला और युवा सांसदों को शामिल करने और नई तकनीकों के अनुकूल होने का भी समय है।

सिविल सेवा बोर्ड (सीएसबी)

- पंजाब सरकार ने IAS अधिकारियों का निश्चित कार्यकाल देने के लिए सिविल सेवा बोर्ड (CSB) को सूचित कर दिया है।

सरकार के इसके पक्ष में दिए गए तर्क	विरोधी तर्क
यदि अधिकारियों का एक कार्यकाल निश्चित होगा तो वे बेहतर सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम होंगे। वे सुरक्षित महसुस करेंगे एवं नेताओं की खुशामद करने के बजाए नियमों पर अडिग रहेंगे। अधिकारियों को नियुक्ति की नई जगह पर समायोजित होने में तीन से छः माह का समय लगता है। यदि उनकी नियुक्ति वहाँ दो वर्ष के लिए की जाएगी तो वे अच्छे परिणाम दे पाएंगे।	प्रशासनिक अधिकारियों को निश्चित कार्यकाल देने संबंधी इस सूचना से राज्यों के कई नेता परेशान हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अधिकारियों की नियूक्ति या स्थानातरण राज्य का अधिकार है। उनका कहना है कि ऐसा करने से राज्य के प्रशासन में बाधा उत्पन्न होगी तथा यह राज्य सरकार के अधिकारों का हनन भी होगा। निश्चित कार्यकाल के होने एवं अधिकारियों के स्थानांतरण के प्रत्येक मामलें को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले मंडल द्वारा मंजुरी की आवश्यकता के बाद नेताओं का प्रभाव कम हो जाएगा।

सीएसबी का विवरण –

- 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं राज्यों को निर्देश दिया कि वे नौकरशाहों के स्थानांतरण एवं पोस्टिंग पर विचार करने के लिए सीएसबी स्थापित करें।
- CSB राजनीतिक आकाओं द्वारा सिविल सेवकों के बार–बार स्थानांतरण का अंत करती है। यह अपने कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले एक सिविल सेवक के स्थानांतरण पर कड़ा निर्णय है।
- इसका उद्देश्य राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही को बचाना भी है।

CSB की संरचना –

- राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है।
- इसमें वरिष्ठतम अतिरिक्त मुख्य सचिव या अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, वित्तीय आयुक्त या सदस्य के रूप में समकक्ष रैंक एवं स्थिति के अधिकारी होते है।
- इसके अतिरिक्त, इसके सदस्य सचिव के रूप में राज्य सरकार में कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव या सचिव होंगे।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

समाचार –

- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कोविड–19 संबंधी देशव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण एवं लिंग चयन के विरुद्ध मौजूदा संसदीय कानून के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को जून माह के अंत तक निलंबित करने के निर्णय को लेकर व्याख्या प्रस्तुत करने को कहा है।
- सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के नियम 8, 9(8) एवं 18।(6) को निलंबित कर दिया था।
- भारत में लैंगिक पक्षपातपूर्ण लिंग चयन की प्रथा के कारण जन्म के समय से ही गायब लड़कियों की संख्या वर्ष 2001–12 की अवधि में प्रति वर्ष 0.46 मिलियन थी।
- विशेषज्ञों का मत है कि इसके कारण लिंग निर्धारण की निंदनीय प्रथा को बढ़ावा मिलेगा।

गैरसैण

समाचार –

- गैरसैण (चमोली जिले, उत्तराखंड में तहसील) को औपचारिक रूप से राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है।
- उम्मीद है कि यह घोषणा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाएगी।
- देहरादून की मौजूदा अस्थायी राजधानी से इसकी दूरी लगभग 270 किमी है।
- जब नवंबर 9, 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य के रूप में बनाया गया था, तो राज्य के नेताओं ने तर्क दिया था कि गैरसैण पहाड़ी राज्य की राजधानी बनने के लिए सबसे उपयुक्त हैं क्योंकि यह कुमाऊँ एवं गढ़वाल दोनों क्षेत्रों के मध्य में है।
- इस हालिया घोषणा के साथ, देहरादून की स्थिति पर स्पष्टता की कमी है। हाल ही में, राज्य सूचना विभाग की निर्देशिका प्रकाशित की गई है जिसमें अभी भी अस्थायी राजधानी के रूप में इस औपनिवेशिक शहर का उल्लेख है।

द्वारा 1018 शहरों एवं कस्बों के नामों की वर्तनी में बदलाव करें

समाचार –

- तमिलनाडु सरकार ने अपने तमिल उच्चारण के करीब वर्तनी बनाने के लिए कोविड–19 के बीच अंग्रेजी भाषा से प्रचलित 1,018 स्थानों का नाम बदल दिया है।
- अभी केवल लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण स्थानों की वर्तनी में बदलाव किया गया है। बाकी विभिन्न स्थानीय निकायों एवं विभागों के लिए छोड़ दिया गया है।
- सरकार ने दो साल पहले नामों में बदलाव को अधिसूचित किया था, जब तमिल राजभाशा एवंत मिल संस्कृति मंत्री, मा फोई के. पंडियाराजन ने इसे विधानसभा में पेश किया था।

कुछ नए नाम –

- कोयंबटूर, जिसे भारत के मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है, अब कोयम्पुथथूर है।
- वेल्लोर अब विल्लूर
- मायलापोर है एवं अब मयिल्लापुर है।
- पुंढमाली अब पुवीरूनथमल्ली
- धर्मपुरी अब थरूमपुरी है
- तुतीकोरन अब थुत्तुकुड़ी
- तिरुवरुर अब थिरूवरूर
- पुडुचेरी अब पुथुचेरी

इस कदम की आलोचना –

- नाम बदलने से पहले लोगों के साथ विचार–विमर्श नहीं किया गया।
- नामों को सभी जगह बदलने के लिए सभी जगह नए बोर्डों के पेंटिंग के अनुबंधों पर ध्यान नही दिया गया।
- कोविड–19 से लड़ने में सरकार द्वारा हुई खामियों को छुपाने के लिए एवं लोगों का ध्यान दुसरी ओर लगाने के लिए सरकार जानबुझ कर इसे अभी ले कर आई है।
- कुछ नए वर्तनी ने लोगों से उनकी तमिल ध्वन्यात्मकता से मेल न खाने के लिए आलोचना की है। मंत्री ने कहा कि इस तरह के नामों मे, वेल्लोर, जो बन विल्लुर बन गया है को सुधार करके वेल्लुर किए जाने की आवश्यकता है।
- हालाँकि राज्य का अंग्रेजी नाम – तमिलनाडु – बरकरार है, राज्य की राजधानी के नाम पर 1996 में मद्रास से बदल कर चेन्नई कर दिया गया था।

अर्थव्यवस्था

आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन

समाचार –

- कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है। अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज एवं आलू जैसी आवश्यक वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर रखा गया है।
- इससे निजी निवेशकों के अपने व्यावसायिक कार्यों में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप की आशंकाएं दूर हो जाएंगी।
- उत्पादन, धारण, चाल, वितरण एवं आपूर्ति की स्वतंत्रता से पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का दोहन होगा एवं निजी क्षेत्र / कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होगा।
- यह कोल्ड स्टोरेज में निवेश एवं खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में मदद करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की गई

समाचार –

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 48,000 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित तीन योजनाओं को शुरू किया गया है।

  1. उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव (लगभग 41,000 करोड़ रूपये का परिव्यय) – पीएलआई के तहत, जिसे मोबाइल फोन निर्माण एवं निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर लक्षित किया जाता है, सरकार ने शुरू में 10 फर्मों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है – पांच वैश्विक एवं पांच स्थानीय। पीएलआई योजना भारत में निर्मित सामानों की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष) पर 4% से 6% तक की प्रोत्साहन राशि एवं आधार वर्ष के बाद पांच साल की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को लक्षित क्षेत्रों के तहत कवर करेगी।

  2. कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (लगभग 3,300 करोड रूपये) – विशेष वस्तु इलेक्ट्रॉनिक सामानों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, अर्धचालक/प्रदर्शन निर्माण इकाइयों, असेंबली, टेस्ट, मार्किंग एवं पैकेजिंग (एटीएमपी) की पहचान सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% की वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।) इकाइयों, विशेष उप–विधानसभाओं एवं पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण के लिए पूर्वोक्त सामान।

  3. संशोधित इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्लस्टर (लगभग 3,800 करोड़ रूपये) – EMC 2.0 आम सुविधाओं एवं साथ–साथ विश्व स्तर के बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करेगा, जिसमें रेडी बिल्ट फैक्ट्री (RBF) शेड/प्लग एंड प्ले सुविधाएं, उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ रहेंगी जो प्रमुख वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित करने में मदद करेगा।

महत्व –

- योजनाएं एक मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने में मदद करेंगी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक संपत्ति होगी एवं मूल्य श्रृंखला में एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने एवं इसे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने में मदद करेगी।
- योजनाएं घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की विकलांगता को दूर करने में मदद करेंगी एवं इस प्रकार देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेंगी।
- सभी योजनाएं घटकों की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला एवं अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे एवं बड़ी लंगर इकाइयों एवं उनके आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के लिए सामान्य सुविधाओं को सक्षम करेंगी।

- इन योजनाओं में 2025 तक US $ 1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं US $ 5 ट्रिलियन सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा।
- तीन नई योजनाओं से पर्याप्त निवेश, मोबाइल फोन के उत्पादन में वृद्धि एवं उनके पुर्जों/घटकों से 2025 तक लगभग 10,00,000 करोड रुपये एवं लगभग 5 लाख प्रत्यक्ष एवं 15 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने की उम्मीद है।
- **रोजगार सृजन** – तीन नई योजनाओं के साथ, सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में लगभग 10 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन करते हुए 8 लाख करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करना है।

वन नेशन–वन राशन कार्ड योजना

समाचार –
- वन नेशन वन कार्ड योजना में तीन और राज्य यानी ओडिशा, सिक्किम एवं मिजोरम शामिल हुए हैं। अब तक यह सुविधा 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सक्षम है।
- वन नेशन वन राशन कार्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लाभार्थी विशेष रूप से प्रवासी अपनी पसंद के किसी भी पीडीएस दुकान से पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उपयोग कर सकते हैं।
- कोई गरीब व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित नहीं होता है जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं।
- इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों से लाभ उठाने के लिए एक से अधिक राशन कार्ड रखने वाले किसी भी व्यक्ति की संभावना को दूर करना है।
- इससे लाभार्थियों को स्वतंत्रता मिलेगी क्योंकि वे किसी एक पीडीएस दुकान से बंधे नहीं होंगे एवं दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे।

एमएसपी सूची में शामिल 23 अतिरिक्त एमएफपी आइटम

समाचार –
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सूची में 23 अतिरिक्त लघु वन उपज (एमएफपी) वस्तुओं को शामिल किया गया है।
- उनमें वन तुलसी के बीज, वन जीरा, मशरूम, काले चावल एवं जोहर चावल शामिल हैं।
- इससे वस्तुओं का कवरेज 50 से बढ़कर 73 हो जाता है। यह कोविड–19 महामारी के मद्देनजर किया गया है ताकि आदिवासी एमएफपी इकट्ठा करने वालों को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

योजना का विवरण –
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2013 में, गैर–राष्ट्रीयकृत/गैर–एकाधिकार वाले लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से एमएफपी के लिए एक मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी।
- यह एमएफपी इकट्ठा करने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक उपाय है, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्य हैं, जिनमें से अधिकांश वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों में हैं।

योजना के उद्देश्य –
- यह सुनिश्चित करती हैं कि आदिवासी आबादी को जंगल से इकट्ठा होने वाली उपज के लिए एक पारिश्रमिक मूल्य मिले एवं उन्हें रोजगार के वैकल्पिक रास्ते मुहैया कराए जाए।
- संसाधन आधार की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संग्रह, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन आदि में वनवासियों के प्रयासों के लिए उचित मौद्रिक वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें।
- घटाए गए लागत के साथ बिक्री आय से उन्हें राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त करें।

कार्यान्वयन –
- एमएसपी पर एमएफपी खरीदने की जिम्मेदारी राज्य नामित एजेंसियों के पास होगी।
- बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए, बाजार संवाददाताओं की सेवाओं को नामित एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से एमएफपी व्यापार के प्रमुख बाजारों द्वारा लाभ उठाया जाएगा।
- यह योजना प्राथमिक मूल्यवर्धन के साथ–साथ कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस आदि जैसे आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का भी समर्थन करती है।
- योजना के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण मंत्रालय द्वारा तकनीकी सहायता से किया जाएगा।

टॉप टू टोटल

समाचार –
- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने सभी पेरिशबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स (टॉप से लेकर टोटल) के लिए TOP (टोमेटो–ओनियन–आलू) फसलों से ऑपरेशन ग्रीन्स के विस्तार की घोषणा की।
- ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा बजट 2018–2019 में टमाटर, प्याज एवं आलू (TOP) फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने के लिए की गई थी। इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह योजना अब टमाटर, प्याज एवं आलू (TOP) फसलों से लेकर अन्य सभी पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स (TOP से लेकर टोटल) तक बढ़ा दी गई है।
- इसका उद्देश्य फल एवं सब्जियों के उत्पादकों को लॉकडाउन के कारण संकट की बिक्री से बचाना है एवं इसके बाद के घाटे को कम करना है।
- पात्र संस्थाएँ – खाद्य प्रोसेसर, सहकारी समितियाँ, व्यक्तिगत किसान, निर्यातक, राज्य विपणन / सहकारी संघ फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण / विपणन में लगे हुए हैं।
- मंत्रालय निम्नलिखित दो घटकों की लागत का 50% लागत मानदंड के अधीन प्रदान करेगा
  1. पात्र फसलों के अधिशेष उत्पादन को क्लस्टर से उपभोग केंद्र तक यातायात एवं
  2. पात्र फसलों के लिए भंडारण क्षमता की सुविधा (अधिकतम 3 माह की अवधि के लिए)।

पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना

समाचार –
- हाल ही में 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय' ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के एक भाग के रूप में 'पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज' योजना की शुरुआत की।

- योजना के तहत कुल 35,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। जिससे 9 लाख कुशल एवं अर्द्ध–कुशल रोजगारों के सृजित होने की संभावना है।
- असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की लगभग 25 लाख इकाइयों में लगभग 74% खाद्य प्रसंस्करण श्रमिक कार्यरत हैं। जिसमें से दोतिहाई ग्रामीण क्षेत्रों में हैं एवं 80% परिवार आधारित व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की और पलायन को रोकते हैं।

योजना का विवरण–

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा।
- परिव्यय को निम्नलिखित तरीके से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा साझा किया जाएगा –
  1. केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में।
  2. पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में।
  3. विधानमंडल युक्त केंद्र शासित प्रदेशों में 60:40 के अनुपात में।
  4. अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में 100% व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

- मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, जो अपनी इकाइयों के उन्नयन की इच्छुक हैं, वे पात्र इकाइयाँ परियोजना लागत का 35% तक ऋण–आधारित पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रति इकाई है।
- कृषक उत्पादक संगठनों (थ्च्चे)ध्स्वयं सहायता समूहों (SHGs)/सहकारी समितियों या राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों या निजी उद्यमों को सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम सहित बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये 35% की दर से क्रेडिट–लिंक्ड अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
- सीड कैपिटल (आरंभिक वित्त पोषण) के रूप में प्रति स्वयं सहायता समूह सदस्य को कार्यशील पूंजी एवं छोटे उपकरण खरीदने के लिये 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

'एक जिला एक उत्पाद' (One District One Product - ODDP) दृष्टिकोण –

- निवेश प्रबंधन, आम सेवाओं का लाभ उठाने एवं उत्पादों के विपणन को बढ़ाने के लिये योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद के दृष्टिकोण को अपनाया गया है।
- राज्यों द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक जिले के लिये एक खाद्य उत्पाद की पहचान की जाएगी।
- व्क्व में जल्दी खराब होने वाला उत्पाद या अनाज आधारित उत्पाद हो सकता है जिसका जिले एवं उनके संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जाता है।
- ऐसे उत्पादों की सूची में आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, कीनू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, मत्स्यन, मुर्गी पालन आदि शामिल हैं।

सतत गेल्वेनाईज्ड रेबार उत्पादन सुविधा

समाचार –

- केंद्रीय इस्पात मंत्री ने पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में सतत गेल्वेनाईज्ड रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया। इससे निर्माण उद्योग को गेल्वेनाईज्ड रेबार की आपूर्ति की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता पूर्ण होगी।

इस्पात क्षेत्र के वैश्विक परिदृश्य का संक्षिप्त विवरण –

- CY 2019 में, विश्व कच्चे इस्पात का उत्पादन 1870 मिलियन टन तक पहुंच गया एवं CY 2018 पर 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई।
- चीन उसी अवधि में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बना रहा (996 मिलियन टन) भारत के बाद (111mt), जापान (99 mt) एवं संयुक्त राज्य अमेरिका (88 mt)।

घरेलू परिदृश्य –

- भारतीय इस्पात उद्योग ने नए विकास के चरण में प्रवेश किया है, बाद के विनियमन, पुनरुत्थान अर्थव्यवस्था पर उच्च सवारी एवं स्टील की बढ़ती मांग।
- उत्पादन में तेज वृद्धि से भारत 2017 के अपने 3 रे स्थान से 2018 एवं 2019 में कच्चे स्टील के उत्पादन में दुसरे स्थान आ गया है। देश विश्व में स्पंज आयरन या डीआरआई का सबसे बड़ा उत्पादक भी है एवं 2019 में चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टील उपभोक्ता है।
- भारत की तरह एक विनियमित, उदारीकृत आर्थिक/बाजार परिदृश्य में, सरकार की भूमिका एक सूत्रधार की है जो नीति दिशानिर्देशों का पालन करता है एवं संस्थागत तंत्र स्थापित/इस्पात क्षेत्र की दक्षता एवं प्रदर्शन में सुधार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए संरचना करता है।
- इस भूमिका में, सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 जारी की, जिसने 2030–31 तक मांग एवं आपूर्ति दोनों पक्षों पर भारतीय इस्पात उद्योग के लिए दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया है। सरकार ने सरकारी खरीद में लौह निर्मित इस्पात एवं इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए एक नीति की घोषणा की है।

उत्पादन –

- इस्पात उद्योग क्रमशः 1991 एवं 1992 में डी–लाइसेंस एवं डी–नियंत्रित था।
- 2019 में भारत विश्व का कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था।

गेल्वेनाईज्ड इस्पात –

- यह अपने विस्तारित स्थायित्व के कारण सबसे लोकप्रिय इस्पात प्रकारों में से है, जिसमें इस्पात की मजबूती एवं संरचना के साथ–साथ जस्ता–लोहे के कोटिंग की संक्षारण सुरक्षा है। जस्ता संक्षारक तत्वों के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करके आधार धातु की रक्षा करता है, एवं कोटिंग की बलि प्रकृति लंबे समय तक चलने एवं उच्च गुणवत्ता वाले स्टील उत्पाद का परिणाम देती है।
- यह बहुमुखी प्रतिभा इसे विभिन्न परियोजनाओं एवं उद्योगों पर लागू करती है, जिसमें कृषि, सौर, मोटर वाहन, निर्माण, आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC)

समाचार –

- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) की 49 वीं शासी परिषद की बैठक, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त निकाय, जून 27, 2020 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
- इस दिन बंकिम चंद्र चटर्जी की 182 वीं जयंती के साथ–साथ एमएसएमई उद्यम दिवस भी मनाया गया।

एनपीसी के बारे में एनपीसी

- भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।
- 1958 में भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित।
- यह एक स्वायत्त, बहुपक्षीय, गैर–लाभकारी संगठन है जिसमें तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों एवं अन्य हितों के अलावा नियोक्ताओं एवं श्रमिक संगठनों एवं सरकार के समान प्रतिनिधित्व है।
- एनपीसी टोक्यो स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ) का एक घटक है, जो एक अंतर सरकारी निकाय है, जिसका भारत सरकार एक संस्थापक सदस्य है।
- एनपीसी अपने ग्राहकों के साथ मिलकर उत्पादकता बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, लाभ बढ़ाने, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने एवं बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। यह निर्णय लेने, बेहतर प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं, कार्य संस्कृति एवं साथ ही आंतरिक एवं बाहरी दोनों के लिए ग्राहकों की संतुष्टि के लिए विश्वसनीय डेटाबेस प्रदान करता है।

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020

समाचार –

- बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया है।
- अध्यादेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को संशोधित करता है जो सहकारी बैंकों पर लागू होता है।
- यह अधिनियम की धारा 45 में संशोधन भी करता है, ताकि जनता, जमाकर्ताओं एवं बैंकिंग प्रणाली के हितों की रक्षा के लिए एवं अपने उचित प्रबंधन को सुरक्षित रखने के लिए, यहां तक कि अधिस्थगन के आदेश के बिना भी किसी बैंकिंग कंपनी के पुनर्निर्माण या समामेलन की एक योजना बनाई जा सके एवं वित्तीय प्रणाली के व्यवधान से बचा जा सके।

विवरण –

- यह सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने का प्रयास करता है ताकि सहकारी बैंकों के साथ–साथ अन्य बैंकों के संबंध में आरबीआई के पास पहले से उपलब्ध शक्तियों का विस्तार हो सके एवं साथ ही साथ ध्वनि बैंकिंग विनियमन के लिए, एवं व्यावसायिकता सुनिश्चित करने एवं पूंजी तक उनकी पहुंच को सक्षम बनाया जा सके।
- संशोधन राज्य सहकारी समितियों की मौजूदा शक्तियों को प्रभावित नहीं करते हैं।
- संशोधन प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) या सहकारी समितियों पर लागू नहीं होते हैं (जिनका प्राथमिक उद्देश्य एवं प्रमुख व्यवसाय कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त है, एवं जो 'बैंक' या 'बैंकर' या 'शब्द' का उपयोग नहीं करते हैं चेक जारी नही करते है।)

प्रधानमंत्री स्वानीधि योजना

समाचार –

- हाल ही में 'केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय' द्वारा छोटे दुकानदारों एवं फेरीवालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु –

- इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकेंगे।
- ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलैट्रल की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिये एक वर्ष का समय दिया जाएगा, विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किश्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे।
- साथ ही इस योजना के तहत यदि लाभार्थी लिये गए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले ही करते हैं तो उन्हें 7% (वार्षिक) की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (Direct Benefit Transfer - DBT) के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- पीएम स्वनिधि के तहत निर्धारित तिथि से पहले ऋण के पूर्ण भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लागू होगा।

स्विस बैंकों में जमा भारतीय पैसो में 5.8% की गिरावट

समाचार –

- स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक (स्विस नेशनल बैंक – SNB) से नवीनतम डेटा जारी हुआ है।
- इस डेटा के अनुसार भारत 2019 के अंत में स्विस बैंकों के साथ अपने नागरिकों और उद्यमों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में तीन स्थान नीचे 77 वें रैंक (पिछले वर्ष में 74 वें स्थान) पर आ गया है।
- भारत में स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और उद्यमों द्वारा जमा पैसे की बात आती है, जिसमें भारत स्थित शाखाएँ भी शामिल हैं।
- यह स्विट्जरलैंड स्थित बैंकों के सभी विदेशी ग्राहकों द्वारा जमा किए गए कुल धन का लगभग 0.06% है।
- तुलनात्मक रूप से, शीर्ष स्थान पर स्थित ब्रिटेन के पास 2019 के अंत में स्विस बैंकों के साथ लगाए गए कुल विदेशी कोषों में से 27 प्रतिशत के करीब है।
- भारत स्थित शाखाओं सहित स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और उद्यमों द्वारा लगाए गए फंड 2019 में 5.8 प्रतिशत गिरकर 899 मिलियन स्विस फ्रैंक (6,625 करोड़ रुपये) हो गए।
- शीर्ष रैंक वाले देशों में, यूके, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, फ्रांस और हांगकांग के बाद शीर्ष पांच में है।
- शीर्ष पांच देशों में अकेले स्विस बैंकों में कुल विदेशी धन का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, जबकि शीर्ष–10 का खाता लगभग दो–तिहाई है।
- शीर्ष–15 देशों के स्विस बैंकों में सभी विदेशी धन का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि शीर्ष –30 का योगदान लगभग 90 प्रतिशत है।
- शीर्ष–10 देशों में जर्मनी, लक्जमबर्ग, बहामास, सिंगापुर और केमैन द्वीप भी शामिल हैं।

स्किल बिल्ड रिईग्नाईट

समाचार –

- आईबीएम के साथ साझेदारी में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने अधिक नौकरी चाहने वालों तक पहुंचने एवं भारत में व्यापार मालिकों को नए संसाधन प्रदान करने के लिए फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म 'कौशल बिल्ड रिग्नाइट' का अनावरण किया है।

विवरण –

- स्किल बिल्ड रिइग्नाइट के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्सवर्क तक पहुंच प्रदान करने एवं नौकरी चाहने वालों एवं उद्यमियों को अपने करियर एवं व्यवसायों को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए समर्थन की सलाह देता है।
- यह प्रशिक्षण संस्थानों एवं बुनियादी ढांचे के अपने नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्र के युवाओं के लिए एक दीर्घकालिक संस्थागत प्रशिक्षण है।

- आईबीएम राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) एवं ITI में छात्रों एवं प्रशिक्षकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं क्लाउड कम्प्यूटिंग के क्षेत्र में बहुमुखी डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देगा।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

विशेषताएं –

- उद्यमियों के लिए व्यक्तिगत कोचिंग, अपने छोटे व्यवसायों को स्थापित करने या फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए सलाह लेना क्योंकि वे कोविड 19 महामारी से बाहर निकलने के लिए वसूली पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं।
- वित्तीय प्रबंधन, व्यवसाय रणनीति, डिजिटल रणनीति, कानूनी सहायता एवं छोटे व्यवसाय के मालिकों के लिए अधिक जैसे पाठ्यक्रम।

शिशु ऋण

समाचार –

- केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायों एवं कुटीर उद्योगों के लिए 'मुद्रा शिशु ऋण' की घोषणा की है ताकि कोविड–19 महामारी के कारण दुकानदारों को नुकसान न हो।
- 1500 करोड़ के ब्याज सबवेंशन की घोषणा की गई है।
- 12 महीने की अवधि के लिए 2% ब्याज दर उपशमन सरकार द्वारा की पेशकश की जाएगी।
- यह मुद्रा शिशु ऋण के तहत 50,000 रूपये तक के छोटे उधारकर्ताओं को लाभान्वित करेगा।

विवरण–

- गैर–कॉर्पोरेट, गैर–कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय पीएम द्वारा 2015 में पीएमएमवाई लॉन्च किया गया था।
- उधार देने वाले संस्थान – वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, एमएफआई एवं एनबीएफसी।
- MUDRA ने लघु युनिट की आवश्यकताओं को देखते हुए तीन उत्पाद बनाए हैं –
  1. शिशु – 50,000 रूपये तक का उधार।
  2. किशोर – 50,000 रुपये से 5 लाख रूपये तक के ऊपर के ऋण।
  3. तरुण– 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के ऋण।
- **उद्यमी मित्र पोर्टल** – यह लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा MSMEs को क्रेडिट एवं हैंडहोल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए शुरू किया गया था।
- **उद्यम सखी** – महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम लागत वाले उत्पादों एवं सेवाओं के लिए घूमने वाले व्यवसाय मॉडल बनाकर महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय की एक पहल है।

कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया।
- यह महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

विवरण –

- यह कदम घरेलू / अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एवं क्षेत्रों के आर्थिक विकास का बढ़ाने का परिणाम देगा। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान होगा।
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार वहां कोई हवाई अड्डा नहीं था। 3 किमी लंबी रनवे स्ट्रिप पहले ही बन चुकी है। अब, एयरबस का एक बड़ा विमान भी हवाई अड्डे पर उतर सकता है।
- कुशीनगर उत्तर–पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लगभग 50 किमी पूर्व में स्थित है एवं यह महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है।
- कई अन्य बौद्ध स्थल कुशीनगर के पास मौजूद हैं जैसे श्रावस्ती (238 किमी), कपिलवस्तु (190 किमी) एवं लुम्बिनी (195 किमी)।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)

समाचार –

- हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुसरण में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 15000 करोड़ रुपये के पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) की स्थापना को मंजूरी दी है।

विवरण –

- एएचआईडीएफ से डेयरी एवं मांस प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे एवं निजी क्षेत्र में पशु चारा संयंत्र की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश की बहुत आवश्यक प्रोत्साहन की सुविधा होगी।
- पात्र लाभार्थी किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), एमएसएमई, धारा 8 कंपनियां, निजी कंपनियां एवं व्यक्तिगत उद्यमी होंगे जिनके न्यूनतम 10% मार्जिन मनी योगदान होगा शेष 90% अनुसूचित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला ऋण घटक होगा।
- भारत सरकार पात्र लाभार्थियों को 3% ब्याज उपदान देगी। प्रमुख ऋण राशि के लिए 2 वर्ष की मोहलत अवधि एवं उसके बाद 6 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि होगी।
- सरकार रुपये की क्रेडिट गारंटी फंड भी स्थापित करेगी। नाबार्ड द्वारा 750 करोड़ का प्रबंधन किया जाना है। क्रेडिट गारंटी उन स्वीकृत परियोजनाओं को दी जाएगी जो एमएसएमई परिभाषित छत के तहत आते हैं। गारंटी कवरेज उधारकर्ता की क्रेडिट सुविधा का 25% तक होगा।

महत्व –

- यह है कि इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक अग्रिम निवेश को पूरा करने के लिए पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी एवं निवेशकों के लिए समग्र रिटर्न / भुगतान वापस बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
- पात्र लाभार्थियों द्वारा प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे में इस तरह के निवेश भी इन संसाधित एवं मूल्य वर्धित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देंगे।
- चूंकि, भारत में डेयरी उत्पादन के अंतिम मूल्य का लगभग 50–60% किसानों को वापस मिल जाता है, इसलिए, इस क्षेत्र में विकास का किसान की आय पर महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।
- दुग्ध बिक्री से डेयरी बाजार एवं किसानों की प्राप्ति का आकार संगठित एवं सहकारी समितियों द्वारा आयोजित बंद विकास के साथ जुड़ा हुआ है।
- एएचआईडीएफ में निवेश प्रोत्साहन न केवल 7 गुना निजी निवेश का लाभ उठाएगा, बल्कि किसानों को इनपुट पर अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे उच्च उत्पादकता पैदा होगी जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

- एएचआईडीएफ के माध्यम से अनुमोदित उपायों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आजीविका निर्माण में 35 लाख की मदद मिलेगी।

'उद्भव देश का नाम' GeM प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए

समाचार –

- स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने नए उत्पादों का पंजीकरण करते समय सरकारी ई–मार्केटप्लेस (GeM) पर सभी विक्रेताओं के लिए मूल देश को सूचीबद्ध करना अनिवार्य कर दिया है।
- जीईएम में बदलाव केंद्र के आत्मानिर्भर भारत एवं मेक इन इंडिया नीतियों के अनुरूप हैं।
- इस प्लेटफॉर्म पर खरीदार अब विभिन्न उत्पादों में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत देख सकते हैं।
- वे विभिन्न उत्पादों को देखने के लिए एक नए मेक इन इंडिया फिल्टर पर भी स्विच कर सकते हैं जो खरीदारों की तरह स्थानीय सामग्री पर उनकी प्राथमिकताओं से मेल खाते हैं, केवल उन उत्पादों को खरीदना चुन सकते हैं जो न्यूनतम 50% स्थानीय सामग्री मानदंडों को पूरा करते हैं।

सरकारी ई–मार्केटप्लेस (GeM) –

- विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों / संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए एक स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है।
- इसे 2016 में लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं दक्षता लाना है।
- यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है जिसने प्रौद्योगिकी को बोनाफाइड विक्रेताओं के लिए प्रवेश बाधाओं को दूर करने के लिए उपयोग किया है एवं कई प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के साथ एक जीवंत ई–मार्केटप्लेस बनाया है।
- यह सरकारी उपयोगकर्ताओं को अपने पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ई–बोली एवं रिवर्स ई–नीलामी के उपकरण भी देता है।
- वर्तमान में, GeM के पास 15 लाख से अधिक उत्पाद, लगभग 20,000 सेवाएं एवं 40,000 से अधिक सरकारी खरीदार संगठन हैं।

भारत में डीकार्बोनिजिंग ट्रांसपोर्ट

समाचार –

- अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (ITF) के सहयोग से NITI Aayog ने भारत के लिए एक निम्न–कार्बन परिवहन प्रणाली की दिशा में एक मार्ग विकसित करने के इरादे से 'भारत में डीकार्बोनिजिंग ट्रांसपोर्ट' परियोजना शुरू की।
- भारत 2008 से परिवहन नीति के लिए एक अंतर–सरकारी संगठन ITF का सदस्य रहा है।
- इस ऑनलाइन कार्यक्रम ने भारत में परिवहन एवं जलवायु हितधारकों को नियोजित परियोजना गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

परियोजना का विवरण –

- यह देश के लिए एक परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन रूपरेखा तैयार करेगा।
- यह देश में परिवहन चुनौतियों एवं कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2 संबंध में इनपुट देने का अवसर प्रदान करके) में कमी करेगा एवं भारत में परियोजना से संबंधित गतिविधियों के बारे में परिवहन एवं जलवायु हितधारकों को सूचित करेगा।
- भारत के अलावा पहल में वर्तमान प्रतिभागी अर्जेंटीना, अजरबैजान एवं मोरक्को हैं।
- DTEE आईटीएफ एवं वुप्पर्टल इंस्टीट्यूट के बीच एक सहयोग है, जो कि जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर द एनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी के इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव (IKI) द्वारा समर्थित है।

गरीब कल्याण रोजगार अभियान

समाचार –

- भारतीय पीएम ने बड़े पैमाने पर रोजगार का शुभारंभ किया–ग्रामीण सार्वजनिक कार्य अभियान जिसका नाम गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, जो कि भारी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों / गांवों में सशक्तिकरण एवं आजीविका के अवसर प्रदान करता है।
- कोविड–19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक भेद को बनाए रखते हुए ग्रामीण कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) एवं कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
- यह अभियान 125 दिनों का है।
- अभियान के लिए छह राज्यों, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एवं ओडिशा के 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के साथ कुल 116 जिलों को चुना गया है जिसमें 27 एस्पिरेशनल जिले शामिल हैं।
- इन जिलों में प्रवासी श्रमिकों के लगभग 2/3 को कवर करने का अनुमान है।
- अभियन 12 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, अर्थात् ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार एवं कृषि के बीच एक समन्वित प्रयास होगा।
- इसमें एक ओर प्रवासी कामगारों को रोजगार देने एवं दूसरी ओर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों का गहन एवं केंद्रित कार्यान्वयन शामिल होगा।

विश्व निवेश रिपोर्ट 2020

समाचार –

- यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (UNCTAD) ने अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड इनवेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 में कहा कि भारत को 2019 में विदेशी निवेश में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिले।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं –

- भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मामले में दुनिया का नौवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था।
- विकासशील एशिया क्षेत्र में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए शीर्ष पांच मेजबान अर्थव्यवस्थाओं के बीच था।
- भारत में सबसे बड़ा दक्षिण एशियाई प्राप्तकर्ता FDI, 2019 में 20 प्रतिशत बढ़कर 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- अधिकांश निवेश सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एवं निर्माण उद्योग में थे।
- भारत में बाद में कोविड–19 महामारी एवं भारत के बड़े बाजार में एक कम लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि देश को बाजार में निवेश आकर्षित करने के लिए जारी रहेगी।

- 2005 के बाद यह पहली बार होगा कि वैश्विक एफडीआई 1 ट्रिलियन डॉलर से कम है।
- 2020 में, एशिया में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कोरोनवायरस वायरस की महामारी के कारण आर्थिक रूप से कमजोर रहने एवं 45 प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान है।
- दक्षिण एशिया में, FDI में भी तेजी से कमी होने की उम्मीद है।

UNCTAD -
- स्थायी अंतर सरकारी निकाय।
- 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित।
- यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है।
- यह संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है, लेकिन इसकी अपनी सदस्यता, नेतृत्व एवं बजट है।
- यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का एक हिस्सा भी है।

UNCTAD द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्टें –
1. ट्रेड एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट
2. टेक्नॉलोजी एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट
3. डिजीटल इकॉनोमी रिपोर्ट

ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे

समाचार –
- दिल्ली–अमृतसर एक्सप्रेसवे के हिस्से के रूप में सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खड़ेर साहिब के माध्यम से नकोदर से अमृतसर सिटी के लिए एक नए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी का विकास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है।
- इसके तहत अमृतसर से गुरदासपुर तक की सड़क को भी पूरी तरह से विकसित कर पूरी तरह से सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। इसके साथ, अमृतसर के माध्यम से या तो नकोदर से गुरदासपुर की यात्रा करने का विकल्प होगा।
- इस ग्रीनफील्ड संरेखण से अमृतसर शहर के अलावा अन्य धार्मिक स्थलों जैसे कि सुल्तानपुर लोधी, गोविंद साहिब, खदेर साहिब के साथ ही पंजाब में हाल ही में विकसित डेरा बाबा नानक/करतारपुर साहिब इंटरनेशनल कॉरिडोर को भी सबसे छोटा एवं वैकल्पिक एक्सप्रेस कनेक्टिविटी मिलेगी।
- एक बार परियोजना पूरी हो जाने के बाद, अमृतसर से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक यात्रा का समय लगभग चार घंटे कम हो जाएगा।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत अमृतसर परियाजना के तहत दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का विकास किया है।

दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC)

समाचार –
- भारत सरकार ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था।
- इसके तहत, महामारी कोविड–19 के कारण आईबीसी के तहत कंपनियों के खिलाफ नए इंसॉल्वेंसी की कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
- 25 मार्च, जिस दिन कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन शुरू किया गया था उसके, छह महीने की अवधि (जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।) में दिवाला कार्यवाही शुरू करने पर विचार नहीं किया जाएगा।
- यह 6 महीने की अवधि के लिए IBC के अनुभाग 7, 9 एवं 10 को निलंबित करता है, जबकि एक सक्षम प्रावधान इसके लिए 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- आईबीसी में इस आशय के बदलावों की घोषणा सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान सुधारों के तहत की थी।
- सरकार के अनुसार, यह विचार 'उन कॉर्पोरेट व्यक्तियों की मदद के लिए है जो अभूतपूर्व स्थिति के कारण संकट का सामना कर रहे हैं, कुछ समय के लिए उक्त संहिता के तहत इनसॉल्वेंसी कार्यवाही में धकेल ना दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए, संशोधन उन वास्तविक तनाव का सामना कर रहे उन लोगो दिवालियापन अदालतों में घसीटे जाने से सुरक्षा करेंगे जिनके कारण उनके नियंत्रण से परे थे।
- पिछले–डिफॉल्टरों (25 मार्च, 2020 से पहले) के खिलाफ IBC की कार्यवाही भी जारी नहीं रह सकती है। लेकिन एक स्थायी आधार पर इस निर्दिष्ट अवधि के दौरान डिफॉल्ट के लिए दिवालियापन की कार्यवाही से सुरक्षा के कुछ अनपेक्षित परिणाम हैं जिनके बारे में विचार किया जाना चाहिए।

विश्व प्रत्यायन दिवस (WAD) 2020

समाचार –
- WAD हर साल 9 जून को मनाया जाता था।
- इस दिवस का उद्देश्य व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को बढ़ावा देना है।
- WAD 2020 की थीम 'प्रत्यायन' खाद्य सुरक्षा में सुधार' है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम (IAF) एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (ILAC) द्वारा तय किया गया है।
- प्रमाणन निकायों (NABCB) के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एवं नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL), क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) के दो मान्यता बोर्ड, ने एक वेबिनार का आयोजन किया।
- ऐसा करने में, मान्यता संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेष रूप से अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण (एसडीजी 3) का समर्थन करती है।
- गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए प्रत्यायन एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन अंतिम लक्ष्य खाद्य क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में उत्पाद एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।

भारत का पहला गैस एक्सचेंज

समाचार –
- हाल ही में 'पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय' द्वारा एक ई–समारोह के माध्यम से भारत के प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण–आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, 'इंडियन गैस एक्सचेंज' का शुभारंभ किया गया है।

प्रमुख बिंदु –
- 'इंडियन गैस एक्सचेंज' प्राकृतिक गैस के लिये एक वितरण–आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा।
- यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों को निर्बाध ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने के लिये पूरी तरह से वेब–आधारित इंटरफेस पर आधारित है।

- इंडियन गैस एक्सचेंज, ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 'इंडियन एनर्जी एक्सचेंज' (Indian Energy Exchange - IEX) की सहायक/अनुषंगी कंपनी के रूप में कार्य करेगा।
- इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राकृतिक गैस का व्यापार रुपये में किया जायेगा जिसमे न्यूनतम आवंटन का आकार 100 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (MBTU) जो कि ऊष्मा की इकाई है, के द्वारा निर्धारित किया गया है।
- 'इंडियन गैस एक्सचेंज' बाजार सहभागियों को मानकीकृत गैस अनुबंधों में व्यापार करने में समर्थ बनाएगा।
- यह एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में क्रेता–विक्रेता प्राधिकृत केंद्रों के माध्यम से स्पॉट मार्केट (Spot Market) एवं वायदा अनुबंध (Forward Market) में आयातित प्राकृतिक गैस का कारोबार कर सकेंगे।
- इसके लिये तीन केंद्रों (गुजरात के दाहेज, हजीरा एवं आंध्र प्रदेश का ओडुरु–काकीनाड़ा) का चयन किया गया है।
- बिना किसी खरीददार की खोज के इस डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयातित 'तरलीकृत प्राकृतिक गैस' (LNG) को बेचा जायेगा अर्थात् खरीदारों को उचित मूल्य पाने के लिये अब कई डीलरों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 'इंडियन गैस एक्सचेंज' में अगले दिन एवं एक महीने तक की डिलीवरी के लिये अनुबंध की अनुमति है जबकि आमतौर पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिये अनुबंध छह महीने से एक वर्ष तक होता है।
- ज्ञातव्य है कि देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है जिसे 'इंडियन गैस एक्सचेंज' पर नहीं बेचा जाएगा।
- इसके माध्यम से सिर्फ बाहर से आयातित अर्थात अन्य देशों से आयातित प्राकृतिक गैस की ही खरीदी एवं बिक्री की जाएगी।

तुरंत कस्टम्स

समाचार –

- बेंगलुरु एवं चेन्नई में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क (CBIC, वित्त विभाग के तहत राजस्व विभाग की सहायक कंपनी) द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम, 'तुरंत कस्टम्स' लॉन्च किया गया है।
- बेंगलुरू एवं चेन्नई में तुरंत कस्टम्स की शुरुआत अखिल भारतीय रोल आउट का पहला चरण होगा जो 31 दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा एवं पहले चरण में बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी का आयात होगा।

विवरण –

- इस कार्यक्रम में, आयातकों को अब आयात के बंदरगाह के बाहर स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दूरस्थ रूप से किए गए एक फेसलेस मूल्यांकन के बाद सीमा शुल्क से अपना माल प्राप्त हो सकता है।
- दूसरे शब्दों में, चेन्नई में आयात किए गए सामान का मूल्यांकन बेंगलुरु में स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है एवं साथ ही, सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली द्वारा सौंपा जा सकता है।

महत्व –

- ये सीमा शुल्क सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ नियमित इंटरफेस को समाप्त करके एवं पूरे देश में मूल्यांकन में एकरूपता प्रदान करके आयातकों को लाभ प्रदान करेगा।
- इससे लेनदेन की लागत में कमी आएगी एवं अनुकूल आकलन के लिए पोर्ट खरीदारी की प्रथा को समाप्त किया जा सकेगा।
- यह व्यापार करने में आसानी के लिए एक मेगा सुधार है।
- यह आयातित वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए एक विशाल छलांग है।

स्वास्थ्य एवं ऊर्जा कुशल भवनों से संबंधित पहल

समाचार –

- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL), अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स (USAID), MAITREE (एनर्जी एफिशिएंसी के लिए मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम) प्रोग्राम के साथ कार्यस्थलों को स्वस्थ एवं हरा–भरा बनाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'स्वस्थ एवं ऊर्जा कुशल भवन' पहल की शुरुआत की।

विवरण –

- यह प्रयास इमारतों के भीतर एक मानक अभ्यास के रूप में मूल्य– प्रभावी ऊर्जा दक्षता की गोद लेने के वृद्धि के लिए लक्षित है।
- विशेष रूप से ठंडक एवं ईईएसएल पर केंद्रित इन प्रयासों पर सबसे पहले इन कार्यालयों (भारत के शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों – एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड एवं पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से चलाई जा रही है) में इसकी शुरूआत की है।
- यह पहल मौजूदा इमारतों एवं एयर कंडीशनिंग सिस्टम को रेट्रोफिट करने की चुनौतियों को संबोधित कर रही है ताकि वे स्वस्थ एवं ऊर्जा–कुशल दोनों हों।
- यह परियोजना देश भर में अन्य इमारतों में भविष्य के उपयोग के लिए विशिष्टताओं को विकसित करने के साथ–साथ विभिन्न प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता एवं लागत लाभों का मूल्यांकन करने में सहायता एवं वायु गुणवत्ता, आराम, एवं ऊर्जा पर उनके अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रभावों का समाधान करेगी। उपयोग।

भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक

समाचार –

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पूरे देश में डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपये का भुगतान अवसंरचना विकास निधि (PIDF) स्थापित कर रहा है।

विवरण –

- 2019 में, आरबीआई ने एक स्वीकृति विकास निधि की स्थापना का भी प्रस्ताव किया था जिसका उपयोग छोटे शहरों एवं शहरों में कार्ड स्वीकृति बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।
- PIDF को टियर–3 से टियर–6 केंद्रों एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में भौतिक एवं डिजिटल दोनों प्रकार के बुनियादी ढांचे (पीओएस) की तैनाती के लिए परिचितों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है।
- आरबीआई ने आधे फंड को कवर करते हुए 250 करोड़ रुपये का शुरुआती योगदान दिया है। शेष कार्ड जारी करने वाले बैंकों एवं देश में संचालित कार्ड नेटवर्क से आएंगे।
- फंड को एक सलाहकार परिषद के माध्यम से शासित किया जाएगा, लेकिन इसका प्रबंधन RBI द्वारा किया जाएगा।
- यह फंड भारत में 2019–2021 में भुगतान एवं निपटान प्रणाली पर दृष्टि दस्तावेज द्वारा प्रस्तावित उपायों के अनुरूप है।

- PoS बुनियादी ढांचे की बढ़ी हुई क्षमता समय के साथ नकदी की मांग को कम करने वाली है। 2021 तक लगभग 5 मिलियन सक्रिय PoS होंगे।

कोल इंडिया आर्म वेस्टर्न कोलफील्ड्स

समाचार –

- कोल इंडिया सब्सिडियरी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) ने महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कोयले की तीन नई खदानें खोलीं जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 2.9 मिलियन टन (MT) है।
- कंपनी ने कंपनी की 15 प्रमुख खानों के संचालन की निगरानी के लिए 'WCL EYE' के नाम से एक निगरानी प्रणाली शुरू की। यह कोयला स्टॉक की निगरानी में भी सहायता करेगा।
- इसने अपने कर्मचारियों एवं हितधारकों से जुड़ने के लिए SAMVAAD नामक एक ऐप भी लॉन्च किया।

डब्ल्यूसीएलद्वारा खोली गई तीन खदानें –

- अदसा खदान, महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में,
- कन्हान क्षेत्र शारदा भूमिगत खदान
- मध्यप्रदेश के पेंच क्षेत्र में धनकसा भूमिगत खदान।

पीके मोहंती समिति

समाचार –

- RBI ने भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए वर्तमान स्वामित्व दिशानिर्देशों एवं कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए RBI ने केंद्रीय बोर्ड निदेशक पीके मोहंती की अध्यक्षता में एक पाँच सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह का गठन किया है।
- यह 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

समिति के संदर्भ की शर्तें –

- भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व एवं नियंत्रण से संबंधित वर्तमान लाइसेंस दिशानिर्देशों एवं नियमों की समीक्षा करने एवं उचित मानदंडों का सुझाव देना।
- बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्तियों / संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड की जांच एवं समीक्षा करना।
- गैर–सहकारी वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के माध्यम से वित्तीय सहायक कंपनियों की पकड़ पर वर्तमान नियमों का अध्ययन करना एवं मामले में सभी बैंकों को एक समान विनियमन के लिए पलायन का तरीका सुझाना।
- प्रारंभिक / लाइसेंसिंग चरण में प्रमोटर के शेयरधारिता के मानदंडों की जांच करने के लिए एवं बाद में शेयरधारिता के कमजोर पड़ने के लिए समयसीमा के साथ।

सीमा समायोजन कर

समाचार –

- संयुक्त राज्य अमेरिका–चीन व्यापार तनावों के कारण, जो कि आगे कोविड–19 से भी ऊपर उठने की उम्मीद है, एक छप्ज्ज ।लवह सदस्य ने घरेलू उद्योगों को एक स्तर का खेल मैदान देने के लिए आयात पर सीमा समायोजन कर (BAT) लगाने का समर्थन किया है।

BAT का विवरण –

- यह एक शुल्क है जिसे सीमा शुल्क के अलावा आयातित सामान पर लगाया जाना प्रस्तावित है जो प्रवेश के बंदरगाह पर वसूला जाता है।
- बीएटी एक राजकोषीय उपाय है जो माल या सेवाओं पर कर के गंतव्य सिद्धांत के अनुसार शुल्क लगाता है।
- बैट एक कर क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पादों या सेवाओं की आपूर्ति करने वाली विदेशी एवं घरेलू कंपनियों के लिए 'प्रतिस्पर्धा की समान स्थिति' को बढ़ावा देना चाहता है।
- वृहद स्तर पर, आयात कम होने एवं निर्यात बढ़ने के साथ, एक देश अपने व्यापार घाटे में कटौती कर सकता है।

समस्या –

- भारतीय उद्योग घरेलू करों जैसे कि बिजली शुल्क, ईंधन पर शुल्क, स्वच्छ ऊर्जा उपकर, मंडी कर, रॉयल्टी, जैव विविधता शुल्क के बारे में सरकार से शिकायत कर रहा है जो घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर वसूला जाता है क्योंकि ये उत्पाद उत्पाद में अंतर्निहित होते हैं।
- लेकिन कई आयातित सामान अपने मूल देश में इस तरह के लेवी के साथ लोड नहीं किए जाते हैं एवं इससे भारतीय बाजार में ऐसे उत्पादों को लाभ मिलता है।

2019–20 के लिए राष्ट्रीय आय का अनंतिम अनुमान

समाचार –

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने कॉन्स्टेंट (2011–12) एवं करंट प्राइस दोनों पर वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान जारी किए हैं।
- एनएसओ के अनुमानों में चौथी तिमाही एवं वित्त वर्ष 2019–20 की वृद्धि क्रमशः 3.1% एवं 4.2% रही, जो कि 11 वर्षों में सबसे धीमी गति है।
- सरकार का कहना है कि लॉकडाउन ने डेटा प्रवाह को प्रभावित किया है, एवं वैधानिक रिपोर्टिंग समयसीमा के अनुसार अनुमानों में संशोधन की संभावना है।
- हालांकि, तथ्य यह है कि पहली तीन तिमाहियों के लिए जीवीए संख्या को काफी नीचे की ओर संशोधित किया गया है, यह दर्शाता है कि भारतीय में नोवेल कोरोनवायरस के उतरने से पहले ही आर्थिक चिंताएं गहरी एवं व्यापक थीं।

जीवीए पद्धति –

- 2015 में, जीडीपी माप के लिए अपने दृष्टिकोण की व्यापक समीक्षा के मद्देनजर, भारत ने राष्ट्रीय खातों के अपने संकलन में बड़े बदलाव करने का विकल्प चुना।
- यह पूरी प्रक्रिया को 2008 के संयुक्त राष्ट्र प्रणाली (एसएनए) के अनुरूप लाने की कोशिश करता है।
- एसएनए के अनुसार, जीवीए को आउटपुट माइनस के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो मध्यवर्ती खपत का मूल्य है।
- जीवीए एक व्यक्तिगत निर्माता, उद्योग या क्षेत्र द्वारा जीडीपी में योगदान के लिए एक उपाय है।
- अपने सरलतम तरीके से, यह उपयोग किए गए इनपुट एवं कच्चे माल की लागत में कटौती के बाद अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का रुपया मूल्य प्रदान करता है।
- इसे राष्ट्र की लेखा बैलेंस शीट के आय पक्ष पर मुख्य प्रविष्टि के रूप में वर्णित किया जा सकता है, एवं अर्थशास्त्र से, परिप्रेक्ष्य आपूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है।

NSO द्वारा GVA का अनुमान –

- GVA पर डेटा के भाग के रूप में, NSO उत्पादन के त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुमान दोनों देता है – आर्थिक गतिविधि द्वारा जोड़े गए सकल मूल्य से मापा जाता है।
- सेक्टोरल वर्गीकरण आठ व्यापक श्रेणियों पर डेटा प्रदान करता है जो अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कराई गई वस्तुओं एवं सेवाओं के सरगम का विस्तार करते हैं।
- ये हैं – 1) कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालनय 2) खनन एवं उत्खननय 3) विनिर्माणय 4) बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति एवं अन्य उपयोगिता सेवाएंय 5) निर्माणय 6) प्रसारण से संबंधित व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं सेवाएंय 7) वित्तीय, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएँय 8) लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं।

वित्त वर्ष 2021 में अर्थव्यवस्था के 3.2% कम होने की संभावना –

समाचार –

- विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में 3.2% के कमी की आशंका व्यक्त की है, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में यह कमी मुख्यतः कोरोनोवायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कड़े उपायों के कारण रहने की संभावना है।
- विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट में, विश्व बैंक ने कहा कि संकुचन बड़े पैमाने पर वर्ष में 31 मार्च तक अमल में आएगा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वर्ष में 3.1% की दर से विकास करेगी।
- राजकोषीय प्रोत्साहन एवं निरंतर मौद्रिक नीति को बनाए रखने में सहायता के बावजूद वैश्विक विकास एवं वित्तीय क्षेत्र में बैलेंस शीट के तनाव से उबरने का असर गतिविधि पर भी पड़ेगा।
- बहुपक्षीय ऋण देने वाली संस्था ने सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर ध्यान दिया, जिसमें कोविड–19 के प्रतिक्रिया स्वरूप लिए गए स्वास्थ्य देखभाल उपाय, वेतन समर्थन, निम्न–आय वाले परिवारों को नकदी का हस्तांतरण, कर भुगतानों का आधान, साथ ही ऋण एवं छोटे व्यवसायों एवं वित्तीय संस्थानों के लिए तरलता समर्थन शामिल है।
- विश्व बैंक ने कहा कि कोरोनोवायरस महामारी एवं शटडाउन उपायों के तेज एवं बड़े पैमाने पर होने वाले झटके से 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकुचन को बढ़ावा मिलेगा।

समाज एवं स्वास्थ्य

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार

समाचार –

- हाल ही में राज्यों द्वारा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के विस्तार की मांग को देखते हुए योजना की अवधि को नवंबर, 2020 के अंत तक बढ़ा दिया गया है।

प्रमुख बिंदु –

- सरकार द्वारा योजना के विस्तार पर 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किये जाऐगे।
- 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' का लाभ देश के सभी नागरिकों को प्राप्त हो सके इसके लिये 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' की व्यवस्था का विस्तार शीघ्र ही पूरे देश में किया जाएगा।
- 1 जून, 2020 तक 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना को 20 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लागू किया जा चुका है। 31 मार्च, 2021 तक सभी शेष राज्य भी इस योजना से जुड़ जाएंगे।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) –

- PMGKAY, कोविड–19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज' (Pradhan Mantri Garib Kalyan Package - PMGKP) का एक हिस्सा है।
- योजना के तहत 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को कवर किया गया है।
- योजना की घोषणा तीन महीने (अप्रैल, मई एवं जून) के लिये की गई थी।
- योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' (National Food Security Act - NFSA) के तहत प्रदान किये 5 किलो अनुदानित अनाज (गेहूं या चावल) के अलावा 5 किलोग्राम मुक्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा।
- क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार, लाभार्थियों को मुफ्त में 1 किलो दाल भी प्रदान की गई है।

सांस्कृतिक सद्भाव मंडप

समाचार –

- केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने रामपुर (उत्तर प्रदेश) में 'सांस्कृतिक सद्भाव मंडप' के लिए आधारशिला रखी।
- सांस्कृतिक सद्भाव मंडप एक सामुदायिक केंद्र है जिसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत स्थापित किया जा रहा है।
- केंद्र का उपयोग विभिन्न सामाजिक–आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियों, कौशल विकास प्रशिक्षण, कोचिंग, आपदा के दौरान राहत गतिविधियों और विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
- अल्पसंख्यक मामलों को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सामाजिक आर्थिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) लागू किया जाता है।

कोवैक्सिन

समाचार –

- कोवैक्सिन कोविड–19 के खिलाफ भारत का पहला वैक्सीन उम्मीदवार है, जिसे चरण I एवं II नैदानिक परीक्षणों के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) की मंजूरी मिली है।
- कोवैक्सिन एक निष्क्रिय टीका है जो संक्रामक SARS-CoV–2 वायरस के एक स्ट्रेन से बनाया गया है।
- इसे भारत बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- DGCI भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, प्ट तरल पदार्थ और टीकों जैसे दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।
- यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

'eBloodServices'

समाचार –

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (IRCS) के साथ साझेदारी में 'eBloodServices' ऐप लॉन्च किया गया है।
- eBloodServices का उद्देश्य लोगों को विशेष रूप से कोविड–19 महामारी के दौरान आसानी से सुरक्षित रक्त का उपयोग करने की अनुमति देना है।
- इसे डिजिटल इंडिया योजना के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सीडीएसी) की ई–रक्तकोश टीम द्वारा विकसित किया गया है।
- एप्लिकेशन को रक्त शोधक के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ रक्त प्राप्त करना आसान होगा एवं सेवा में एकल खिड़की तक पहुंच होगी।
- ई–रक्तकोष एक केंद्रीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन प्रणाली है जो पूरे देश में ब्लड बैंकों के मानक संचालन प्रक्रियाओं, दिशानिर्देशों एवं वर्कफ्लो को मानकीकृत एवं व्यवस्थित करने के लिए एक व्यापक आईटी समाधान प्रदान करता है।
- इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक स्वैच्छिक मानवीय संगठन है जिसे 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। सोसाइटी के अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं।

नशा मुक्त भारत – वार्षिक कार्य योजना (2020–21)

समाचार –

- **नशा मुक्त भारत** – 272 सबसे प्रभावित जिलों के लिए वार्षिक कार्य योजना (2020–21) को 'अंतर्राष्ट्रीय दिवस के खिलाफ नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी' के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री द्वारा ई–लॉन्च किया गया था।
- नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 'सबसे अधिक प्रभावित' 272 जिलों की पहचान की है जो ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं पूर्वोत्तर राज्यों में हैं।
- इन जिलों की पहचान केंद्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से प्रभावित लोगों के रूप में की गई है।
- नशा मुक्त भारत 'अभियान मूल रूप से 2015 में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल द्वारा शुरू किया गया था।
- मादक द्रव्यों के सेवन से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की राष्ट्रीय सूची के अनुसार, पंजाब के 22 जिलों में से 18 हरियाणा के 22 जिलों में से 10 के साथ–साथ एनसीबी द्वारा चिन्हित किए गए हैं।
- लगभग 8,50,000 भारतीय ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, लगभग 4,60,000 बच्चों एवं 1.8 मिलियन वयस्कों को इनहेलेंट निर्भरता के लिए मदद की आवश्यकता होती है एवं 7.7 मिलियन भारतीयों को ओपियोइड निर्भरता के लिए मदद की आवश्यकता होती है।

कार्य योजना के घटक –

1. जागरूकता के कार्यक्रम।
2. उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों एवं स्कूलों पर ध्यान दें।
3. समुदाय की निर्भरता एवं निर्भर जनसंख्या की पहचान।
4. अस्पताल की सेटिंग में उपचार सुविधाओं पर ध्यान दें।
5. सेवा प्रदाता के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

शैक्षणिक एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए योजना सहयोग (स्पार्क)

समाचार –

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (IITM) के शोधकर्ता हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था में संक्रमण की प्रत्याशा में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए वैकल्पिक तकनीक विकसित करने के लिए शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने या एसपीएआरसी की योजना के तहत जर्मनी में अपने समकक्षों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
- इस परियोजना का उद्देश्य हाइड्रोजन विकास प्रतिक्रियाओं के लिए नए कम लागत वाले इलेक्ट्रोकैटलिस्ट्स का विकास करना है।
- कार्बन डाइऑक्साइड की एक बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन परिणाम उत्पन्न करने के पारंपरिक तरीके, एक ग्रीनहाउस गैस जिसने पर्यावरणीय गंभीर चिंताओं को लागू किया।

स्पार्क का विवरण –

- यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है।
- इस योजना का उद्देश्य भारतीय संस्थानों एवं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षिक एवं अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाते हुए भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर SPARC कार्यक्रम को लागू करने वाला राष्ट्रीय समन्वय संस्थान है।

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान

समाचार –

- प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान नामक एक 125–दिवसीय अभियान शुरू किया है जो उत्तर प्रदेश में प्रवासी एवं दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को रोजगार देगा।
- 5000 उपकरण किट भी राज्य में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत वितरित किए जाएंगे।
- यह मेगा जॉब स्कीम गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है।
- अभियान उत्तर प्रदेश के कुल 31 जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने पर केंद्रित होगा।

कैसे लागू किया जाएगा अभियान?

- केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को अभियान के तहत रोजगार की आवश्यकता वाले लोगों को काम देने की जिम्मेंदारी सौंपी गई है।
- अभियान के लिए सार्वजनिक अवसंरचना से संबंधित 25 कार्य एवं आजीविका के अवसरों में सुधार के लिए चुना गया है जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण घरों का निर्माण, वृक्षारोपण अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण, आदि।
- श्रमिकों के कौशल सेट के आधार पर कार्य प्रदान किए जाएंगे।

'नए सामान्य' की खोज आभियान

समाचार –

- NITI Aayog ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF), सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज (CSBC), अशोका यूनिवर्सिटी एवं हेल्थ एंड डब्ल्यूसीडी के साथ साझेदारी में 'नए सामान्य की खोज' नामक एक अभियान एवं इसकी वेबसाइट शुरू की है।

अभियान के बारे में –

- उद्देश्य देश में एक उपयुक्त कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना है, जिससे लोगों को अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में मास्क पहनने के लिए अनुकूल बनाया जा सके।
- जब तक एक वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती है, तब तक देश के नागरिकों को हाथ की स्वच्छता, मास्क पहनना आदि अभ्यास करके अपने दैनिक जीवन में कुछ व्यवहारिक परिवर्तनों को अपनाना आवश्यक है।
- व्यवहार परिवर्तन अभियान को सशक्त समूह 'ग्रुप 6' के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। (यह समूह प्रभावी समाधान एवं योजनाओं के निर्माण के माध्यम से कोविड–19 प्रतिक्रिया गतिविधियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है)।

व्यवहार परिवर्तन अभियान के दो भाग हैं –

- वेब पोर्टल (http://www-covidthenewnormal-com/) – इसमें कोविड–सुरक्षित होने के लिए आवश्यक व्यवहार संबंधी मानदंड शामिल हैं।
- **मीडिया अभियान** – जैसा कि महामारी ने पूरे देश में लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है, लोग टेलीविजन या इंटरनेट पर अधिक समय दे रहे हैं। व्यवहार परिवर्तन अभियान का उद्देश्य विज्ञापन, बच्चों के लिए एनीमेशन, सोशल नेटवर्किंग साइटों पर आभासी जागरूकता अभियान, आदि के माध्यम से लोगो तक पहुंच बनाना है।

अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मादक पदार्थों के सेवन एवं अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस?

- नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी 2020 के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को 'बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान' विषय के तहत मनाया जा रहा है। UNODC वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 भी इस अवसर पर जारी की गई।
- विश्व में मादक पदार्थों के सेवन से मुक्त समाज बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 7, 1987 करे संकल्प 42/112 अपनाया, एवं 26 जून को घोषित नशीली दवाओं के सेवन एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया।

2020 विषय का फोकस –

- हमारे समाजों पर दवा के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर के देशों के बीच सीमा पार सहयोग बढे। यह कई प्रकार की गलत सूचनाओं के नकारात्मक प्रभावों को प्रतिबंधित करने में मदद करेगा, जिससे नशीली दवाओं की समस्या को दूर करने में शामिल अधिकारियों के लिए चुनौतियां पैदा हुई हैं।
- मादक पदार्थों की तस्करी ने कई विकासशील देशों के समग्र विकास में वर्षों से बाधा डाली है, क्योंकि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जीवन में मौद्रिक स्थिरता के लिए विभिन्न दवा या तस्करी नेटवर्क का शिकार होते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए, समझ में सुधार लाना होगी जिसके लिए बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से बेहतर ज्ञान समाज पर इन नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है।

2020 में दिन का महत्व –

- विश्व ड्रग रिपोर्ट 2020 के अनुसार, यदि 2009 के आंकड़ों की तुलना 2018 से की जाए, तो दुनिया भर में ड्रग उपभोक्ताओं की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2019 में 269 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है।
- एक वैश्विक महामारी के समय, व्यक्तियों, निजी क्षेत्रों, गैर–लाभकारी संगठनों एवं दुनिया भर की सरकारों को प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों के बारे में सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से ड्रग्स के खतरो के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है।

वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020

- यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स (UNODC) ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के ख़िलाफ वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 जारी की है।
- **ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट कार्यालय (UNODC)** – इसकी स्थापना 1997 में संयुक्त राष्ट्र ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम एवं सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन के बीच विलय के माध्यम से हुई थी।
- उद्देश्य – ड्रग्स, अपराध एवं आतंकवाद के मुद्दों के समाधान में सदस्य राज्यों की सहायता करना।
- मुख्यालय – वियना, ऑस्ट्रिया।

वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020

समाचार –

- हाल ही में 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय' द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से वार्षिक तपेदिक (टीबी) रिपोर्ट, 2020 जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु –

- इंडिया टीबी रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, वर्ष 2019 में लगभग 24.04 लाख टीबी (क्षय) मरीजों को अधिसूचित/चिन्हित किया गया है जो वर्ष 2018 की तुलना में 14% अधिक हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में टीबी–एचआईवी से एक साथ होने वाली मौतों की संख्या में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है जिसमे कुल 9% मरीज शामिल हैं।
- इंडिया टीबी की रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, हर वर्ष देश में टीबी–एचआईवी सह–संक्रमण से लगभग 9,700 लोगों की मृत्य हो जाती है।
- इंडिया टीबी रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, देश में कुल 92000 ऐसे लोगों को अधिसूचित किया गया है जिन्हें टीबी–एचआईवी एक साथ है।
- सभी अधिसूचित टीबी रोगियों में एचआईवी जाँच को लेकर जागरूकता का स्तर वर्ष 2019 में 81% हो गया जो वर्ष 2018 में 67% था।
- पिछले दो वर्षों में टीबी रोगियों में उपचार की सफलता दर 70–73% के आसपास रही है। जबकि वर्ष 2014–2016 में यह 76 एवं 77% के बीच रही थी।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के कुल मामलों में से 20% मधुमेह से पीड़ित लोगों के भी हैं।
- वर्ष 2019 में, संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अधिसूचित टीबी रोगियों में 64 प्रतिशत रोगियों की रक्त शर्करा की जाँच की गई थी।
- रिपोर्ट के अनुसार, तम्बाकू के उपयोग के कारण 8% टीबी मामलों में वृद्धि देखी गई है जबकि वर्ष 2018 में यह 4% थी।
- रिपोर्ट के अनुसार देश में अभी भी 0.54 मिलियन टीबी की आबादी को अधिसूचित नहीं किया गया है जो एक चिंता का विषय है।

निक्षय पोषण योजना –

- वर्तमान में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' द्वारा वर्ष 2030 तक विश्व को टीबी/क्षय/तपेदिक के मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है परंतु वर्तमान में भारत सरकार वर्ष 2025 तक देश से क्षय रोग को खत्म करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- वर्तमान में टीबी के उपचार के लिये 4.5 लाख से अधिक डॉट सेंटर देश के लगभग हर गाँव में उपचार प्रदान करते हैं।
- 'निक्षय पोषण योजना' के माध्यम से टीबी रोगियों को उनके पोषण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- वर्ष 2019 में 'टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान' की शुरुआत की गई है जो देश में टीबी के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम है।

निक्षय सिस्टम –

- देश निक्षय सिस्टम द्वारा, टीबी के मरीजों के लगभग पूर्ण ऑनलाईन नोटिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है।
- इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय, नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर के सहयोग से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं सेंट्रल टीबी डिविज़न विकसित कर रहा है।
- निक्षय, एक इंफोर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो मरीजों की जानकारियों के प्रबंधन एवं विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने एकमात्र स्थान है।

ओबीसी के उप–वर्गीकरण पर आयोग

समाचार –

- संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग का कार्यकाल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6 महीने यानी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

अनुच्छेद 340 का विवरण –

- यह पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति के लिए शर्तें तय करता है।
- राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों से मिलकर एक आयोग नियुक्त करने का आदेश दे सकता है, जो भारत के भीतर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए उपयुक्त समझता है।

अन्य संवैधानिक प्रावधान –

- अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के बराबर–बराबर व्यवहार नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 16 (4) – यह प्रदान करता है कि राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान कर सकता है, जो राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

उप–वर्गीकरण –

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने 2015 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप–वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया।
- अक्टूबर 2017 में, राष्ट्रपति ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता में अति पिछड़े वर्गों (ईबीसी) को प्राथमिकता देकर एक कुशल तरीके से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए OBC के उप–वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की।
- ओबीसी के उप वर्गीकरण से यह सुनिश्चित होगा कि ओबीसी समुदायों के बीच अधिक पिछड़ा भी शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण के लाभों का उपयोग कर सकता है।
- यह निर्णय क्रीमी लेयर के बड़े वर्गों को कोटा सिस्टम का लाभ उठाने से रोकता है ताकि वे अपने स्वयं के जाति समूहों के बीच गरीब वर्गों के नुकसान से बच सकें।
- वास्तव में, केंद्र सरकार अब सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़े वर्गों के तहत आने वाले जाति समूहों को अलग–अलग वर्गों द्वारा आरक्षण लाभों का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने की मांग कर रही है।

युक्ति 2.0

समाचार –

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कोरोनवायरस के मद्देनजर दूसरे चरण में देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता एवं इन्क्यूबेट स्टार्ट–अप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से आत्मसात करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है।
- इससे पहले, मंत्री ने YUKTI (यंग इंडिया कॉम्बिंग विद सीओवीआईडी विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन) वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था।

पोर्टल का विवरण –

- समग्र एवं व्यापक तरीके से कोविड–19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करने का इरादा रखता है एवं इसे MHRD के इनोवेशन सेल एवं AICTE द्वारा विकसित किया गया है।
- इस पोर्टल के माध्यम से, मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं को अपनी प्रौद्योगिकियों एवं नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित समर्थन मिले।
- डेटाबेस हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति का एक स्पष्ट चित्र भी देगा।
- इससे सरकार को बाधाओं की पहचान करने एवं देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए उचित नीतियां तैयार करने में भी मदद मिलेगी।

युक्ति 2.0

- यह युक्ति के पुराने संस्करण का तार्किक विस्तार है।
- YUKTI 2.0 'को एवं हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में incubated startups से संबंधित जानकारी को व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने में मदद करने के लिए बनाया गया है।
- YUKTI 2.0 पहल आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
- युवा नए तरीके से सोचने में सक्षम हैं एवं उन्हें अपने विचारों को उद्यमों में बदलने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है।
- इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि YUKTI 2.0 जैसी पहल हमारे शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।
- निवेशकों के साथ नवप्रवर्तनकर्ताओं को जोड़ने के लिए YUKTI 2.0 को एक बाजार के रूप में उभरने की आवश्यकता है, ताकि व्यावसायीकरण के लिए नवीन तकनीकों को आगे बढ़ाया जा सके।
- यह पोर्टल हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली में नवाचारों एवं उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने एवं राष्ट्र निर्माण में युवाओं को शामिल करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

FabiFlu

समाचार –

- ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स ने हल्के से मध्यम लक्षणों के साथ, 18 से 75 वर्ष के आयु वर्ग के कोविड–19 रोगी जो देश में सभी सकारात्मक मामलों में से लगभग 80% के बराबर हैं, के लिए एक मौखिक एंटी–वायरल दवा शुरू करने की घोषणा की है।
- फेविपिरवीर कोविड–19 रोगियों में सह–रुग्ण स्थितियों जैसे मधुमेह एवं हृदय रोग के साथ हल्के से मध्यम कोविड–19 लक्षणों के साथ उपयोग की जा सकती है। यह 4 दिनों के भीतर वायरल लोड को तेजी से कम करता है एवं तेजी से रोगसूचक एवं रेडियोलॉजिकल सुधार प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, फेविपिरवीर ने कोविड–19 सौम्य से लेकर हल्के कोविड–19 मामलों में 88% तक के नैदानिक सुधार को दिखाया है।
- Glenmark, एक शोधपरक एकीकृत वैश्विक दवा कंपनी है एवं इसे भारत के ड्रग रेगुलेटर से विनिर्माण एवं विपणन की मंजूरी मिली है। भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (DCGI), कोविड–19 के इलाज के लिए भारत में फैबइरुविर–अनुमोदित दवा फैबीफ्लू बनाते हैं।
- नए या पुनः उभरने वाले इन्फ्लूएंजा वायरस के संक्रमण के उपचार के लिए 2014 से जापान में फेवीपिरवीर को मंजूरी दी गई है। इसकी क्रिया का एक अनूठा तंत्र है – यह कोशिकाओं में एक सक्रिय फॉस्फोरिबोसाइलेटेड फॉर्म (फेवीपिरविर–आरटीपी) में परिवर्तित हो जाता है एवं वायरल आरएनए पोलीमरेज द्वारा सब्सट्रेट के रूप में पहचाना जाता है, जिससे आरएनए पोलीमरेज गतिविधि बाधित होती है।

छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

समाचार –

- हर साल 21 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 11 जून 2014 को महासभा के 69 वें सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया।
- इस वर्ष, अधिकांश देशों द्वारा अपनाए गए सामाजिक दूरस्था उपायों के कारण, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित थीम 'योगा फॉर हेल्थ – योग एट होम' है।
- WHO ने योग को शारीरिक गतिविधि 2018–20 पर अपनी वैश्विक कार्य योजना में स्वास्थ्य में सुधार के साधन के रूप में उल्लेख किया है – एक स्वस्थ दुनिया के लिए अधिक सक्रिय लोग।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021

समाचार –

- क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 17 वां संस्करण जारी किया गया है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है?

- यह फनंबुनंतमससप ैलउवदके (QS) द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन है – दुनिया भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के विश्लेषण में विशेषज्ञता वाली एक ब्रिटिश कंपनी।
- पहले, इसे टाइम्स हायर एजुकेशन – क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कहा जाता था। 2010 के बाद से नाम बदल गया।
- अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग विशेषज्ञ समूह (IREG) की स्वीकृति प्राप्त करने वाली यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है।
- यह दुनिया के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग देता है।

विश्वविद्यालयों को कैसे स्थान दिया जाता है?

- संस्थानों को रैंक करने के लिए, QS छह संकेतक का उपयोग करता है –
  1. शैक्षणिक प्रतिष्ठा
  2. कर्मचारी प्रतिष्ठा
  3. फैकल्टी / छात्र अनुपात
  4. संकाय के अनुसार प्रतिमान
  5. आंतरिक संकाय अनुपात
  6. अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात।

I-LAB (संक्रामक रोग नैदानिक LAB)

समाचार –

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत के ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में कोविड–19 परीक्षण के लिए भारत की पहली I-Lab (संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला) का उद्घाटन किया।
- यह मोबाइल परीक्षण सुविधा कोविद परीक्षण के लिए देश के दूरदराज के क्षेत्रों में DBT परीक्षण हब के माध्यम से तैनात किया जाएगा।
- यह I-Lab आंध्र प्रदेश मेड–टेक जोन (एएमटीजेड) टीम द्वारा 8 दिनों के रिकॉर्ड समय में डीबीटी के समर्थन से राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के BIRAC द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- I-Lab में जैव सुरक्षा की सुविधा है एवं यह RT-PCR के साथ–साथ एलिसा परीक्षण करने में सक्षम है।

डेक्सामेथासोन

समाचार –

- ब्रिटेन में एक बड़े नैदानिक परीक्षण का नेतृत्व करने वाले शोधकर्ताओं ने घोषणा की कि दवा डेक्सामेथासोन के उपयोग से कोविड–19 रोगियों में सबसे गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की मृत्यु दर में एक तिहाई के आसपास कटौती पाई गई हे।
- यह एक एंटी–इन्फ्लेमेटरी दवा है, आमतौर पर ऐसी स्थितियों का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम नहीं करती है, एवं सूजन एवं ऊतक क्षति का कारण बनती है।
- डेक्सामेथासोन रसायनों के उत्पादन को कम करता है जो सूजन का कारण बनता है एवं सफेद रक्त कोशिकाओं के कार्य करने के तरीके को प्रभावित करके प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को भी कम करता है।
- यह एक श्रेणी में आता है जिसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है, जो कि कोर्टिकोल की निकटता से नकल करता है, मानव में प्राकृतिक रूप से अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा निर्मित हार्मोन है।

सहकार मित्र योजना

समाचार –

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की एक पहल ने अकादमिक संस्थानों के पेशेवरों को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से नेतृत्व एवं उद्यमशीलता की भूमिका विकसित करने का अवसर दिया।
- सहायक सहकारी संस्थाएं युवा पेशेवरों के नए विचारों तक पहुंच बनाती हैं। प्रशिक्षु आत्मनिर्भर होने के लिए ईच्छुक क्षेत्र में काम करने का अनुभव प्राप्त करते हैं।
- यह सहकारी समितियों के साथ–साथ युवा पेशेवरों के लिए भी एक जीत की स्थिति होने की उम्मीद है।
- प्रत्येक इंटर्न को 4 महीने की इंटर्नशिप अवधि में वित्तीय सहायता मिलेगी।
  1. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, आईटी आदि जैसे विषयों में पेशेवर स्नातक इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे।
  2. व्यावसायिक, कृषि व्यवसाय, सहयोग, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास, परियोजना प्रबंधन में एमबीए की डिग्री हासिल कर रहे हैं छात्र भी पात्र होंगे।

Aarogyapath

समाचार –

- अरोग्यपथ, एक सीएसआईआर नेशनल हेल्थकेयर सप्लाई चेन पोर्टल है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की वास्तविक समय पर उपलब्धता प्रदान करना है।
- यह निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं ग्राहकों की सेवा के लिए हाल ही में कोविड–19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शुरू किया गया था।

जया जेटली टास्क फोर्स

समाचार –

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित।
- मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर कम करने एवं पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों की जांच करना।
- जया जेटली द्वारा निर्देशित एवं यह अगले महीने के 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- टास्क फोर्स के जनादेश में स्वास्थ्य, चिकित्सीय कल्याण एवं माँ एवं नवजात/शिशु/बच्चे में गर्भावस्था के दौरान, जन्म एवं उसके बाद पोषण की स्थिति के साथ विवाह एवं मातृत्व की उम्र के सहसंबंध की जांच शामिल है।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस

समाचार –

- दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (WFSD) 7 जून 2020 को मनाया गया।
- थीम – 'खाद्य सुरक्षा, सभी का व्यवसाय'।
- डब्ल्यूएफएसडी को पहली बार 2019 में, 'द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी' की छतरी के नीचे अदीस अबाबा सम्मेलन एवं जेनेवा फोरम द्वारा 2019 में किए गए खाद्य सुरक्षा के पैमाने पर प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए मनाया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के सहयोग से डब्ल्यूएचओ ने सार्वजनिक एजेंडे में खाद्य सुरक्षा की मुख्य धारा के प्रयासों को आगे बढ़ाया एवं विश्व स्तर पर खाद्य जनित बीमारियों के बोझ को कम किया।

बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस

समाचार –

- हर साल 12 जून को मनाया जाता है।
- अपने किसी भी रूप में बाल श्रम के खिलाफ दुनिया भर में आंदोलन को बढ़ावा देना चाहता था।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जागरूकता बढ़ाने एवं बाल श्रम को रोकने के लिए पहली बार 2002 में शुरू किया गया था।
- थीम – कोविड–19 – बाल श्रम से बच्चों की रक्षा करें, पहले से कहीं अधिक।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य लक्ष्य 8.7 को 2025 तक अपने सभी रूपों में बाल श्रम को समाप्त करने का आह्वान किया गया है।

NIRF रैंकिंग जारी

समाचार –

- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) को 2015 में विभिन्न श्रेणियों एवं ज्ञान के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए शुरू किया गया था।
- यह संस्थानों को एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने एवं साथ ही साथ उनके विकास की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- ये रैंकिंग एक ठोस आधार देते हुए विदेशी छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम के लिए आकर्षित करती है।
- यह इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस (IoE) योजना के लिए निजी संस्थानों के मूल्यांकन के मानदंडों में से एक है।

रैंकिंग संस्थानों के लिए उपयोग किए जाने वाले पैरामीटर

1. शिक्षण, सीखना एवं स्त्रोत
2. अनुसंधान एवं व्यावसायिक आचरण।
3. स्नातक परिणाम।
4. पहुँच एवं समावेशिता।
5. साथियों का द्रष्टिकोण।

इस रैंकिंग की पांचवीं लगातार संस्करण

- इस वर्ष 'डेंटल' श्रेणी को पहली बार कुल 10 श्रेणियों / विषय डोमेन में लाया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में, भारतीय संस्थान वैश्विक रैंकिंग में 'अंतर्राष्ट्रीयकरण' पैरामीटर पर संघर्ष करते हैं। यह धारणा के लिए दिए गए उच्च भार के कारण है जो एक व्यक्तिपरक पैरामीटर है।
- जबकि, एनआईआरएफ में, 90% पैरामीटर पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ एवं तथ्य आधारित हैं, जबकि केवल 10% शैक्षणिक साथियों एवं नियोक्ताओं द्वारा धारणा के व्यक्तिपरक पैरामीटर पर आधारित है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

समाचार –

- हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2018–19 में भारत की बेरोजगारी दर में कमी आई है, जहाँ एक ओर वर्ष 2017–18 में यह 6.1 प्रतिशत थी, वहीं वर्ष 2018–19 में यह घटकर 5.8 प्रतिशत हो गई।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु –

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी च्स्थ्ै 2018–19 के अनुसार, इस अवधि के दौरान श्रम बल भागीदारी दर में 37.5 प्रतिशत के साथ मामूली सुधार हुआ है, जो कि 2017–18 में 36.9 प्रतिशत था।
- विदित हो कि श्रम बल को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो या तो कार्य कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं अथवा काम के लिये उपलब्ध हैं।
- इस प्रकार श्रम बल भागीदारी दर देश की कुल आबादी में श्रम बल का प्रतिशत है।
- वहीं बेरोजगारी दर का अभिप्राय श्रम बल के भीतर कार्य न पाने वाले लोगों के प्रतिशत से होता है।
- ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत थी एवं महिलाओं में 3.5 प्रतिशत, जबकि नगरीय क्षेत्र में यह दर पुरुषों में 7.1 प्रतिशत एवं महिलाओं के बीच 9.9 प्रतिशत थी।
- रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में एक कामगार ने औसतन करीब 45 घंटे कार्य किया, जबकि नगरीय क्षेत्रों में एक सप्ताह में एक विशिष्ट अवधि के दौरान एक कामगार ने औसतन 50 घंटे कार्य किया।
- बीते वर्ष आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट से पता चला था कि देश में बेरोजगारी दर बीते 45 वर्षों के सबसे उच्चे स्तर पर पहुँच गई थी।
- वर्ष 2018–19 के दौरान लगभग 51.7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत स्वनियोजन था। वहीं 25.1 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की आय का मुख्य स्रोत आकस्मिक मजदूरी थी एवं लगभग 13.1 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की आय का मुख्य स्रोत नियमित मजदूरी थी।
- वर्ष 2018–19 के दौरान करीब 31.8 प्रतिशत नगरीय परिवारों की आय का मुख्य स्रोत स्वनियोजन था। वहीं 11.0 प्रतिशत नगरीय परिवारों की आय का मुख्य स्रोत आकस्मिक मजदूरी थी एवं 42.8 प्रतिशत नगरीय परिवारों की आय का मुख्य स्रोत नियमित मजदूरी थी।
- भारत में 68.4 प्रतिशत कामगार गैर–कृषि क्षेत्र में अनौपचारिक रूप से कार्य कर रहे थे।
- प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बीच बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- 15–29 आयु वर्ग के युवाओं एवं शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी की दर क्रमशः 17.3 प्रतिशत एवं 11 प्रतिशत रही।
- बेरोजगारी के कारण शहरी युवा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। आँकड़ों के अनुसार 2018–19 के दौरान नगरीय पुरुषों में बरोजगारी दर 18.7 प्रतिशत एवं नगरीय महिलाओं में 25.7 प्रतिशत थी।

चुनौतियाँ –

- 2019–20 में कोविड–19 के कारण लगाए गए लॉकडाऊन से बढी बेरोजगारी दर से निपटना।
- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी के अनुसार, भारत में बेरोजगारी दर जुन 2019 के 7.87 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर मई 2020 में 23.48 प्रतिशत हो गई।

ट्यूलिप पोर्टल

समाचार –

- ट्यूलिप एक शहरी लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसमें सभी ULBs एवं स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को अवसर प्रदान किए गए हैं।
- वित्त मंत्री द्वारा एस्पिरेशनल इंडिया 'थीम के तहत बजट 2020–21 की घोषणा के अनुसार इसकी कल्पना की गई है।
- यह भारत के स्नातकों के मूल्य–से–बाजार को बढ़ाने में सहायता करेगा एवं शहरी नियोजन, परिवहन इंजीनियरिंग, पर्यावरण, नगरपालिका वित्त आदि जैसे विविध क्षेत्रों में एक संभावित प्रतिभा पूल बनाने में मदद भी करेगा।
- इससे ऊर्जा के क्षेत्र में नए विचारों का प्रसार होगा। भारत की शहरी चुनौतियों के समाधान के लिए सह–निर्माण में युवाओं का सहयोग बढ़ेगा।
- यह प्रक्षेपण 2025 तक एमएचआरडी एवं एआईसीटीई के 1 करोड़ सफल इंटर्नशिप के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है।।

विश्लेषण –

- यह कार्यक्रम आने वाले वर्षों में दुनिया में सबसे बड़ी कार्य–आयु की आबादी के कारण भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने में मदद करेगा।
- भारत में तकनीकी स्नातकों का पर्याप्त पूल है, जिनके लिए वास्तविक विश्व परियोजना कार्यान्वयन एवं नियोजन, व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक है।
- सामान्य शिक्षा समाज में मौजूद उत्पादक ज्ञान की गहराई को नहीं दर्शा सकती है। शिक्षा को 'सीख कर करने' के रूप में देखने के बजाय, हमारे समाजों को शिक्षा को 'करने से सीखने' के रूप में पुर्नस्थापित करने की आवश्यकता है।
- इस प्रकार ट्यूलिप भारत के ULBs एवं स्मार्ट शहरों के कामकाज में ताजा ऊर्जा एवं विचारों को बढ़ावा देने के साथ–साथ सीखने के अनुभव के साथ इंटर्न प्रदान करने के जुड़वां लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा।

विज्ञान एवं तकनीक

अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस

समाचार –

- अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2020, 30 जून को मनाया गया।
- इस दिवस का उद्देश्य क्षुद्रग्रह प्रभाव खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना एवं पृथ्वी के निकट खतरे वाली वस्तुओं के मामले में वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले विश्वसनीय संकट संचार कार्यों के बारे में जनता को सूचित करना है।

क्षुद्रग्रह –

- वे धातुओं एवं चट्टानों से बने होते हैं एवं सूर्य की परिक्रमा करते हैं एवं सौर मंडल के छोटे पिंड हैं।
- उनकी कक्षाएँ छोटी एवं अण्डाकार होती हैं।
- वे पूंछ के वातावरण या कोमा का उत्पादन नहीं करते हैं।
- क्षुद्रग्रह बेल्ट एक टोरस के आकार का क्षेत्र है, जो बृहस्पति एवं मंगल ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है।

2023 में स्पेस वॉक पर पहला पर्यटक

समाचार –

- रूसी कंपनी – SP कोरोलेव रॉकेट एवं स्पेस कॉर्पोरेशन – RSC एनर्जिया (रूस की स्पेस एजेंसी के एक हिस्से) ने घोषणा की है कि वह 2023 में स्पेसवॉक के लिए पहला टूरिस्ट ले जाएगा।
- यह घोषणा RSC एनर्जिया द्वारा स्पेस एडवेंचर्स (संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद सामने आई।
- सौदा के अनुसार दो पर्यटकों को दोनों कंपनियों के संयुक्त समझौते के तहत 2023 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए भेजा जाएगा।

- आरएससी एनर्जिया की ओर से, दो पर्यटकों में से एक रोस्कोसमोस से एक कॉस्मोनॉट के साथ एक स्पेसवॉक करने में सक्षम होगा।
- 2001 से 2009 के बीच, अंतरिक्ष एडवेंचर्स के साथ–साथ रोस्कोसमोस आईएसएस में आठ पर्यटकों को ले गया है।
- 2001 में, डेनिस टीटो (यूएसए का एक व्यवसायी) विश्व का पहला निजी स्पेस एक्सप्लोरर (दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला पर्यटक) बन गया।
- 2009 के बाद से दुनिया में कोई अन्य अंतरिक्ष पर्यटन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। आज तक किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने स्पेसवॉक नहीं किया है।

बैकग्राउंड –

- मई 30, 2020 को, स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस में सफलतापूर्वक पहुंचाया। स्पेसएक्स (संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित अंतरिक्ष परिवहन सेवा एवं एयरोस्पेस निर्माता कंपनी), जिसने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी (रोस्कोस्मोस) के एकाधिकार को तोड़ दिया।
- मई 30, 2020 तक, केवल रोस्कोस्मोस के पास इंसानों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक ले जाने की तकनीक थी। सभी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन रूसी चालक दल के अंतरिक्ष यान सोयुज की मदद से किए गए थे।
- फरवरी 2020 में स्पेसएक्स ने स्पेस एडवेंचर्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत, दोनों कंपनियों ने अगले साल अंतरिक्ष पर्यटन यात्रा करने की योजना बनाई है। यात्रा के लिए अंतरिक्ष पर्यटकों की संख्या होगी 3. इस यात्रा के तहत आने वाले पर्यटकों के लिए स्पेसवॉक अभी समझौते का हिस्सा नहीं है।

अनन्या, कीटाणुनाशक स्प्रे

समाचार –

- डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (पुणे) ने अनन्या नाम की एक नैनो–टेक्नोलॉजी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित की है, जो कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए सभी प्रकार की सतहों को कीटाणुरहित करने में कारगर है।
- 'नैनो–टेक्नोलॉजी असिस्टेड फॉर्मुलेशन' कोविड–19 को मानव शरीर में प्रवेश करने से रोक सकता है, एवं इस सूत्रीकरण परत के संपर्क में आने पर वायरस को बेअसर कर सकता है।

विवरण –

- स्प्रे, मास्क, पीपीई, अस्पताल के लिनन, एवं अन्य संभावित दूषित सतहों जैसे चिकित्सा उपकरणों, एलेवेटर बटन, डोर नॉब्स, गलियारों एवं कमरों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- यह चांदी के नैनोकणों एवं एक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध दवा, एम्पीसिलीन को संश्लेषित करके विकसित किया गया है।
- इस सामग्री के गुणों का दो तरीकों से परीक्षण किया गया है – परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी एवं इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी।
- सूत्रीकरण में वायरस के बाहरी प्रोटीन को बेअसर करने की क्षमता होती है एवं चांदी के नैनो–कणों में वायरस की झिल्ली को तोड़ने की क्षमता होती है, जिससे यह अप्रभावी हो जाता है।
- यह पानी पर आधारित स्प्रे है एवं 24 घंटे से अधिक समय तक प्रभावी रहेगा।
- यह सूत्रीकरण कपड़े, प्लास्टिक एवं धातु की वस्तुओं का बहुत प्रभावी ढंग से पालन करता है, एवं मनुष्यों के लिए इसकी विषाक्तता नगण्य है।
- स्प्रे की शेल्फ लाइफ छह महीने से अधिक की बताई जाती है।

नैनोंज़ाईम्स

समाचार –

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IIS बेंगलुरु) की एक शोध टीम ने ऐसे नैनो एंजाइम विकसित किए हैं जो जीवाणुओं की कोशिका झिल्ली को सीधे उसके फॉस्फोलिपिड्स को निशाना बनाकर नष्ट कर सकते हैं।
- नैनोंज़ाईम्स, नैनोमेट्रीज हैं जो बैक्टीरिया पैदा करने वाले रोगों की एक श्रेणी के कोशिका झिल्ली को विघटित कर सकते हैं।
- नैनोमीटर को कई संभावित रोगजनक बैक्टीरिया पर परीक्षण किया जाता है जिससे टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेचिश, हैजा एवं न्यूमोनिया होता है। यह पाया गया कि नैनो एंजाइम ने विकास को रोक दिया एवं रोगाणुओं को मार दिया।
- नैनोंज़ाईम्स एंटीबायोटिक दवाओं की जगह ले सकता है जो अप्रभावी हो गए हैं क्योंकि कई बैक्टीरिया ने अपने स्वयं के एंजाइम का उत्पादन करके उनके लिए प्रतिरोध विकसित किया है।

एक्सट्रीम हीलियम तारा

समाचार –

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान द्वारा किये गए अध्ययन में गर्म एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स के वायुमंडल में पहली बार एकल आयन फ्लोरीन की उपस्थिति का पता चला है।

विवरण –

- एक एक्सट्रीम हीलियम तारा या EHe कम द्रव्यमान वाला सुपरजायंट (बहुत बड़े व्यास एवं कम घनत्व का एक अत्यंत चमकीला तारा) है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता है। जबकि हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे आम रासायनिक तत्त्व है।
- हमारी आकाशगंगा में अब तक ऐसे 21 तारों का पता लगाया गया है। इन हाइड्रोजन रहित पिंडों की उत्पत्ति एवं विकास एक रहस्य है। इनकी रासायनिक विशिष्टताएँ विकास के स्थापित सिद्धांत को चुनौती देती हैं,क्योंकि इनकी रासायनिक संरचना कम द्रव्यमान वाले विकसित तारों के समान नहीं होती है।

अध्ययन का महत्त्व –

- यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि EHe के निर्माण में मुख्य रूप से में कार्बन–ऑक्सीजन (CO) एवं एक हीलियम (He) श्वेत वामन तारों (White Dwarfs) का विलय शामिल होता है।

श्वेत वामन (White Dwarfs) –

- एक श्वेत वामन या सफेद बौने तारे का निर्माण तब होता है जब सूर्य जैसा कोई तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है।
- अपने परमाणु ईंधन के जलने के अंतिम चरण तक, इस प्रकार का तारा अपने बाह्य पदार्थों का सर्वाधिक निष्कासन करता है, जिसके परिणामस्वरूप निहारिका (nebula) का निर्माण होता है।
- तारे का केवल गर्म कोर शेष रहता है। यह कोर एक बहुत गर्म सफेद बौना तारा बन जाता है, जिसका तापमान 100,000 केल्विन से अधिक होता है।
- यद्यपि इनका आकार सूर्य के आकार का लगभग आधा होता है फिर भी ये पृथ्वी से बड़े होते हैं।

- Ehe तारों के विकास के बारे में जानने के लिये उनकी रासायनिक संरचना के सटीक निर्धारण की आवश्यकता होती है एवं यदि कोई विशिष्टता हो, तो बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
- हाइड्रोजन रहित इन पिंडों के विकास को समझने में फ्लोरीन बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्म एक्सट्रीम हीलियम तारों में फ्लोरीन की खोज से उनके विकास के रहस्य के बारे में पता चल सकता है।
- ठंडे EHe तथा ठंडे चिरसम्मत हाइड्रोजन रहित पिंडों (Classical Hydrogen Deficient Stars) में सामान्य तारों (800–8000 के क्रम का) की तुलना में उच्च फ्लोरीन संवर्द्धन पाया गया। RCB परिवर्तक यानी उत्तरकीरीट तारामंडल (Coronae Borealis) में उपस्थित तारे इन दोनों के बीच निकट विकासवादी संबंध को इंगित करते हैं।

अध्ययन का महत्व –

- यह अध्ययन गर्म EHe के विकास क्रम में ठंडे EHe एवं अन्य हाइड्रोजन–रहित तारों के विकासवादी परिदृश्य– जिसमें दो श्वेत वामन तारों का विलय शामिल है, के बारे में जानकारी प्रदान करता है। गर्म EHe के वायुमंडल में अधिक फ्लोरीन प्रचुरता के बारे में जानकारी प्राप्त होने से उनके निर्माण के बारे में दशकों पुराना रहस्य हल हो सकता है।

स्वचालित अल्ट्रासाउंड (LUS) कोविड–19 के लिए

समाचार –

- भारत में अपनी तरह का पहला स्वचालित फेफड़ों का अल्ट्रासाउंड (LUS), IIT - पलक्कड़ द्वारा कोविड–19 की स्क्रीनिंग एवं निगरानी के लिए क्लाउड–आधारित छवि विश्लेषण एवं स्कोरिंग प्रणाली के माध्यम से विकसित किया गया है।
- ऐप अब केवल अल्ट्रासाउंड वीडियो अपलोड करके स्वचालित विश्लेषण करने के लिए चिकित्सकों के लिए उपलब्ध है।
- एक नर्सिंग सहायक (एक कुशल चिकित्सक की अनुपस्थिति में), एलयूएस के एक साधारण प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, फेफड़ों की छवियों को प्राप्त करता है एवं छवियों को क्लाउड में स्थानांतरित करता है।
- छवियों का विश्लेषण क्लाउड पर किया जाता है एवं स्कोर को कुछ मानदंडों के अनुसार या तो संक्रमण के प्रकार या उसकी गंभीरता के लिए निर्धारित किया जाता है।
- दृष्टिकोण न केवल कोविड–19 का पता लगाने के लिए प्रतिबंधित है, बल्कि फेफड़ों के अन्य संक्रमणों की पहचान करने में भी मदद करता है।

सत्यभामा

समाचार –

- SATYABHAMA (साईंस एंड टेक्नोलोजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माईनिंग एडवांसमेंट) पोर्टल को केंद्रीय खान मंत्रालय के कोयला एवं विज्ञान कार्यक्रम के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।

विवरण –

- इसके उद्देश्य में खनन एवं खनिज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है।
- पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा डिजाइन, विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है।
- यह पोर्टल NITI Aayog के NGO Darpan पोर्टल के साथ भी एकीकृत है।
- यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना की दक्षता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के तहत, खान मंत्रालय देश के खनिज संसाधनों के लागू भू–विज्ञान, खनिज अन्वेषण, खनन एवं संबद्ध क्षेत्रों, खनिज प्रसंस्करण, इष्टतम उपयोग एवं संरक्षण में अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

समाचार –

- हाल ही में भारत 'ग्लोबल पार्टनरषिप अष्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' में एक संस्थापक सदस्य के तौर पर षामिल हो गया है।
- भारत के अतिरिक्त इस पहल से जुड़ने वाले अन्य सदस्यों में विश्व की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ, जैसे– अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया एवं सिंगापुर आदि शामिल हैं।

विवरण –

- ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय एवं बहु–हितधारक पहल है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारीपूर्ण विकास एवं मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार एवं आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करने पर आधारित है।
- उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इस पहल के तहत ।प से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान एवं अनुप्रयुक्त गतिविधियों की सहायता से AI के संबंध में सिद्धांत (Theory) एवं व्यवहार (Practice) के बीच मौजूद अंतर को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी।
- यह पहल प्रतिभागी देशों के अनुभव एवं विविधता का उपयोग करके AI से जुड़ी चुनौतियों एवं अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने का अपने प्रकार का पहला प्रयास है।
- GPAI पहल के अंतर्गत AI के जिम्मेदारीपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिये साझेदारों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों एवं शिक्षाविदों को एक साथ लाया जाएगा एवं ऐसी कार्यप्रणाली विकसित की जाएगी, जिनसे यह दर्शाया जा सके कि कोविड–19 के मौजूदा वैश्विक संकट से बेहतर ढंग से निपटने के लिये किस प्रकार AI का लाभ उठाया जा सकता है।
- ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने से भारत समावेशी विकास के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि भारत ने बीते कुछ वर्षों में अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से मानव के समावेशन एवं सशक्तीकरण के दृष्टिकोण के साथ शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, ई–कॉमर्स, वित्त, दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में AI का लाभ उठाना शुरू कर दिया है।

चंद्र का ध्रुवीय अन्वेषण –

समाचार –

- NASA ने ऑर्बिटल साइंस कॉर्पोरेशन ऑफ डलेस, वर्जीनिया के साथ 187 मिलियन डॉलर के अनुबंध को अंतिम रूप दिया, जो नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन स्पेस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- अनुबंध एजेंसी के गेटवे लूनर परिक्रमा चौकी के शुरुआती चालक दल के मॉड्युल के लिए है।
- नासा ने गेटवे के लिए निवास और रसद (HALO) समर्थन को डिजाइन करने के लिए यह अनुबंध जारी किया है, जो नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य 2024 तक पहली महिला और अगले आदमी को चंद्रमा पर भेजना है।
- अनिवार्य रूप से, गेटवे एक छोटा अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, जिसका अर्थ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा और बाद में मंगल के अभियानों के लिए होगा।
- यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक अस्थायी कार्यालय और जीवित क्वार्टर के रूप में कार्य करेगा, जो पृथ्वी से लगभग 2,50,000 मील की दूरी पर है।
- अंतरिक्ष यान में रहने वाले क्वार्टर, विज्ञान और अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाएं और अंतरिक्ष यान का दौरा करने के लिए डॉकिंग पोर्ट होंगे।
- इसके अलावा, अंतरिक्ष यात्री प्रति वर्ष कम से कम एक बार गेटवे का उपयोग करेंगे और उस पर संपूर्ण वर्ष नहीं रहेंगे जैसे वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर करते हैं।
- आईएसएस की तुलना में, गेटवे बहुत छोटा है, जबकि आईएसएस छह बेडरूम वाले घर के आकार का है।
- नासा ने 2026 के लिए गेटवे के पूरा होने का लक्ष्य रखा है, जबकि अंतरिक्ष यान पर काम पहले से ही चल रहा है।
- 2022 तक, नासा ने अंतरिक्ष यान के लिए शक्ति और प्रणोदन तैयार करने की योजना बनाई है, जिसे एक पार्टनर द्वारा प्रदान किए गए वाणिज्यिक रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा।

नेचर इंडेक्स– 2020

समाचार –

- भारत सरकार के 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' के तीन स्वायत्त संस्थानों सहित भारत के शीर्ष 30 संस्थानों को 'नेचर इंडेक्स– 2020' में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु –

- 'नेचर इंडेक्स', 82 उच्च गुणवत्ता वाली विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित शोधलेखों के आधार पर तैयार किया जाने वाला डेटाबेस है।
- ये डेटाबेस 'नेचर रिसर्च' द्वारा संकलित किया गया है।
- 'नेचर रिसर्च' अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी 'स्प्रिंगर नेचर' का एक प्रभाग है।
- 'नेचर इंडेक्स' में विभिन्न संस्थाओं की वैश्विक, क्षेत्रीय तथा देशों के अनुसार रैंकिंग जारी की जाती है।

नेचर इंडेक्स–2020 में शामिल भारतीय संस्थान –

- नेचर इंडेक्स–2020 में विभिन्न विश्वविद्यालयों, 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों', 'भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों', अनुसंधान संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं सहित 30 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है।
- सूचकांक में DST के तीन स्वायत संस्थान 'विज्ञान आधारित कृषि के लिये भारतीय संघ', कोलकाता 7 वें स्थान पर, 'जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र', बंगलौर 14 वें स्थान पर एवं 'एस. एन. बोस बुनियादी विज्ञान के लिये राष्ट्रीय केंद्र', कोलकाता 30 वें स्थान पर हैं।
- वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो 'वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद', 160 वें स्थान तथा 'भारतीय विज्ञान संस्थान', बंगलौर 184 वें स्थान के साथ शीर्ष 500 रैंकिंग में शामिल होने वाले अग्रणी भारतीय संस्थान हैं।

'नेचर इंडेक्स' के आधार –

- नेचर इंडेक्स तैयार करते समय निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है –
- किसी संस्थान द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य।
- संस्थान का विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान।
- संस्थान का उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान में एक–दूसरे के साथ सहयोग तथा समय के साथ किया जाने वाला बदलाव।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

नेपाल–भारत मैत्री

समाचार –

- नेपाल–भारत मैत्री – विकास साझेदारी के तहत पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू में एक स्वच्छता सुविधा के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
- यह पहल दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों एवं लोगों से लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने में एक एवं मील का पत्थर है।
- 2018 में, नेपाल–भारत मैत्री – पशुपति धर्मशाला का काठमांडू में उद्घाटन किया गया।
- यह सुविधा काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटीद्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
- इंडिया जिसने वित्तीय सहायता को 2.33 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का संकल्प लिया है।

खोलोंगचू पनबिजली परियोजना

समाचार –

- भूटान सरकार एवं खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के बीच 600 मेगावाट खोलोंगछू (संयुक्त उद्यम) जलविद्युत परियोजना के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- खोलोंगचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना एक रन–ऑफ–द–रिवर परियोजना है, जो पूर्वी भूटान में त्राश्यांगत्से जिले में खोलोंगचू नदी के निचले हिस्से पर स्थित है।
- इस परियोजना का क्रियान्वयन भूटान के ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन (DGPC) एवं भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN) के बीच गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

नाविक दिवस 2020

समाचार –

- इस वर्ष, 25 जून को, नाविकों (डॉट्स) के वार्षिक दिवस की 10 वीं वर्षगांठ 'सीफेरर्स आर की वर्कस' थीम के तहत मनाया गया।
- सीफेरर्स अभियान का 2020 दिवस, समुद्री यात्रियों को उनके बलिदान एवं उनके सामने आने वाले मुद्दों को स्वीकार करते हुए श्रद्धांजलि देता है। कई मल्लाह महीनों घर से दूर रहते हैं एवं अनिश्चित होते हैं कि वे फिर घर लौटने में सक्षम होंगे या नही।
- अभियान महामारी के जवाब में समुद्री यात्रियों द्वारा हासिल किए गए कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता है। सभी को यह स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि इस बिमारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सामान पहुंचाने के लिए मल्लाहों की क्षमता केंद्रीय है।
- अभियान सभी को प्रोत्साहित करता है कि वे समुद्री यात्रियों के साथ सम्मान का व्यवहार करें ताकि वे विश्व व्यापार को चालू रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर सकें।
- नाविक, कोविड–19 महामारी से लड़ने वाले लोगों की अग्रिम पंक्ति में हैं, जो महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रवाह को बनाए रखने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं, जैसे कि भोजन, दवाइयां एवं चिकित्सा आपूर्ति। हालांकि, संकट ने नाविकों के लिए काम करने की कठिन परिस्थितियों को जन्म दिया है, जिसमें अनिश्चितताओं एवं पोर्ट एक्सेस, री–सप्लाई, क्रू में बदलाव एवं प्रत्यावर्तन के बारे में कठिनाइयां शामिल हैं।

आर्म्स ट्रेड ट्रीटी (ATT)

समाचार –

- चीन संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में शामिल हो जाएगा जो कि संघर्ष क्षेत्रों में हथियारों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा पिछले साल अमेरिका को समझौते से बाहर निकालने की योजना की घोषणा के बाद आया है।
- कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के शीर्ष विधायी निकाय ने संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने के बारे में निर्णय लेने के लिए मतदान किया, जिसे हथियारों के प्रवाह को संघर्ष क्षेत्रों में नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है।
- यह पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के समझौता – जो 2014 में लागू हुआ था, से बाहर निकालने के लिए घोषणा के बाद आता है ।
- यह भी कहा गया कि चीन केवल ऐसे उत्पादों का निर्यात संप्रभु देशों को करता है, न कि गैर–राज्य अभिनेताओं को।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में कहा गया है कि चीन अब दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक है।

एटीटी का विवरण –

- यह एक बहुपक्षीय संधि है जो पारंपरिक हथियारों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती है।
- इस संधि में सदस्य देशों को हथियारों के अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण के रिकॉर्ड रखने एवं सीमा पार ऐसे शिपमेंट को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है जो कि मानव अधिकारों के उल्लंघन या नागरिकों पर हमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- यह 4 दिसंबर 2014 को लागू हुआ।
- एटीटी मानव पीड़ा को कम करने, राज्यों के बीच सहयोग, पारदर्शिता एवं जिम्मेदार कार्रवाई को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय शांति में योगदान देने के उद्देश्य से पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने का एक प्रयास है।
- 2012 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के तत्वावधान में एक वैश्विक सम्मेलन में न्यूयॉर्क शहर में संधि पर बातचीत की गई थी।

फिलिस्तीन शरणार्थीयों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण एजेंसी (UNRWA)

समाचार –

- भारत ने आने वाले दो वर्षों में UNRWA को 10 मिलियन डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है।
- UNRWA के लिए आभासी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की गई।
- प्रशिक्षण एवं निर्माण संस्थानों के माध्यम से क्षमता वृद्धि भारत के अनुसार, फिलिस्तीन को इसके विकास संबंधी सहायता का एक प्रमुख मुद्दा है।
- यह योगदान 2020 के लिए घोषित 5 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की अतिरिक्त राशि होगा।
- भारत कोविड–19 महामारी के बीच महत्वपूर्ण, जीवनरक्षक दवाओं की आवश्यकता वाले देशों की मदद कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण एजेंसी (UNRWA) –

- यह 1949 में महासभा द्वारा स्थापित एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है।
- यह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत एवं सामाजिक सेवाओं, शिविर बुनियादी ढांचे के क्षेत्र एवं सुधार, संरक्षण एवं माइक्रोफाइनेंस में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के राहत एवं मानव विकास में मदद करती है ।
- यह पूर्वी यरुशलम एवं गाजा पट्टी सहित जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन शरणार्थियों को सहायता एवं राहत देने का काम करता है।
- यह लगभग पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान एवं वित्तीय सहायता से वित्त पोषित है एवं वर्तमान में दुनिया के 20 प्रतिशत शरणार्थियों में 5.4 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सेवा करता है।

विश्व शरणार्थी दिवस

समाचार –

- विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2020 को 'एवरी एक्शन काउंट्स' थीम के साथ मनाया गया।
- यह दिन दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है।
- विनाशकारी संघर्ष एवं उत्पीड़न हर साल अपने घरों एवं देशों के हजारों लोगों को उखाड़ फेंकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, हर मिनट, 20 लोग सब कुछ पीछे छोड़कर संघर्ष एवं युद्ध से बचने के लिए मजबूर होते हैं।

शरणार्थी कौन है?

- संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार, जो लोग 'अपने जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, एक विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता, या राजनीतिक राय' के कारण 'उत्पीड़न के एक अच्छी तरह से स्थापित भय के कारण अपने घरों एवं देशों से भाग गए थे' शरणार्थी हैं।

- 4 दिसंबर, 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित एक प्रस्ताव को अपनाया, एवं निर्णय लिया कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में चिह्नित किया जाएगा, ताकि जागरूकता फैलाने एवं शरणार्थियों के लचीलापन का सम्मान किया जा सके।

कोविड–19 महामारी एवं शरणार्थी संकट

- UNHCR सरकारों के साथ मिलकर विस्थापितों की स्वच्छता एवं स्वच्छता सेवाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। यह लोगों के साथ जागरूकता पैदा करने के लिए भी काम कर रहा है। वैश्विक संगठन के मुताबिक, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि, घातक वायरस से संक्रमित होने पर उनकी सुरक्षा की जाए एवं उनका उचित इलाज किया जाए।
- शरणार्थियों के अलावा, अन्य संयुक्त राष्ट्र–नामित विस्थापित व्यक्ति भी हैं जैसे कि शरण चाहने वाले, आंतरिक रूप से विस्थापित लोग, या आईडीपी, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं एवं स्टेटलेस लोगों को पार नहीं किया है जिनके पास राष्ट्रीयता नहीं है।

कोविड–19 सक्रिय प्रतिक्रिया एवं व्यय समर्थन कार्यक्रम

समाचार –

- भारत सरकार एवं एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) ने कमजोर घरों के लिए प्रतिकूल कोविड–19 महामारी के प्रभावों पर अपनी प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए भारत को मदद करने के लिए $750 मिलियन 'कोविड–19 सक्रिय प्रतिक्रिया एवं व्यय सहायता कार्यक्रम' पर हस्ताक्षर किए।
- परियोजना को एआईआईबी एवं एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा $ 2.250 बिलियन की राशि में वित्तपोषित किया जा रहा है, जिसमें से 750 मिलियन डॉलर एआईआईबी द्वारा प्रदान किए जाएंगे एवं 1.5 बिलियन डॉलर एडीबी द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
- प्राथमिक लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार होंगे, किसान, स्वास्थ्य कर्मचारी, महिलाएं, महिला एसएचजी, विधवा, पीडब्ल्यूडी, वरिष्ठ नागरिक, कम वेतन पाने वाले आदि।

एआईआईबी का विवरण –

- यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक मिशन है। एशिया में, जनवरी 2016 में परिचालन शुरू हुआ।
- एआईआईबी अब दुनिया भर में 102 स्वीकृत सदस्यों तक पहुंच गया है।
- एआईआईबी चीन का दिमाग है। एआईआईबी का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचा विकास है।
- बुनियादी ढांचे एवं अन्य उत्पादक सेवाओं के निर्माण में उन्नति के माध्यम से पूरे एशिया में परस्पर संपर्क स्थापित करके, एआईआईबी एशियाई क्षेत्र में विकास एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है।

SIPRI ईयरबुक 2020

समाचार –

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने SIPRI ईयरबुक 2020 का शुभारंभ किया, जो आयुध, निरस्त्रीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन करता है।

प्रमुख खोजें –

- नौ परमाणु–सशस्त्र राज्य–संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल एवं उत्तर कोरिया के पास – एक साथ 2020 की शुरुआत में 13,400 परमाणु हथियार थे, 2019 की संख्या 13,865 से कम।
- 2019 में परमाणु युद्ध की संख्या में समग्र कमी के बावजूद, सभी परमाणु हथियार रखने वाले राज्य अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करना जारी रखते हैं।
- 6,375 एवं 5,800 युद्ध के साथ, रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक हिस्सा है।
- चीन एवं पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। यह चीनी शस्त्रागार में परमाणु हथियारों की संख्या 320 पर आंकी गई है, जबकि पाकिस्तान एवं भारत के परमाणु बलों के पास क्रमशः 160 एवं 150 हथियार होने का अनुमान है। 2019 में, भारत में 130–140 वारहेड थे।
- चीन पहली बार न्यूक्लियर ट्रायड विकसित कर रहा है, जो नई भूमि–समुद्र–आधारित मिसाइल एवं परमाणु–सक्षम विमानों से बना है।

चीन में अंतर–संसदीय गठबंधन

समाचार –

- अमेरिका सहित आठ लोकतंत्रों के वरिष्ठ सांसदों ने कम्युनिस्ट चीन का मुकाबला करने के लिए एकजुट किया है। उन्होंने चीन (IPAC) पर अंतर–संसदीय गठबंधन लॉन्च किया है।

IPAC -

- IPAC वैश्विक व्यापार, सुरक्षा एवं मानवाधिकारों पर चीन के बढ़ते प्रभाव से उत्पन्न खतरे का सामना करने में मदद करने के लिए एक नया क्रॉस–संसदीय गठबंधन है।
- भाग लेने वाले राष्ट्रों में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे एवं साथ ही यूरोपीय संसद के सदस्य शामिल हैं।
- यह विधायकों का एक अंतरराष्ट्रीय क्रॉस–पार्टी समूह है जो सुधार के लिए काम कर रहा है कि लोकतांत्रिक देश चीन के साथ कैसे संपर्क करते हैं।
- समूह का उद्देश्य 'उचित एवं समन्वित प्रतिक्रियाओं का निर्माण करना, एवं चीन से संबंधित मुद्दों पर एक सक्रिय एवं रणनीतिक दृष्टिकोण को तैयार करना है।'

ग्लोबल वैक्सीन समिट

समाचार –

- हाल ही में, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री द्वारा आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट के दौरान, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण Gavi को 15 मिलियन डॉलर दिए।
- इस आभासी शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक देशों, व्यापारिक नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, सरकारी मंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों एवं देश के नेताओं ने भाग लिया।

पृष्ठभूमि –

- कोविड–19 के प्रकोप के बाद से, दुनिया भर में टीके के विकास के गंभीर प्रयास हुए हैं। नैदानिक परीक्षणों के चरण 2 में पहले से ही 100 विभिन्न प्रकार के टीके विकसित किए जा रहे हैं।

- कई सरकारें, फार्मा एवं बायोटेक कंपनियां वैक्सीन के विकास के विभिन्न मोर्चों पर सहयोग कर रही हैं क्योंकि इसके लिए विशेषज्ञता एवं निवेश की बहुत आवश्यकता है।

घोषणा की मुख्य झलकियाँ –

- भारत इन चुनौतीपूर्ण समय में दुनिया के साथ एकजुटता से खड़ा है क्योंकि हमारी सभ्यता दुनिया को एक परिवार के रूप में देखना सिखाती है एवं देश ने इस शिक्षण को जीने की कोशिश की है।
- भारत के पीएम ने उल्लेख किया कि भारत ने दवाओं के उपलब्ध भंडारों को 120 से अधिक देशों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि अपने पड़ोस में एक आम प्रतिक्रिया की रणनीति बनाकर एवं एक साथ अपनी जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करते हुए, मांगने वाले देशों को भी मदद करते हैं।
- उन्होंने उल्लेख किया कि कोविड–19 महामारी ने वैश्विक सहयोग की सीमाओं को उजागर किया है एवं हाल के इतिहास में पहली बार, मानव जाति एक स्पष्ट साझा दुश्मन का सामना कर रही है जिसे जीतने के लिए एक साझा रणनीति की आवश्यकता होती है।
- उन्होंने मिशन इन्द्रधनुष का उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य देश के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है एवं उन्हें भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में जोड़े गए छह नए टीकों के बारे में जानकारी दी।
- उन्होंने उल्लेख किया कि भारत दुनिया में टीकों का सबसे बड़ा उत्पादक है एवं इसने दुनिया के लगभग 60 प्रतिशत बच्चों के टीकाकरण में योगदान दिया है एवं भारत GAVI के काम को मान्यताएवं महत्व देता है।

GAVI क्या है?

- इसे 2000 में बनाया गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय के साथ, गावी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है – एक वैश्विक वैक्सीन एलायंस, जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को एक साथ ला रहा है, जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए एवं आने वाले टीकों की समान पहुंच बनाने के साझा लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है।
- इसका मिशन जीवन को बचाना, गरीबी को कम करना, महामारी के खतरे से दुनिया की रक्षा करना एवं एसडीजी हासिल करने की दिशा में काम करना है।
- GAVI को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, विश्व बैंक एवं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मदद मिलती है।
- GAVI ने दुनिया के सबसे गरीब देशों में 13 मिलियन से अधिक मौतों को रोकने वाले 760 मिलियन से अधिक बच्चों के टीकाकरण में मदद की है।
- GAVI भी दाताओं के साथ काम करता है, जिसमें संप्रभु सरकारें, निजी क्षेत्र की नींव एवं कॉर्पोरेट भागीदार, गैर सरकारी संगठन आदि शामिल हैं।

भारत–पाकिस्तान संबंध

समाचार –

- पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर गोलाबारी एवं जवाबी कार्रवाई चिंता का विषय है क्योंकि इसे इतने लंबे समय तक अनुमति दी गई है कि यह रोजमर्रा की बात हो गई है।
- पुरे मई 2020 में, पीर पंजाल रेंज, जो कश्मीर घाटी का मोर्चा है, में मोर्टारों एवं छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई है।

चिंता का विषय –

- यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति रही है, जब गोले, चुरुंडा एवं सिलिकोत जैसे गाँवों में, रिहायशी इलाकों में गिरते हैं।
- जब गोले बरसने लगते हैं, तो ग्रामीण दहशत में आ जाते हैं, अपने घरों को छोड़कर अस्थायी ठिकानों पर भाग जाते हैं।
- अगस्त 2019 में धारा 370 एवं कोविड–19 लॉकडाउन के कमजोर पड़ने के बाद जीवन में यह अतिरिक्त व्यवधान, कुछ ऐसा है जिसे तत्काल संबोधित किया जाना चाहिए।
- शेलिंग को एक नियमित घटना नहीं होने देना चाहिए।
- नियंत्रण रेखा के साथ पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम स्पष्ट रूप से काम नहीं कर रहा है, एवं सरकार को सामान्य स्थिति लौटने तक नागरिकों के लिए बम आश्रयों का निर्माण करने की आवश्यकता है।
- भारत को पाकिस्तान के साथ फिर से जुड़ने एवं सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन को समाप्त करने की आवश्यकता है।

भारत–नेपाल संबंध

समाचार –

- भारत एवं नेपाल द्विपक्षीय संबंधों में एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं जब दोनों देश मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं।
- नेपाल सरकार ने अपने नक्शे में एक बदलाव की पुष्टि करते हुए संवैधानिक संशोधन पारित करने का निर्णय लिया जिसमें लिपुलेख, कालापानी एवं लिंपियाधुरा, भारत द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले क्षेत्र, संबंधों में एक निश्चित रूप से नए चरण को चिह्नित करते हैं।
- नेपाल के उद्देश्यपूर्ण तरीके से संशोधन को आगे बढ़ाने के लिए ठीक उसी समय जैसा कि भारत–चीन सीमा स्टैंड–ऑफ बॉल्स्टर्स भारत में कुछ लोगों के बीच विश्वास है कि नेपाल बीजिंग के समर्थन से पैदा विश्वास के साथ बोल रहा है।
- उन आरोपों की सच्चाई के बावजूद, या जो संबंधों में गिरावट के लिए अधिक जिम्मेदार हैं, जिस गति के साथ संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था, उसमें अब कूटनीति के लिए बहुत कम जगह बची है।

चिंता का विषय –

- मई में, भारत के रक्षा मंत्री ने मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया। घोषणा एवं इसकी समयावधि ने भारत–नेपाल संबंधों के उत्सुक पर्यवेक्षकों को भी हैरान कर दिया।
- किसी ने नहीं सोचा था कि इस क्षेत्र में एक सड़क परियोजना का उद्घाटन इतनी शीघ्रता से एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा।
- घोषणा ने तुरंत नेपाल सरकार, वहां के लोगों एवं राजनीतिक खिलाड़ियों को हाई अलर्ट पर रख दिया।
- नेपाल की तीखी प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी – सड़क का निर्माण वर्षों से हो रहा था, इसलिए यह दिखावा करने के लिए कि वह इस विकास से अनभिज्ञ थी एवं इसलिए इसके उद्घाटन तर्क पर आश्चर्य हुआ। सुगौली संधि (1816) के अनुसार, काली (महाकाली) नदी के पूर्व में, लिम्पियाधुरा, कालापानी एवं लिपु लेख सहित सभी क्षेत्र नेपाल के हैं।
- ओली सरकार, जो राजतंत्र द्वारा किए गए 'असमान' समझौतों को पलट कर अपनी विरासत का निर्माण करना चाहती है, भारत के लिए एक सुरक्षा दुःस्वप्न का कारण भी बन सकती है यदि यह अपनी लंबी सीमा के अन्य असुरक्षित सीमा चौकियों के हिस्सों को खोलता है, एवं पुरानी प्रतिबद्धताओं को उलट देता है।

आगे की राह –

- एक महामारी का समय शत्रुतापूर्ण पड़ोस का समय नहीं है।
- इस समय, भारत को आदर्श रूप से दक्षिण एशिया में गहरे क्षेत्रीय एवं उप–क्षेत्रीय सहयोग के लिए गति पैदा करनी चाहिए। विडंबना यह है कि नेपाल के साथ हालिया घटनाक्रम इसके विपरीत हैं।
- यह दोनों देशों के बीच शांति को बिगाड़ने वाले किसी भी मामले को सुलझाने के लिए सहानुभूति के साथ रचनात्मक बातचीत में विश्वास को दोहराने का समय है।
- अच्छे एवं बुरे समय में, भारत एवं नेपाल को एक साथ रहना होगा। राजनयिक बातचीत को जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जाना चाहिए।
- दोनों तरफ के दूतावासों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- 2015 में जो कुछ भी हुआ था उसे अब दोहराया नहीं जाना चाहिए। भारत को कोविड–19 संकट के दौरान भी बातचीत से दूर नहीं रहना चाहिए।

आंतरिक सुरक्षा

Maareech

समाचार –

- भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी–टारपीडो डिकॉय सिस्टम जिसे 'मारीच' के नाम से जाना जाता है तथा जो सभी फ्रंटलाइन जहाजों से दागे जाने में सक्षम है, को शामिल किया।

विवरण –

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया।
- आने वाले टॉरपीडो का पता लगाने एवं बेअसर करने में सक्षम है।
- यह प्रेरण रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास की दिशा में भारतीय नौसेना एवं DRDO के संयुक्त संकल्प का सबुत है।
- इसने 'मेक इन इंडिया' पहल एवं आला प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने के देश के संकल्प को भी एक प्रमुख स्थान दिया है।
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक रक्षा PSU, इस डिकॉय प्रणाली के उत्पादन का कार्य करेगी।
- भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता में आज अग्रिम सीमा के युद्धपोतों से निकाल दिए जाने में सक्षम उन्नत टारपीडो डिकॉय सिस्टम 'मारीच' के लिए एक अनुबंध के समापन के साथ एक बड़ा बढ़ावा मिला है।

CERT – बड़े पैमाने पर फिशिंग हमले की चेतावनी

समाचार –

- सरकार के साइबर वॉचडॉग इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT–In) ने कोविड–19 महामारी का फायदा उठाते हुए देश भर में बड़े पैमाने पर फिशिंग हमले की चेतावनी दी है।
- यह चेतावनी सिंगापुर स्थित साइबर खुफिया फर्म साइफिरमा के निष्कर्षों पर आधारित है एवं इसका श्रेय कुख्यात उत्तर कोरिया समर्थित साइबर अपराध समूह – लाजर समूह को दिया गया है।
- हमलावर अपनी साख, वित्तीय जानकारी को चुराने या अपने कंप्यूटर से छेड़छाड़ करने के लिए लक्षित लोगों को कोविड–19 से संबंधित नकली ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट या टेक्स्ट संदेश भेजेंगे।
- ये फिशिंग अभियान सरकारी एजेंसियों, स्थानीय विभागों को प्रभावित करेंगे जो सरकारी वित्तीय सहायता के संवितरण के लिए जिम्मेदार हैं।
- ये दुर्भावनापूर्ण ईमेल स्पूफ किए गए पते – माध्यम से भेजे जा सकते हैं जैसे – ncov@gov-in के। वे लिंक या फाइलें शामिल कर सकते हैं जो दुर्भावनापूर्ण कोड वितरित कर सकते हैं।

फिशिंग अभियान क्या हैं?

- 90 के दशक के मध्य में, फिशिंग शब्द का अर्थ धोखाधड़ी एवं पैसे चोरी करने की कोशिशों एवं संवेदनशील जानकारी जैसे कि उपयोगकर्ता, संगठनों या लोगों या संगठनों के क्रेडिट कार्ड के विवरण को इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के माध्यम से भरोसेमंद संस्था के रूप में प्रस्तुत करना है।
- फिशिंग हमले सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों के माध्यम से किए गए साइबर सुरक्षा खतरे हैं।
- फिशिंग के पीछे आम इरादें – वायरस, कृमि, ट्रोजन हॉर्स, स्पाइवेयर, रैंसमवेयर, गलत सूचना एवं दुष्प्रचार फैलाने, मनोवैज्ञानिक युद्ध – विशिंग (टेलीफोन का उपयोग करना) एवं Smishing के माध्यम से (एसएमएस) – नाबालिगों के यौन शोषण, वित्तीय प्रवेश, पहचान की चोरी, मैलवेयर स्थापित करना है।
- **प्रकार/फिशिंग की तकनीकें** – स्पीयर फिशिंग, व्हेलिंग, कैटफिशिंग / कैटफिशिंग, क्लोन फिशिंग, वॉयस फिशिंग, लिंक मैनीपुलेशन एवं वेबसाइट फॉरजरी

डीप सब्मर्जेन्स रेस्क्यू व्हीकल (डीएसआरवी) कॉम्प्लेक्स

समाचार –

- विशाखापत्तनम में दीप जलमग्न बचाव वाहन (DSRV) कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया।
- यह परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है एवं इसे नई शामिल पनडुब्बी बचाव प्रणाली को समायोजित करने एवं बचाव–तैयार राज्य में डीएसआरवी परिसंपत्तियों को संग्रहीत करने के लिए डिजाइन किया गया है।

DSRV का विवरण –

- इस प्रणाली में एक पनडुब्बी बचाव पोत, एक रिमोट ऑपरेशन वाहन, साइड स्कैन सोनार एवं अन्य संबद्ध उपकरण शामिल होते हैं।
- यह एक डूबे हुए पनडुब्बी से बचाया जाने के बाद गोताखोरों को डिकंम्प्रस करने के लिए इसमे चेम्बर्स एवं हाइपरबेरिक चिकित्सा उपकरण है।
- इस प्रणाली में वायु या सड़क द्वारा जुटाए जाने की क्षमता है, जिससे प्रभावी एवं तीव्र तरीके से दूर के स्थानों पर भी पनडुब्बी बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- भारतीय नौसेना ने दो ऐसी प्रणालियों को शामिल किया है जो क्रमशः भारत के पश्चिम एवं पूर्वी तट पर पनडुब्बियों को बचाव कवर प्रदान करेगी।
- वर्तमान में, लगभग 40 राष्ट्र हैं जो पनडुब्बियों का संचालन करते हैं, जिनमें से कुछ में ही पनडुब्बी बचाव क्षमता का कोई रूप है, भारत उनमें से एक है।
- भारतीय नौसेना की तीसरी पीढ़ी की पनडुब्बी बचाव क्षमता अन्य नौसेनाओं द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में आकस्मिकताओं के दौरान सहायता के लिए मांगी जा सकती है जो आईओआर में भारत की भूमिका के लिए एक गेमचेंजर साबित हो सकती है।

गुगल द्वारा में डेटा प्रथाओं की गलत व्याख्या की गई

समाचार –

- अभियोगी ने अमेरिका के कैलिफोर्निया जिले के उत्तरी जिला के लिए अमेरिका में गुगल उपयोगकर्ताओं की ओर से मुकदमा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुगल ने संघीय वायरटैप कानून के साथ–साथ कैलिफोर्निया गोपनीयता कानून का उल्लंघन किया है।
- गुगल के खिलाफ दायर एक प्रस्तावित क्लास एक्शन मुकदमा में आरोप लगाया गया है कि उपयोगकर्ता अपनी गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए चाहे जो कदम उठा ले इंटरनेट विशालकाय ट्रैक्स को खोजता है एवं ब्राउजिंग डेटा को ट्रेक करता है।

समस्या –

- वादी का आरोप है कि गुगल उन उपयोगकर्ताओं के ब्राउजिंग डेटा को ट्रैक करता है, एकत्र करता है एवं यहां तक कि उन उपयोगकर्ताओं के ब्राउजिंग डेटा को भी पहचानता है जो इकॉग्नीशीओ मोड पर कार्य करते हैं।
- उन्होंने दावा किया कि गुगल, गुगल एनेलेटिक्स, गुगल एडमैनेजर एवं अन्य प्लग–इन जैसे सर्वव्यापी टूल के पास से 'अपने वास्तविक ट्रैकिंग को पूरा करता ह'।
- गुगल एनेलेटिक्स एवं अन्य टूल तभी लागू किए जाते हैं जब उनका कोड मौजूदा वेबसाइटों के कोड में एम्बेड किया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने 'ऑनलाइन 70% से अधिक वेबसाइटों एवं इंटरनेट पर प्रकाशकों' को गुगल एनेलेटिक्स में नियुक्त किया है।
- जब कोई उपयोगकर्ता इन गुगल टूल पर काम करने वाली वेबसाइटों तक पहुंचता है, तो गुगल को स्वचालित रूप से उपयोगकर्ता के आईपी पते, साइट के URL एवं कई एवं अधिक जानकारी के बारे में जानकारी मिलती है।
- गुगल ने अपनेएनेलेटिक्स कोड को इस तरह से डिजाइन किया है कि जब इसे चलाया जाता है, गुगल उपयोगकर्ता के ब्राउजर को उसकी व्यक्तिगत जानकारी गुगल एवं उसके सर्वर को कैलिफोर्निया भेजने का कारण बनता है।
- यह भी आरोप लगाया गया है कि गुगल अपने डेटा संग्रह प्रथाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है।

मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया शामिल

समाचार –

- भारत, स्थायी रूप से ऑस्ट्रेलिया को शामिल करके, मालाबार त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का विस्तार करने के लिए तैयार है जिसमें भारत, अमेरिका और जापान शामिल हैं।

मालाबार नौसेना अभ्यास का विवरण –

- मूल रूप से 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ, 2015 में जापान एक स्थायी भागीदार बन गया।
- पिछले गैर–स्थायी प्रतिभागी ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर हैं।
- वार्षिक मालाबार श्रृंखला की शुरुआत 1992 में हुई और इसमें विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें लड़ाकू विमान संचालन से लेकर नाविकिय अंतर्जनपदीय परिचालन अभ्यासों के माध्यम से लड़ाकू विमानों का संचालन शामिल है।

ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने का महत्व –

- इससे पहले, भारत को चिंता थी कि यह चीन को निशाना बनाते हुए एक "चतुर्भुज सैन्य गठबंधन" की उपस्थिति देगा।
- अब दोनों इंडो–पैसिफिक 'में सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं।'
- इसने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की बेहतर समझ के लिए कई क्षेत्रों में पारस्परिक हित का अभिसरण किया है।
- दोनों से रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के उपायों के हिस्से के रूप में लंबे समय से लंबित म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट (एमएलएसए) के समापन की उम्मीद है।

मनी लॉन्ड्रिंग के संयोजन पर यूरेशियन समूह एवं आतंकवाद का वित्तपोषण (ईएजी)

समाचार –

- भारतीय अधिकारियों ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के तत्वावधान में मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्तपोषण (ईएजी) की बैठक में 32 वें विशेष यूरेशियन समूह में भाग लिया। बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई थी।

ईएजी क्या है?

- ईएजी एक क्षेत्रीय निकाय है जिसमें नौ देश शामिल हैं – भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान एवं बेलारूस।
- 2004 में स्थापित, यह FATF का एक सहयोगी सदस्य है।
- संस्थापक सम्मेलन 6 अक्टूबर, 2004 को मास्को में आयोजित किया गया था एवं इसमें छह संस्थापक देशों ने भाग लिया था – बेलारूस, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस एवं ताजिकिस्तान।
- 2005 एवं 2010 में, समूह का विस्तार उज्बेकिस्तान (2005), तुर्कमेनिस्तान (2010) एवं भारत (2010) को शामिल करने के लिए किया गया था।
- मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्तपोषण पर यूरेशियन समूह के समझौते पर जून 2011 में मास्को में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने ईएजी को एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन का दर्जा दिया था।

ईएजी के मुख्य कार्य –

- सदस्य देशों को 40 – एफएटीएफ एंटी–मनी लॉन्ड्रिंग सिफारिशें लागू करने एवं आतंकवादी वित्तपोषण (एफएटीएफ 40+9 सिफारिशें) से निपटने पर 9 विशेष एफएटीएफ सिफारिशें लागू करते हैं।
- मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के उद्देश्य से संयुक्त गतिविधियों का विकास एवं संचालन।
- एफएटीएफ 40+9 सिफारिशों के आधार पर सदस्य–राज्यों के पारस्परिक मूल्यांकन के एक कार्यक्रम को लागू करना, जिसमें एएमएल / सीएफटी प्रयासों के क्षेत्र में अपनाए गए विधायी एवं अन्य उपायों की प्रभावशीलता का आकलन शामिल है।
- विशेष अंतरराष्ट्रीय संगठनों, निकायों एवं इच्छुक राज्यों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का समन्वय।
- मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवादी वित्तपोषण रुझानों (टाइपोलॉजी) का विश्लेषण करना एवं क्षेत्रीय बारीकियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अपराधों से निपटने के सर्वोत्तम तरीकों का आदान–प्रदान करना।

भूगोल एवं पर्यावरण

सूरज की कोरोना

समाचार –

- वैज्ञानिकों ने हाल ही में सूर्य से निकलने वाली रेडियो लाइट की छोटी सी झलक की खोज की है, जो लंबे समय से लंबित कोरोनल हीटिंग समस्या को समझाने में मदद कर सकती है।
- डेटा को मर्चिसन वाइडफील्ड ऐरे (MWA) रेडियो टेलीस्कोप की मदद से एकत्र किया गया था।
- सूर्य पर एक चुंबकीय विस्फोट के बाद इलेक्ट्रॉनों के बीम से रेडियो रोशनी या सिग्नल निकलते हैं।
- ये अवलोकन आज तक के सबसे मजबूत सबूत हैं कि छोटे चुंबकीय विस्फोटों को मूल रूप से यूजीन पार्कर (प्रख्यात अमेरिकी सौर खगोल भौतिकीविद्) द्वारा 'नैनोफ्लेरेस' के रूप में जाना जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये विस्फोट वास्तव में कोरोना को गर्म कर सकते हैं।

विवरण –

- सूर्य के कोरोना सूर्य के वातावरण का सबसे बाहरी हिस्सा है। यह आमतौर पर सूर्य की सतह के तेज प्रकाश से छिपा होता है। इसे विशेष उपकरणों का उपयोग करके देखा जा सकता है।
- इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है।
- कोरोना सूर्य की सतह की तुलना में लगभग 10 मिलियन गुना कम घना है। यह कम घनत्व सूर्य की सतह की तुलना में कोरोना को बहुत कम उज्ज्वल बनाता है।
- कोरोना सूर्य की सतह से बहुत दूर है। लेकिन सूर्य की सतह की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक गर्म है।
- कोरोना अंतरिक्ष में दूर तक फैला हुआ है। इससे वह सौर वायु आती है जो हमारे सौर मंडल से होकर जाती है। कोरोना के तापमान के कारण इसके कण बहुत तेज गति से चलते हैं। ये गति इतनी अधिक है कि कण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बच सकते हैं।

वाइडफील्ड ऐरे (MWA) रेडियो टेलीस्कोप का विवरण –

- यह कम आवृत्ति वाली रेडियो सरणी (एरे) के निर्माण एवं संचालन के लिए संगठनों के एक अंतरराष्ट्रीय संघ के बीच एक संयुक्त परियोजना है।
- आवृत्ति रेंज 70–300 मेगाहर्ट्ज में काम कर रहे, MWF के मुख्य वैज्ञानिक लक्ष्य सूर्य के, सूर्यमंडल, पृथ्वी के आयनमंडल, एवं रेडियो क्षणिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए ब्रह्मांड के ईको (Reoisation) के कॉस्मोपोलॉजिकल एपिक हाइड्रोजन उत्सर्जन के साथ ही साथ एक्सट्रागैलेक्टिक रेडियो आकाश के नक्शे का पता लगाना है।

भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन

समाचार –

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का पहला आकलन प्रकाशित किया है।
- यह आने वाले सदी में उपमहाद्वीप पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पर भारत का पहला राष्ट्रीय पूर्वानुमान है।
- ये अनुमान भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे में विकसित एक जलवायु पूर्वानुमान मॉडल पर आधारित हैं, एवं यह 2022 में तैयार होने वाले जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की अगली रिपोर्ट का हिस्सा होगा।
- यह भारत में जलवायु विज्ञान एवं नीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि मौजूदा अनुमानों को भूमि एवं समुद्र के तापमान, मॉनसून वर्षा, बाढ़, सूखा एवं हिमालयी वार्मिंग एवं ग्लेशियर के नुकसान के ऐतिहासिक रुझानों के संदर्भ में रखा गया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें –

- रिपोर्ट की मानें तो सतही हवा के तापमान में 5° सेल्सियस की वृद्धि सदी के अंत तक होती है यदि मानव गतिविधियाँ वर्तमान दर पर GHG का उत्सर्जन करती रहती हैं।
- आईपीसीसी के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, पिछली शताब्दी में वैश्विक औसत तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है।
- वर्षा में परिवर्तनशीलता होगी, विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान जो भारत द्वारा प्राप्त 70% वर्षा लाती है एवं इसकी ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक चालकों में से एक है।
- मानसून की बारिश 1400 के औसत से 2100 तक बदल सकती है जो 22.5% तक जा सकती है।

प्रतिनिधि एकाग्रता मार्ग (आरसीपी) –

- भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के आकलन के अनुसार, 1976 एवं 2005 की अवधि की तुलना में, सबसे खराब स्थिति में, भारत में औसत सतह हवा का तापमान सदी के अंत तक 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।
- आरसीपी 4.5 के एक मध्यवर्ती परिदृश्य के तहत, देश का औसत तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।
- तापमान में वृद्धि हिंदू कुश–हिमालयी क्षेत्र में एवं भी अधिक होगा जहां औसत 5.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
- क्षेत्र तापमान, वर्षा एवं बर्फबारी में जलवायु से संबंधित परिवर्तनशीलता के लिए पहले से ही अत्यधिक संवेदनशील है।
- 2100 तक, आरसीपी 8.5 परिदृश्य के तहत 1976–2005 की अवधि की तुलना में गर्म दिनों एवं गर्म रातों की आवृत्ति क्रमशः 55% एवं 70% तक बढ़ सकती है।
- देश में गर्मी की लहरों की घटनाओं में भी तीन से चार गुना वृद्धि हो सकती है।
- जैसा कि 2019 में देश द्वारा पहले ही महसुस किया जा चुका हैं उनके घटने की अवधि भी बढ़ेगी।

ग्यानद्रोमोर्फ

समाचार –

- थ्रिसुर में कोयल वेटलैंड्स के पुजहकल इलाके में एक अजीबोगरीब ड्रैगनफ्लाई, स्कार्लेट स्किमर (क्रोकोथीमिस सर्विसिया) को देखा गया।

विवरण –

- मादा का ग्रीक अर्थ 'गाइन' के, पुरुष के लिए 'एंद्रो', एवं 'मोर्फ' का अर्थ विविधता है।
- वैयक्तिक पशु जिनके पास आनुवंशिक रूप से नर एवं मादा विषमता दोनों हैं।
- मच्छरों, फलों की मक्खियों, मकड़ियों, क्रसटेशियन एवं अन्य आथ्रीपोड्स के साथ–साथ पक्षियों में भी गाइंड्रोमॉर्फ्स की सूचना मिली है। लेकिन वे उन तितली प्रजातियों में सबसे नाटकीय हैं जिनमें शरीर के दोनों प्रकारों को यौन द्विरूपता के कारण शारीरिक रूप से प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएं –

- धब्बेदार व्यक्ति ने द्विपक्षीय ळलदंदकतवउवतचीपेउ दिखाया। पुरुष ड्रैगनफ्लाई में आमतौर पर सिर, वक्ष, पेट एवं पैरों सहित उनके शरीर के लगभग सभी हिस्सों में रक्त–लाल रंग जमा होता है, एवं मादा गहरे भूरे रंग के वक्ष एवं पैरों के साथ हल्के पीले रंग की होती है।
- ग्यानद्रोमोर्फ में कुछ कीड़ों में अंतर्निहित सेक्स–निर्धारण तंत्र के बारे में सूचित करने की क्षमता है एवं इसका उपयोग जननांग जैसे यौन रूप से मंदक संरचनाओं के बीच समरूपता की परिकल्पना को परिष्कृत करने के लिए भी किया जा सकता है।

चिकन का पहला पालतूकरण

समाचार –

- वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में चिकन के शुरुआती वर्चस्व के बारे में नए विवरण सामने आए हैं, जिसमें जीनस गैलस की सभी चार प्रजातियों, रेड जंगल फॉवेल की पांच उप–प्रजातियां एवं दुनिया भर में एकत्र किए गए विभिन्न घरेलू चिकन नस्लों के जीनोम की अनुक्रमण शामिल हैं।
- 863 जीनोम के डीएनए अनुक्रमण ने दक्षिण–पश्चिमी चीन, उत्तरी थाईलैंड एवं म्यांमार में होने वाले चिकन का पहला वर्चस्व दिखाया है।
- परिणामों ने पहले के दावे का खंडन किया कि उत्तरी चीन एवं सिंधु घाटी में मुर्गियों को पालतू बनाया गया था।
- अध्ययन में रेड जंगल फाउल उप–प्रजाति गैलस गैलस स्पैडीसस से एकल वर्चस्व का पता चला।
- अध्ययन में यह भी दिखाया गया है कि सभी पाँच लाल जंगल फाउल उप–प्रजातियां लगभग 50,000 साल पहले (अधिवास की तुलना में बहुत पहले) एक दूसरे से आनुवंशिक रूप से भिन्न थीं, जो कि उनकी भौगोलिक सीमाओं एवं वर्गीकरण वर्गीकरण के अनुरूप थीं।

भितरकनिका मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ

समाचार –

- ओडिशा सरकार ने भितरकनिका नेशनल पार्क में मत्स्य पालन बिल्लियों के लिए दो साल की संरक्षण परियोजना शुरू की है।
- वे दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले एक मध्यम आकार के वाइल्डकैट हैं।
- भारत में, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियों एवं पश्चिमी घाटों पर हिमालय की तलहटी में सुंदरवन के मैंग्रोव जंगलों में मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं।
- 2012 में, पश्चिम बंगाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर मत्स्य पालन बिल्ली को राज्य पशु घोषित किया था।
- आईयूसीएन रेड लिस्टरू कमजोर।
- CITES: परिशिष्ट II
- भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 – अनुसूची I
- धमकी – निवास स्थान, शिकार, दूसरों के बीच अवैध शिकार।

मनी लॉन्ड्रिंग एवं अवैध वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट

समाचार –

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने अवैध वन्यजीव व्यापार पर अपनी पहली वैश्विक रिपोर्ट 'मनी लॉन्ड्रिंग एवं अवैध वन्यजीव व्यापार' रिपोर्ट जारी की।
- अवैध वन्यजीव व्यापार (IWT) पर FATF की यह पहली रिपोर्ट है।
- एफएटीएफ का उद्देश्य उन देशों को मार्गदर्शन प्रदान करना है, जो अवैध वन्यजीव व्यापार से धन शोधन का मुकाबला करने के उपाय कर सकते हैं।
- यह एक अंतर–सरकारी निकाय है जो 1989 में पेरिस में आयोजित जी 7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था।
- इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) मुख्यालय में स्थित है।
- इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए धन शोधन एवं आतंकवादी वित्तपोषण एवं अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए कानूनी, विनियामक एवं परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को मानकों को निर्धारित करना एवं बढ़ावा देना है।
- इसमें 37 सदस्य क्षेत्राधिकार एवं 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं जो दुनिया के सभी हिस्सों में सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हरिताम हरम कार्यक्रम

समाचार –

- 25 जून 2020 को मेडक जिलों नरसापुर के जंगल में एक काले बेर का पौधा लगाकर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरितम् हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया है।
- मुख्यमंत्री ने नरसापुर में शहरी वन पार्क का भी उद्घाटन किया।
- राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम ने भी रोजगार पैदा किया है क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के तहत पौधे रोपने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं।

कार्यक्रम का विवरण –

- 3 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था।
- कार्यक्रम के माध्यम से, तेलंगाना राज्य सरकार ने कुल रोपण करके राज्य में वन आवरण को 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत (2015 के रिकॉर्ड के अनुसार) करने का लक्ष्य रखा है।
- रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य भर में कुल 182 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।
- पौधे इस तरह के जंगल, नगर निगम प्रशासन, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास आदि के रूप में विभागों की मदद से पूरे राज्य में लगाया जाता है।

उत्तर प्रदेश में हर्बल सड़क परियोजना

समाचार –

- उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क के दोनों किनारों पर 800 किमी सड़कों को औषधीय एवं हर्बल पेड़ों के साथ हर्बल बेल्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।
- पीडब्लूडी विभाग इन हर्बल सड़कों पर रेन वाटर रिचार्जिंग सिस्टम की व्यवस्था करेगा।

परियोजना का विवरण –

- ये 800 किलोमीटर की सड़कें राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के साथ होंगी एवं उनके साथ हर्बल गार्डन हवाई, जीवाणु एवं अन्य बीमारियों को दूर रखेगा।
- इन हर्बल सड़कों में पीपल, नीम, सहजन के साथ–साथ ब्राह्मी, अश्वगंधा एवं जटरोफा जैसी अन्य जड़ी–बूटियों की किस्में होंगी।

महत्व –

- ये पौधे दवाओं के लिए कच्चा माल प्रदान करेंगे एवं भूमि के कटाव को रोकने में भी मदद करेंगे।
- यह योजना जैव विविधता को बढ़ावा देने के साथ विकास एवं सौंदर्यीकरण दोनों में मदद करेगी।
- ब्राह्मी जैसे जड़ी–बूटियों के बहुत सारे लाभ हैं जो शरीर के लिए एक सामान्य टॉनिक के रूप में स्मृति एवं अश्वगंधा को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। हालिया अध्ययन में यह ध्यान दिया गया है कि अश्वगंधा कोविड–19 से लड़ने में प्रभावी हो सकता है।

मैकॉस

समाचार –

- राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने एक वन्यजीव तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जो विदेशी मैकॉ की खेप की जब्ती के रूप में की गई है जिसे बांग्लादेश से कोलकाता ले जाया गया था।
- कोलकाता हवाई अड्डे पर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) एवं सीमा शुल्क विभाग के समन्वय से उसी के लिए संयुक्त अभियान चलाया गया।
- पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश एवं म्यांमार की सीमाओं एवं थाईलैंड से निकटता के कारण सीमा पार से वन्यजीव तस्करी के लिए कमजोर हैं।

जब्त मैकॉ के लिए उपलब्ध संरक्षण –

- वे वन्य जीवों एवं वनस्पतियों (CITES) की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के तहत संरक्षित हैं, जिसमें जलकुंभी मैकॉ को उच्चतम सुरक्षा प्रदान की गई है।
- अवैध रूप से आयातित पक्षियों को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 के तहत जब्त कर लिया गया है, जिन्हें CITES प्रावधानों एवं विदेश व्यापार नीति के साथ पढ़ा गया है।
- इसके अलावा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 48 एवं 49 जंगली जानवरों, जानवरों के लेखों या ट्राफियों में व्यापार या वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाती है। आरोपी को अपराध के लिए सात साल की जेल की सजा हो सकती है।

सुकोत्रा द्वीप

समाचार –

- दक्षिणी अलगाववादियों ने यमन के अरब सागर में सुकोत्रा द्वीप पर सऊदी समर्थित सरकारी सेनाओं को बाहर निकालने के बाद अपना गवर्नर नियुक्त कर नियंत्रण कर लिया है।
- यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सुकोत्रा, अपने अद्वितीय जीवों एवं वनस्पतियों के कारण, लाल सागर एवं स्वेज नहर के माध्यम से एशिया को यूरोप से जोड़ने वाली शिपिंग मार्ग में स्थित है।
- सुकोत्रा द्वीपसमूह, उत्तर–पश्चिम हिंद महासागर में अदन की खाड़ी के पास, 250 किमी लंबा है एवं इसमें चार द्वीप एवं दो चट्टानी टापू शामिल हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका विस्तार प्रतित होता हैं।
- समृद्ध एवं विशिष्ट वनस्पतियों एवं जीवों के साथ इसकी जैव विविधता के कारण यह स्थल सार्वभौमिक महत्व का है – सुकोत्रा की 825 पौधों की प्रजातियों में से 37%, इसकी सरीसृप प्रजातियों का 90% एवं इसकी 95% भूमि घोंघा प्रजातियां दुनिया में कहीं और नहीं होती हैं।
- यह स्थल विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण आबादी एवं समुद्री पक्षियों (192 पक्षी प्रजातियां, जिनमें से 44 द्वीपों पर प्रजनन करते हैं, जबकि 85 नियमित प्रवासी हैं) का जीवन स्थल हैं, जिनमें कई खतरे वाली प्रजातियां भी शामिल हैं।
- सुकोत्रा का समुद्री जीवन भी बहुत विविध है, जिसमें रीफ–बिल्डिंग कोरल की 253 प्रजातियाँ, तटीय मछली की 730 प्रजातियाँ एवं केकड़े, झींगा मछली एवं झींगा की 300 प्रजातियाँ हैं।

संक्रांति के उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

समाचार –

- संक्रांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को मनाया गया। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 के 20 जून को घोषित किया गया था।
- यह दिन संक्रांति एवं विषुवों के बारे में जागरूकता लाता है एवं कई धर्मों एवं जातीय संस्कृतियों के लिए उनका महत्व है।
- संक्रांति वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर है एवं विषुव वह समय है जब अंतरिक्ष यह दूरी सबसे कम है।
- संक्रांति एवं विषुव भूमि, कृषि एवं खाद्य उत्पादन प्रणाली, सांस्कृतिक विरासत एवं उनकी सहस्राब्दी परंपराओं की उर्वरता का प्रतीक है।
- वार्षिक रूप से होने वाली दो संक्रांति हैं – गर्मियों की संक्रांति के आसपास (जिसे आमतौर पर 'ग्रीष्म संक्रांति' के रूप में जाना जाता है, गर्मियों का प्राथमिक दिन एवं इसलिए वर्ष का सबसे लंबा दिन) एवं 21 दिसंबर (आमतौर पर 'शीत संक्रांति' के रूप में जाना जाता है) सर्दियों का प्राथमिक दिन एवं वर्ष का सबसे छोटा दिन)।
- गर्मियों में संक्रांति तब होती है जब सूर्य सीधे कर्क रेखा के ऊपर होता है जो 23.5° अक्षांश उत्तर में स्थित है एवं कर्क रेखा के उत्तर में सब जगह के लिए है, सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर है एवं यह वर्ष का सबसे लंबा दिन है।

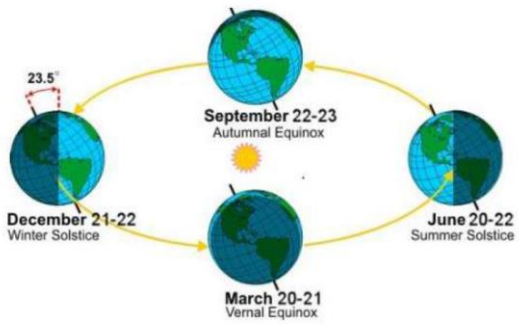

गोल्डन लंगूर

समाचार –

- प्राइमेटोलॉजिस्टों ने देखा है कि सुनहरे लंगूर (ट्रैचीपिटेकस गी), जो भारत एवं भूटान के अर्ध–सदाबहार एवं मिश्रित–पर्णपाती जंगलों की स्थायी प्रजाति गर्भपात के अलावा, मादाओं को शिशुओं के मृतजन्म को भी प्रेरित करते हैं।
- वे असम, भारत एवं पड़ोसी भूटान में पाए जाते हैं जहां वे वर्ष भर रहते हैं।
- गोल्डन लंगूरों ने नम सदाबहार एवं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों के साथ–साथ असम एवं भूटान में कुछ नदी क्षेत्रों एवं सवानाओं पर कब्जा कर लिया है।
- उनके बाल गहरे सुनहरे से लेकर क्रीमी बफ तक हैं एवं उनके चेहरे काले एवं बालों के अलावा लंबी पीली दाढ़ी भी है। यह नोट किया गया है कि उनके फर मौसम के अनुसार रंग बदलते हैं।
- IUCN लाल सूची– लुप्तप्राय
- **CITES**: परिशिष्ट I
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम – अनुसूची I
- **धमकी** – गोल्डन लंगूरों की कम संख्या का मुख्य कारण उनके स्थानीय आवास एवं वनों की कटाई के कारण इस निवास स्थान का तेजी से नुकसान है।

कुंडलाकार सूर्यग्रहण

समाचार –

- एक दुर्लभ खगोलीय घटना, कुंडलाकार सूर्यग्रहण जिसे लोकप्रिय रूप से अग्नि की अंगूठी कहा जाता है, 21 जून, 2020 को दिखाई देगी।
- इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण ग्रीष्म संक्रांति पर हो रहा है, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है।
- जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है, तो पृथ्वी की सतह पर छाया पड़ती है। सूर्य पूरी तरह से चंद्रमा द्वारा एक संक्षिप्त अवधि के लिए कवर किया जाता है। वे स्थान जो चंद्रमा के अंधेरे, घने छाया से घिरे हुए हैं, कुल सूर्य ग्रहण का अनुभव करते हैं।
- उन क्षेत्रों में जो चंद्रमा के नरम विसरित प्रायद्वीपीय छाया में डूबते हैं, आंशिक ग्रहण देखा जाता है। सभी सौर ग्रहणों में, सूरज, चंद्रमा एवं पृथ्वी पूरी तरह से संरेखित नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में, आंशिक ग्रहण होता है। जब तीन खगोलीय पिंड एक सीधी रेखा में होते हैं, तो कुल सूर्य ग्रहण होता है।
- ग्रहण के समय पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी ग्रहण के प्रकार को निर्धारित कर सकती है। चंद्रमा के अंडे के आकार की अण्डाकार कक्षा के कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी हमेशा बदलती रहती है।
- इसका अर्थ है कि ऐसे समय हैं जहां यह पृथ्वी के करीब है एवं आकाश में थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। ऐसे क्षण भी हैं जहां यह दूर है एवं आकाश में कुछ छोटा दिखाई देता है। संयोग से, 21 जून, 2020 को होने वाले ग्रहण के दौरान, चंद्रमा का स्पष्ट आकार सूर्य की तुलना में एक प्रतिशत छोटा है।

विश्व में मरुस्थलीकरण एवं सूखे का दिन

समाचार –

- जून 17, 2020 को "फूड। फीड। फाइबर। – उपभोग एवं भूमि के बीच की कड़ियाँ।" थीम के साथ विश्व में मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस मनाया गया।
- मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 17 जून को यह प्रति वर्ष मनाया जाता है।
- इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा 1995 में घोषित किया गया था, उस दिन के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने मरुस्थलीकरण का मसौदा तैयार किया था।
- इस साल का पालन सार्वजनिक गिरावट के अग्रणी चालक के लिए सार्वजनिक दृष्टिकोण को बदलने एवं मानवता के अथक उत्पादन एवं खपत पर केंद्रित है।
- जैसे–जैसे आबादी बड़ी होती जाती है, धनी एवं अधिक शहरी होते जाते हैं, वहाँ कपड़ों के लिए भोजन, पशु चारा एवं फाइबर प्रदान करने के लिए भूमि की अधिक माँग होती है।
- इस बीच, जलवायु परिवर्तन से बिगड़ती मौजूदा कृषि योग्य भूमि का स्वास्थ्य एवं उत्पादकता घट रही है।
- कपड़े एवं जूते का उत्पादन वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 8 प्रतिशत है, जो 2030 तक लगभग 50 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

पैंगोलिन

समाचार –

- चीन ने पैंगोलिन को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की है एवं अनुमोदित पारंपरिक दवाओं की सूची से पैंगोलिन को हटा दिया है।
- पैंगोलिन फॉलीडोटा ऑर्डर चींटी खाने वाले कवचधारी स्तनधारी हैं। वे त्वचा को कवर करने वाले बड़े, सुरक्षात्मक केरातिन से लैस एकमात्र ज्ञात स्तनपायी हैं।
- पैंगोलिन की आठ प्रजातियों में से, भारतीय पैंगोलिन एवं चीनी पैंगोलिन, भारत में पाए जाते हैं।
- भारतीय पैंगोलिन व्यापक रूप से भारत में पाए जाते हैं, शुष्क क्षेत्र, उच्च हिमालय एवं पूर्वोत्तर को छोड़कर। यह प्रजाति बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एवं श्रीलंका में भी पाई जाती है।
- चीनी पैंगोलिन, पूर्वी नेपाल, भूटान, उत्तरी भारत, उत्तर–पूर्व बांग्लादेश, दक्षिणी चीन एवं ताइवान के माध्यम से हिमालय की तलहटी में पाया जाता है।

IUCN संरक्षण की स्थिति –

- भारतीय पैंगोलिन – लुप्तप्राय
- चीनी पैंगोलिन – गंभीर रूप से लुप्तप्राय
- खतरे – क) पूर्वोत्तर राज्यों में एवं मध्य भारत में इसके मांस का शिकार किया जाता है। एवं बी) विशेष रूप से चीन में चमत्कार, टोने टोटके एवं औषधीय गुणों के कारण इसकी तस्करी की जाती है।

रूस की अंबरनाया नदी में तेल का फैलाव

समाचार –

- रूस ने अपने आर्कटिक क्षेत्र में एक पावर प्लांट के ईंधन रिसाव के कारण 20,000 टन डीजल तेल को स्थानीय नदी में फेंक दिया, जिससे उसकी सतह का लाल हो गई।

विवरण –

- अम्बरनाया नदी, जिसमें तेल का निर्वहन किया गया है, एक नेटवर्क का हिस्सा है जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील आर्कटिक महासागर में बहती है।
- राज्य के स्वामित्व वाली TASS समाचार एजेंसी ने बताया कि रूस के क्रास्नोयार्स्क क्षेत्र के भीतर आपातकालीन उपायों की घोषणा की गई, जो विशाल एवं कम आबादी वाले साइबेरियाई प्रायद्वीप में स्थित है।

रिसाव कैसे हुआ? –

- नॉरिल्स्क में थर्मोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर्माफ्रोस्ट पर बनाया गया है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षों से कमजोर हो गए है।
- बिजली संयंत्र क्षेत्र के नॉरिल्स्क शहर के पास स्थित है, जो मॉस्को से लगभग 3000 किमी उत्तर–पूर्व में है।
- इससे वे खंभे जिन पर संयंत्र के ईंधन टैंक टिके थे उनके डूबने का कारण बन गए।
- लगभग 20,000 टन डीजल तेल अंबरनया नदी में छोड़ा गया था, जो तब से इसकी सतह पर 12 किमी तक बह चुका है।

रूस ने अब तक क्या किया है?

- नदी में बूम बाधाओं को रखा गया था, लेकिन वे उथले पानी के कारण तेल को रोकने में असमर्थ रहे।
- आपातकाल की स्थिति साफ–सफाई के प्रयासों के लिए अतिरिक्त बल एवं संघीय संसाधनों को लाएगी।

नुकसान की सीमा क्या है?

- पर्यावरणविदों ने कहा है कि, इसके उथले पानी एवं दूरदराज के स्थान, साथ ही साथ स्पिल की भयावहता को देखते हुए, नदी को साफ करना मुश्किल होगा।
- वॉल्यूम के मामले में आधुनिक रूस के इतिहास में यह दूसरा सबसे बड़ा ज्ञात तेल रिसाव है।
- साफ–सफाई का प्रयास 5–10 साल के बीच हो सकता है।

लोनार झील

समाचार –

- महाराष्ट्र की लोनार झील गुलाबी हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह पानी में शैवाल की लवणता एवं उपस्थिति के कारण हुआ है।

विवरण –

- यह एक प्राचीन गोलाकार झील है जो महाराष्ट्र में उल्का पिंड द्वारा बनाई गई है।
- 1823 में सीजेई अलेक्जेंडर नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लोनार क्रेटर झील की पहचान एक अद्वितीय भौगोलिक स्थल के रूप में की गई थी।
- लोनार क्रेटर 1979 में भू–धरोहर स्थल बन गया था।
- यह अपेक्षाकृत युवा भौगोलिक रूप से सिर्फ 50,000 साल पुराना है।
- लोनार झील महान डेक्कन ट्रैप के भीतर पाए जाने वालेएक विशाल बेसाल्टिक गठन जो एकमात्र उल्का पिंडों द्वारा बनाया गया एकमात्र ज्ञात गड्ढा है, के भीतर स्थित है।

ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय मंच –

समाचार

- आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय मंच लॉन्च किया एवं इसे एपी पर्यावरण प्रबंधन निगम (APEMC) द्वारा संभाला जाएगा।
- यह अधिकारियों को मंच में शामिल उपकरणों के उपयोग से खतरनाक अपशिष्टों के तुरंत निकासी की निगरानी करने में मदद करेगा।
- APEMC उद्योगों से कचरे के संग्रह को सुव्यवस्थित करेगा, श्रेणी के अनुसार कचरे को खतरनाक या गैर–खतरनाक या ई–कचरे के रूप में व्यवस्थित एवं सुव्यवस्थित करेगा, एवं विभिन्न अपशिष्ट निपटान केंद्रों पर वैज्ञानिक रूप से इसका निपटान करेगा।

भारतीय गौर

समाचार –

- फरवरी 2020 में, नीलगिरी वन प्रभाग में किए गए भारतीय गौर का पहला जनसंख्या आकलन अभ्यास से पता चला है कि अनुमानित 2,000 से अधिक भारतीय गौर 300 वर्ग किलोमीटर की सीमा में रहते हैं।
- नीलगिरी वन प्रभाग में हर साल लगभग 60 गौड़ मर जाते हैं, जो मुख्य रूप से दुर्घटनाओं एवं मानव आवासों के निकटता के कारण होता है।

भारतीय गौर का विवरण –

- गौर, बोस गोरस, जिसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है, सबसे बड़ी विलुप्त होने वाली बोवाइनों में से एक है।
- दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी।
- इसे 1986 से IUCN रेड लिस्ट में 'वल्नरेबल' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट एवं उनकी बहिर्मुखी पहाड़ियाँ विशेष रूप से वायनाड, नागरहोल, मुदुमलाई एवं बांदीपुर कॉम्प्लेक्स, गौर के सबसे व्यापक मौजूदा गढ़ों में से एक हैं।

हल्द्वानी बायो–डायवर्सिटी पार्क

समाचार –

- उत्तराखंड ने विश्व पर्यावरण दिवस पर हल्द्वानी में अपना सबसे बड़ा जैव–विविधता पार्क खोला।

पार्क की विशेषताएं –

- विषयगत उद्यान, एक मिट्टी संग्रहालय, पौधों की प्रजातियां, लाइकेन, काई एवं जुरासिक युग के शैवाल, एक वर्मीकम्पोस्ट इकाई, एक व्याख्या केंद्र एवं एक अत्याधुनिक मौसम स्टेशन हैं।
- पार्क में 479 दुर्लभ पौधों की प्रजातियाँ हैं जिनमें कैक्टस, औषधीय जड़ी–बूटियाँ, विभिन्न प्रकार के पेड़ आदि शामिल हैं
- विभिन्न प्रजातियों के पौधों को विभिन्न इलाकों जैसे नीती मन घाटी एवं केदारनाथ के कुछ ग्लेशियरों से भी लाया गया है।
- जैव विविधता पार्क में पौधों की प्रजातियों को आध्यात्मिक एवं धार्मिक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य एवं सौंदर्य मूल्य वर्गों में विभाजित किया गया है।
- आध्यात्मिक खंड में पेड़ हैं जो पवित्र ग्रंथों जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल एवं अन्य में पाए जाते हैं।
- यह उत्तराखंड की विभिन्न स्थलाकृतियों – अल्पाइन, भाभर, उप–पर्वतीय, पहाड़ी, तृतीयक, दोमट, तराई में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टी को प्रदर्शित करता है।

- पार्क के अंदर व्याख्या केंद्र में विभिन्न पर्यावरणीय अवधारणाओं एवं संरक्षण मुद्दों जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वन नदियों, प्रजातियों के विलुप्त होने, पौधों के आंतरिक संचार एवं जानवरों से मनुष्यों में वायरस के प्रसार जैसे हाल के विकास को समझाया गया है।

एशियाई शेरों की जनगणना

समाचार –
- एशियाई शेर की जनगणना हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा की गई थी एवं विवरण जारी किया गया।

शेर की जनगणना का विवरण –
- हर पांच साल में एक बार आयोजित की जाती है। इस साल लॉकडाउन के कारण इसमें देरी हुई।
- 1936 में जूनागढ़ के नवाब द्वारा पहली शेर जनगणना की गई थी। 1965 से, वन विभाग नियमित रूप से हर पांच साल में शेर की जनगणना कर रहा है।
- विभिन्न कारणों से 6 वीं, 8 वीं एवं 11 वीं जनगणना में एक साल की देरी हुई।

इस वर्ष के प्रमुख निष्कर्ष –
- शेरों की आबादी में 28 प्रतिशत की वृद्धि – गिर क्षेत्र में कुल अनुमानित शेर 674 है। यह संख्या 2015 में 523 था।
- वितरण में 36% विस्तार – आज, एशियाई शेर संरक्षित क्षेत्रों एवं सौराष्ट्र के कृषि–देहाती परिदृश्य में मौजूद हैं। लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में, नौ जिलों को कवर किया गया। 2015 में यह 22,000 वर्ग किमी था।

जनसंख्या में लगातार वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक –
- पिछले कई वर्षों से गुजरात में शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है।
  1. समुदाय की भागीदारी
  2. प्रौद्योगिकी पर रोजगार।
  3. जीवन शैली स्वास्थ्य देखभाल के
  4. उचित प्रबंधन के
  5. मानव–जीवन संघर्ष को कम करने के लिए कदम

यह कैसे किया गया? –
- इस वर्ष, गणना का अनुमान एक जनगणना से नहीं, बल्कि पूनम अवलोकान नामक एक जनसंख्या 'अवलोकन' अभ्यास (2014 में विकसित) से किया गया था, जो प्रत्येक पूर्णिमा को किया जाने वाला एक मासिक–गृह अभ्यास है।
- फील्ड स्टाफ एवं अधिकारी 24 घंटे अपने संबंधित क्षेत्रों में शेरों एवं उनके स्थानों का आकलन करने में बिताते हैं।
- पिछली जनगणना के विपरीत, जिसमें लगभग 2000 प्रतिभागी थे, इस जनगणना में लगभग 1400 कर्मचारी एवं कुछ विशेषज्ञ थे।
- ये कर्मचारी अपने–अपने क्षेत्रों में घूमते रहे एवं शेर ट्रैकर्स द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट के आधार पर एवं मौके के दृश्यों से अपने अनुमान लगाए।

अनुमानों पर चिंता –
- कुछ विशेषज्ञों को अनुमानित संख्या के बारे में आशंका है क्योंकि यह एक अधि–अनुमान हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2015 की जनगणना के एक महीने बाद ही अमरेली में एक फ्लैश फ्लड में 12 शेर मारे गए थे।
- 2018 में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस (CDV) एवं बेब्सियोसिस के प्रकोप में दो दर्जन से अधिक शेर मारे गए थे एवं इस गर्मी में भी एक बेबियोसिस प्रकोप की सूचना मिली थी एवं लगभग दो दर्जन शेरों के मारे जाने की सूचना है।

अन्य क्षेत्रों शेरों का स्थानांतरण –
- वर्तमान में, एशियाई शेर केवल गुजरात तक ही सीमित हैं। एक महामारी पूरी आबादी को मिटा सकती है एवं प्रजाति विलुप्त हो सकती हैं। इसलिए, नए क्षेत्रों एवं राज्यों में प्रजातियों का परिचय एक अच्छा विचार हो सकता है।

विश्व पर्यावरण दिवस

समाचार –
- केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर परामर्श–पत्र जारी किए।
- ये परामर्श–पत्र केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (CPHEEO) ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत तैयार की गई है।
- परामर्श–पत्र निम्न प्रकार हैं –
  1. नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू)के लिए सामग्री वसूली सुविधाएं (MRFs) पर परामर्श–पत्र
  2. लैंडफिल रिक्लेमेशन पर परामर्श–पत्र
  3. ऑन–साइट एवं ऑफ–साइट सीवेज प्रबंधन पर मसौदा परामर्श–पत्र
- ये कुछ प्रमुख समस्याओं के स्थायी समाधान खोजने एवं सुगम बनाने के प्रयास का हिस्सा हैं, जो समग्र स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को रोकते हैं।
- 'मलसूर– द डेमन ऑफ डिफेका' शीर्षक से मल प्रबंधन पर संचार अभियान के लिए एक टूलकिट भी जारी किया गया था।
- इसका उद्देश्य मल कीचड़ के जोखिम की धारणा को बढ़ाना है।

विवरण –
- इसे प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है।
- इस वर्ष का विषय 'जैव विविधता' है।
- भारत में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नागर वन (शहरी वन) पर ध्यान देने के साथ इस वर्ष के विषय पर आभासी उत्सव आयोजित किए।
- इसने 200 निगमों एवं शहरों में शहरी वन बनाने के लिए एक योजना (नगर वन योजना) को फिर से शुरू किया क्योंकि इन सभी शहरों में बगीचे हैं, लेकिन जंगल नहीं हैं।
- वन या तो मौजूदा वन भूमि पर या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य खाली भूमि पर उगाए जाएंगे।
- महाराष्ट्र के पुणे में वाजरे अर्बन फॉरेस्ट को 40 एकड़ नीच भूमि क्षेत्र पर विकसित किया गया है। यह नगर वन योजना के लिए सही मॉडल सेट करता है।
- शहरी वन इन शहरों में प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे।
- विश्व पर्यावरण दिवस 1974 से मनाया जा रहा है एवं अब यह 100 से अधिक देशों में व्यापक रूप से मनाया जाता है तथा पर्यावरण के क्षेत्र में एक वैश्विक मंच बन गया है।
- विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की मेजबानी चीन द्वारा 'वायु प्रदूषण' की थीम के साथ की जा रही है। भारत ने 'प्लास्टिक प्रदूषण' की रोकथाम पर जोर देते हुए विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी की।

- सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के हिस्से के रूप में #SelfiewithSapling अभियान शुरू किया, तथा लोगों से एक पौधा लगाने एवं सोशल मीडिया पर इसके साथ एक सेल्फी पोस्ट करने का आग्रह किया।

स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरमेंट इन फिगर्स 2020 रिपोर्ट

समाचार –
- स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरमेंट रिपोर्ट जारी की गई।
- इसमें उल्लेख किया गया है कि भारत में हर पांच में से एक आंतरिक विस्थापन आपदाओं के कारण होता है, 2019 में ज्यादातर यह बाढ़, चक्रवात एवं सूखे के कारण हुआ है।

मुख्य आकर्षण –
- पिछले साल भारत में 50 लाख से अधिक आंतरिक विस्थापन हुए थे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं (यह विस्थापनों की संख्या को संदर्भित करता है नाकि उसमें शामिल लोगो की संख्या को)
- दक्षिण–पश्चिम मॉनसून के कारण आई बाढ़ें 26 लाख विस्थापनों का कारण बनी, जबकि चक्रवात फानी अकेले 18 लाख विस्थापनों का कारण बना, इसके बाद साइक्लोन वायु एवं बुलबुल इत्यादि आए। रिपोर्ट ने प्रवासी आबादी के 2011 की जनगणना के आंकड़ों को भी तोड़ दिया है।
- आपदा के समय देश में 45 करोड़ से अधिक प्रवासी थे, जिनमें से अधिकांश अपने ही राज्य में प्रवास कर रहे थे। 2011 में, 1.7 करोड़ से अधिक नए प्रवासियों को रोजगार के प्रयोजनों के लिए स्थानांतरित किया गया था, ज्यादातर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में।
- रिपोर्ट में वनों, जल, अपशिष्ट, वायु, भूमि, वन्य जीवन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर डेटा का एक स्नैपशॉट भी है।

सिजोथोरैक्स सिकुसीरुमेन्सिस

समाचार –
- अरुणाचल प्रदेश में मछलियों की एक नई प्रजाति सिजोथोरैक्स सिकुसीरुमेन्सिस खोजी गई है।
- यह मछली पूर्वी सियांग जिले के मीबो सर्कल के तहत गकांग क्षेत्र के पास सिकु एवं सिरुम नदी के जंक्शन से एकत्र की गई थी।
- मछली की प्रजाति जीनस सिजोथोरैक्स की है।
- इस मछली की प्रजाति का नाम उन नदियों के नाम से पड़ा है जहां यह पाई गई थी।
- मछली उफनती हुई नदी के जल निकासी क्षेत्र में रहती है।

कोरल ट्राएंगल डे

समाचार –
- यह दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जून को आयोजित किया जाता है।
- यह कोरल ट्राएंगल का एक विशाल उत्सव है, जो दुनिया की समुद्री जैव विविधता का केंद्र है, जिसमें एशिया–प्रशांत क्षेत्र में 6 देश समाहित है – इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप एवं तिमोर लेस्ते।
- आयोजन समुद्र संरक्षणएवं कोरल ट्राएंगल की सुरक्षा एवं संरक्षण के कई तरीकों पर प्रकाश डालता हैं।
- कोरल ट्रायंगल को कांगो बेसिन एवं अमेजॅन रेनफॉरेस्ट के साथ मिलकर पृथ्वी पर 3 मेगा पारिस्थितिक परिसरों में से एक माना जाता है। इस क्षेत्र में सभी ज्ञात प्रवाल प्रजातियों का 76%, सभी ज्ञात प्रवाल भित्तियों की प्रजातियों का 37% एवं दुनिया के प्रवाल भित्तियों का 53% शामिल हैं।
- पहला कोरल ट्रायंगल डे 9 जून 2012 को विश्व महासागरीय दिवस के साथ मनाया गया था जो हर साल 8 जून को मनाया जाता है।

साइक्लोन निसर्ग

समाचार –
- निर्सग (साइक्लोनिक स्टॉर्म) पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बना है। नई सूची में नाम बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया था।
- निसर्ग ने भूमि की ओर प्रवेश मुंबई तट के बहुत करीब से किया।
- चक्रवात निर्सग को ताकत एवं तीव्रता में चक्रवात अम्फान से कमजोर होने की उम्मीद है।
- हालांकि दोनों चक्रवातों के मामले में, तीव्र तूफान के पीछे असाधारण गर्म महासागर का तापमान लगता है।

चक्रवात क्या है?
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत उच्च गति वाली हवाओं की कोई भी बड़ी प्रणाली है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में एंटीक्लॉकवाईस दिशा में तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में क्लॉकवाईस दिशा में घूमते है।
- हवा की गति, हवा की दिशा, तापमान एवं आर्द्रता जैसे कारक चक्रवात के विकास में योगदान करते हैं।
- बादल बनने से पहले पानी वाष्प में बदलने के लिए वायुमंडल से गर्मी लेता है। जब यह जल वाष्प वर्षा के रूप में वापस तरल रूप में बदल जाता है, तो गर्मी वातावरण में फिर से चली जाती है।
- वातावरण में जारी गर्मी चारों ओर हवा को गर्म करती है। हवा बढ़ने लगती है एवं दबाव में गिरावट का कारण बनती है। अधिक हवा तूफान के केंद्र में जाती है। यह चक्र दोहराया जाता है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, चक्रवात हमेशा बंगाल की खाड़ी में अधिक बार आते हैं, लेकिन वे भारत के पश्चिमी तट से कम आते हैं – एक प्रवृत्ति जो धीरे–धीरे बदल रही है।
- इसके अलावा, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात अरब सागर में बने चक्रवातों से अधिक मजबूत होते हैं। अरब सागर का अपेक्षाकृत ठंडा पानी बंगाल की खाड़ी में बनने वाले बहुत मजबूत चक्रवातों की तुलना में कमजोर चक्रवात बनाता है।

कला एवं संस्कृति

पुणे एनजीओ का उद्देश्य 'लाल–बाल–पाल' की भावना को पुनर्जीवित करना

समाचार –
- 'लाल–बाल–पाल' की स्वतंत्रता–संघर्ष–युग की भावना को पुनर्जीवित करने के लिए, पुणे स्थित गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) 'सरहद' महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू करेगा।
- यह दो साल लंबी घटना होगी एवं इसे 'महाराष्ट्र–बंगाल मैत्री अध्याय' नाम दिया गया है। इसे इन दोनों राज्यों में लोगों के सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में देखा जाता है।
- पंजाब, बंगाल एवं महाराष्ट्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीन राज्यों के बीच ऐतिहासिक संबंध एवं सांस्कृतिक बंधन आधुनिक युग में 'लाल– बाल–पाल' की त्रिमूर्ति द्वारा जम गए थे।

- आजादी के बाद, जबकि महाराष्ट्र एवं पंजाब के बीच सामाजिक–सांस्कृतिक बंधन मजबूत हुए हैं, अतीत में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आत्मीयता के एक समृद्ध वंशावली के बावजूद, बंगाल के साथ महाराष्ट्र के संबंध कुछ कमजोर हुए हैं।
- यह तिलक की मृत्यु शताब्दी (1 अगस्त, 1920–अगस्त 1, 2020) पर शुरू होगी एवं 15 अगस्त, 2022 तक महान दार्शनिक, श्री अरबिंदो घोष की 150 वीं जयंती के अवसर पर जाएगी।

केलाड़ी खुदाई

समाचार –
- तमिलनाडु के कोंथागई उत्खनन स्थल पर काम करने वाले पुरातत्वविदों को एक कंकाल की माप मिली, जिसकी ऊंचाई 75 सेमी थी। यह दो कलशों के बीच पाया गया था एवं माना जाता है कि यह एक बच्चे का है।
- शिवगंगा जिले के केलाड़ी से लगभग 4 किमी दूर कोंथगाई को उस सभ्यता का दफन स्थल माना जाता था।
- इसे केलाड़ी स्थल पर चल रहे छठे चरण में खुदाई के लिए लिया गया था।
- पुरातत्वविदों ने अब तक तीन कलशों की खुदाई की है।
- केलाडी में खुदाई से यह साबित होता है कि तमिलनाडु में संगम युग में वैगई नदी के किनारे एक शहरी सभ्यता मौजूद थी।
- कई पुरावशेषों का पता लगाया गया है जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल (6 ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4 थी सदी ईसा पूर्व) एवं उसके बाद के सांस्कृतिक घटनाक्रमों में लौह युग (12 वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व) के लापता लिंक को समझने के लिए महत्वपूर्ण सबूत प्रदान करते हैं।

आषाढ़ी बिज, कच्छी नववर्ष

समाचार –
- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने लोगों को आषाढ़ी बिज – कच्छी नववर्ष के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं।

विवरण –
- उत्तरी भारत में विशेष रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं अन्य स्थानों पर किसानों के लिए एक शुभ दिन है।
- यह दूसरे दिन आषाढ़ी महीने (आषाढ़ी सुद बीज) की आधी रात को पड़ता है।
- यह मुख्य रूप से मानसून की भविष्यवाणी करने के लिए मनाया जाने वाला एक छोटा त्योहार है।

संकल्प पर्व

समाचार –
- प्रधानमंत्री के आह्वान पर, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक वृक्षारोपण करने के लिए "संकल्प पर्व" मनाएगा।
- **संकल्प पर्व** – यह एक पहल है जिसे प्रधानमंत्री के आह्वान पर 5 लाख पौधे लगाने के लिए लिया गया है या तो कार्यालय परिसर में या जहाँ भी देश के स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण को सुनिश्चित करना संभव है।
- **पेड़** – संस्कृति मंत्रालय ने पांच पेड़ लगाने की सिफारिश की है जो देश की हर्बल विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं – बरगद, आवला, पीपल, अशोक एवं बेल।

विवेकानंद योग विश्वविद्यालय (VaYU)

समाचार –
- 6 ठें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्मरणोत्सव के भाग के रूप में, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स में शुरू किया गया है।
- विश्वविद्यालय ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश करता है जो योग के प्राचीन भारतीय अभ्यास के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधान दृष्टिकोण को जोड़ती है।
- विवेकानंद योग विश्वविद्यालय (VaYU) को भारत के विदेश राज्य मंत्री और विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।
- लॉन्चिंग समारोह न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक आभासी कार्यक्रम था।
- प्रख्यात भारतीय योग गुरु डॉ. एच. आर. नगेन्द्र, स्वामी विवेकानंद योग अनुसन्धान संस्थान (SVYASA) के चांसलर VaYU के पहले अध्यक्ष हैं।
- VaYU वैज्ञानिक सिद्धांतों और योग के लिए आधुनिक अनुसंधान दृष्टिकोण के आधार पर ऑनलाइन स्नातक कार्यक्रम प्रदान करेगा।

अगुआडा फेनिक्स

समाचार –
- एक हवाई दूरस्थ–संवेदन विधि (LIDAR) का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्मारक निर्माण खोजा है।
- यह निर्माण प्राचीन माया सभ्यता द्वारा निर्मित ग्वाटेमेले सीमा के पास अगुआडा फेनिक्स नामक एक स्थान पर स्थित है।

विवरण –
- संरचना मेक्सिको के ताबास्को राज्य में 1,000 और 800 ईसा पूर्व के बीच निर्मित एक विशाल आयताकार ऊंचा मंच है।
- मेक्सिको में ग्वाटेमाला और पालेंक जैसे शहरों में बढ़ते माया पिरामिडों के विपरीत, लगभग 1,500 साल बाद, यह हाल ही में खोजी गई संरचना मिट्टी और पृथ्वी से नहीं बनी थी, पत्थर की भी नहीं और सामूहिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल की गई थी।
- संरचना लगभग एक चौथाई मील (400 मीटर) चौड़ी और नौ–दस मील (1,400 मीटर) लंबी और 33 से 50 फीट (10 से 15 मीटर) ऊँची है। कुल मात्रा में, यह प्राचीन मिस्र के गीजा के ग्रेट पिरामिड से अधिक था, जिसे 1,500 साल पहले बनाया गया था।
- यह साइट मैक्सिकन राज्य वेराक्रूज में पश्चिम में सैन लोरेंजो के पुराने ओल्मेक सभ्यता केंद्र के समान दिखती है।
- लेकिन शासकों और कुलीनों से संबंधित पत्थर की मूर्तियों की कमी, जैसे कि प्रमुख सिर और सिंहासन, सैन लोरेंजो की तुलना में कम सामाजिक असमानता का सुझाव देते हैं।
- यह माया के शुरुआती दिनों में सांप्रदायिक कार्यों के महत्व पर प्रकाश डालता है।
- इस बात पर हमेशा बहस होती रही है कि क्या ओल्मेक सभ्यता माया सभ्यता के विकास का कारण बनी या माया स्वतंत्र रूप से विकसित हुई।

Lidar (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) एक रिमोट–सेंसिंग तकनीक है जो सतह की विशेषताओं के आकार के बारे में 3–डी जानकारी उत्पन्न करने के लिए एक साइट पर उड़ान भरते हुए एक स्पंदित लेजर और अन्य डेटा को रोजगार देती है।

रज पर्व

समाचार –

- ओडिशा ने रज पर्व नामक एक अनूठा त्योहार मनाया।
- यह तीन दिन तक चलने वाला त्योहार है, जो धरती माता (भगवान विष्णु की पत्नी, भूमा देवी) को समर्पित है।
- रज पर्व में नारीत्व का जश्न मनाते हैं।
- उत्सव मिथुन संक्रांति से एक दिन पहले शुरू होता है और उसके दो दिन बाद समाप्त होता है।

त्योहार का विवरण –

- पहला दिन – इसे पिल्ली रज कहा जाता है। तैयारी पिल्ली रज से एक दिन पहले शुरू होती है, और इसे सजबाजा कहा जाता है।
- दूसरा दिन – इसे मिथुन संक्रांति कहा जाता है
- तीसरा दिन – इसे भू दाह या बासी रज कहा जाता है।
- मुख्य रूप से, यह अविवाहित लड़कियों के लिए उनके विवाह की तैयारी का समय है। वे पोदपीठा जैसे पौष्टिक भोजन का सेवन, नंगे पांव न चलना, पहले दिन स्नान करना और पेड़ से जुड़ी रस्सियों के झुलों पर झूलते हुए त्योहार से संबंधित विभिन्न रीति–रिवाजों का पालन करते हैं।

कहानी –

- भूमा देवी इस अवधि के दौरान अपने मासिक धर्म से गुजरती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ओडिया में 'रज' शब्द का अर्थ है मासिक धर्म, और यह रजस्वला से लिया गया है, जिसका अर्थ है मासिक धर्म वाली महिला।
- हैरानी की बात यह है कि यह एक ऐसा त्योहार है जो नारीत्व के इस पहलू का जश्न मनाता है जो नारी के अस्तित्व को अद्वितीय बनाता है।
- मासिक धर्म को प्रजनन क्षमता का संकेत माना जाता है, और इसलिए, यह स्त्रीत्व और उसकी क्षमता को दूसरे जीवन को जन्म देने के रूप में मनाता है।
- परबा के दौरान, ओडिया लोग कोई भी निर्माण कार्य या ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिसके लिए पृथ्वी को खोदने की आवश्यकता होती है।
- और इस तरह की गतिविधियाँ न करके, वे धरती माँ को प्रणाम करते हैं, जिन्हें दिनचर्या के काम से छुट्टी चाहिए होती है।
- त्योहार का समापन वसुमती स्नान या भूमा देवी के स्नान के रूप में होता है।
- महिलाएं एक पत्थर की पूजा करती हैं जो धरती माता का प्रतीक है।
- वे उसे हल्दी के पेस्ट से नहलाते हैं और उसके फूल चढ़ाते हैं और उसे सिन्दूर खिलाते हैं।
- यह त्योहार ग्रीष्मकाल के अंत और मानसून के आगमन के साथ भी जुड़ा हुआ है।
- और इसलिए, यह कृषि और खेती से संबंधित समुदायों और गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है।

ताल–मड्डले

समाचार –

- ताल–मड्डले का प्रदर्शन, कोविड–19 के कारण जून 13, 2020 को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया गया।
- ताल–मड्डले 'यक्षगान थियेटर' का एक प्रकार है।
- ताल–मड्डले कर्नाटक और केरल के करावली और मलनाड क्षेत्रों में प्रदर्शन संवाद या बहस प्रदर्शन का एक प्राचीन रूप है।
- बातचीत का कथानक और सामग्री लोकप्रिय पौराणिक कथाओं से खींची गई है।
- प्रदर्शन में मुख्य रूप से व्यंग्य, वाक्य, दर्शन पदों और हास्य से युक्त पात्रों के बीच एक अभद्र बहस होती है।
- यक्षगान प्रदर्शन के विपरीत, ताल–मड्डले में, कलाकार बिना किसी वेशभूषा के एक जगह पर बैठते हैं और चुने गए एपिसोड के आधार पर अपने वक्तृत्व कौशल का परीक्षण करने में संलग्न होते हैं।
- यदि संगीत यक्षगान प्रदर्शन और 'ताल–मादल' दोनों के लिए सामान्य है, तो बाद वाले ने बिना किसी नृत्य या वेशभूषा के केवल शब्द बोला है।
- इसलिए यह कला रूप, नृत्य, वेशभूषा एवं मंच का सम्मेलन है।

नैमिषा 2020

समाचार –

- यह प्रतिभागियों एवं कला के प्रति उत्साही लोगों को कलाकारों को बनाने और सीखने का मौका प्रदान करने की एक पहल है।
- कार्यक्रम में पेंटिंग, मूर्तिकला, प्रिंटमेकिंग और इन्द्रजाल (एक अंतःविषय रचनात्मक कार्यशाला) पर ऑनलाइन कार्यशाला सत्र शामिल हैं।
- नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (एनजीएमए) द्वारा आयोजित।
- कार्यक्रम से चयनित कलाकृतियों की प्रदर्शनी एनजीएमए के सांस्कृतिक मीडिया प्लेटफॉर्म सोहम पर प्रदर्शित की जाएगी।

सामान्य अध्ययन I
(भारतीय धरोहर एवं संस्कृति, विश्व एवं समाज का इतिहास एवं भूगोल)

कोडुमानल महापाषाण कालीन स्थल

समाचार –

- हाल ही में 'राज्य पुरातत्त्व विभाग, चेन्नई ने तमिलनाडु के इरोड जिले में कोडुमानल खुदाई स्थल से 250 केयर्न–सर्कल की पहचान की है।
- पहली बार किसी कब्र स्थल पर 10 से अधिक बर्तन तथा कटोरे की खोज की गई है।
- सामान्य रूप से किसी कब्र स्थल पर तीन या चार बर्तन मिलते हैं।

प्रमुख बिंदु –

- केयर्न–सर्कल प्रागैतिहासिक पत्थरों की समानांतर रैखिक व्यवस्था होती है।
- मेगालिथ या 'महापाषाण' एक बड़ा प्रागैतिहासिक पत्थर है जिसका उपयोग या तो अकेले या अन्य पत्थरों के साथ संरचना या स्मारक बनाने के लिये किया गया है।
- महापाषाण या मेगालिथ शब्द का प्रयोग उन बड़ी पत्थर की संरचनाओं का उल्लेख करने के लिये किया जाता है जिनका निर्माण शवों को दफन किये जाने वाले स्थलों या स्मारक स्थलों के रूप में किया जाता था।

विवरण –

- पहले के खनन से यह पता चलता है कि यह स्थल ईसापूर्व पाँचवी शताब्दी से लेकर पहली शताब्दी तक व्यापार एवं उद्योग का मुख्य केंद्र रहा था जैसा कि संगम साहित्य के ग्रंथ पाथिन्नुपथ्थु में लिखा गया है।
- यह तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित एक गाँव है।
- यह स्थल एक महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है।
- यह कावेरी की सहायक नदी नॉयल नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित है।

मृत्यु के बाद के जीवन संबंधी अवधारणा में विश्वास –

- पत्थरों की अधिक संख्या तथा पत्थरों के बड़े आकार से यह पता चलता है कि यह कब्र एक ग्राम प्रधान या समुदाय के प्रमुख की हो सकती है।
- इससे मेगालिथिक संस्कृति में दफनाने के बाद अपनाई जाने वाली अनुष्ठान प्रक्रिया तथा मृत्यु के बाद के जीवन संबंधी अवधारणा का पता चलता है।
- ऐसा हो सकता है कि लोगों का ऐसा विश्वास हो कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद एक नया जीवन मिलता है, अतरू कक्षों के बाहर अनाज एवं अनाज से भरे कटोरे रखे गए थे।
- आयताकार कक्षनुमा ताबूत (एक पत्थर से निर्मित छोटे ताबूत जैसा बॉक्स) पत्थर के फलकों से बना होता है तथा पूरी कब्र को पत्थरों से घेरकर बनाया जाता है।

मेगालिथिक संस्कृति –

- दुसरी शताब्दी ईसापूर्व तक प्रायद्वीप का उपरी भाग मेगालिथिक निर्माताओं द्वारा बसाया गया था।
- एक जानवर की खोपड़ी, मोती, ताम्र गलाने वाली इकाइयाँ, एक कार्यशाला की मिट्टी की दीवारें, कुम्हार के बर्तन, तमिल ब्राह्मी लिपि के लेख,
- कोडुमानल के पूर्व में किये गए उत्खनन कार्यों से पता चला है कि इस ग्राम में बहु–जातीय समूह निवास करते थे।
- यह स्थल 5 वीं शताब्दी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक एक व्यापार–सह–औद्योगिक केंद्र था।

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020

समाचार –

- विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) 2020 का 12 वां संस्करण जारी किया गया है।
- हालिया सूचकांक में भारत ने 168 वीं रैंक हासिल की, जबकि 2018 में इसकी रैंक 177 वीं थी।

मुख्य विचार –

- ईपीआई इंडेक्स 2020 ने 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन को मापा।
- सूचकांक ने पर्यावरणीय प्रदर्शन के 32 संकेतकों पर विचार किया और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय प्रदर्शन में 10 साल के रुझान को शामिल किया।
- डेनमार्क 82.5 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा।
- भारत ने 2020 ईपीआई सूचकांक में 100 में से 27.6 स्कोर किया और इसका प्रदर्शन अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में खराब था।
- भारत ने पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर सभी पाँच प्रमुख मापदंडों पर क्षेत्रीय (दक्षिण–एशिया) औसत स्कोर से नीचे स्कोर किया, जिसमें वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और पेयजल, भारी धातु और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं।
- ये निष्कर्ष विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा प्रकाशित 'इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट फॉर फिगर्स' द्वारा उठाए गए चिंताओं के साथ प्रतिध्वनित हुए।
- इसने जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से संबंधित मापदंडों पर क्षेत्रीय औसत से भी नीचे चला गया है।
- दक्षिण–एशिया के देशों के बीच 'जलवायु परिवर्तन' पर पाकिस्तान के बाद भारत दूसरे स्थान पर था।
- जलवायु परिवर्तन श्रेणी के तहत पाकिस्तान का स्कोर (50.6) सबसे अधिक था।

महत्व –

- सूचकांक में दस वर्ष की तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट से पता चला है कि भारत जलवायु से संबंधित मापदंडों पर फिसल गया है।
- रिपोर्ट ने संकेत दिया कि प्रति वर्ष दस वर्षों में ब्लैक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ग्रीनहाउस उत्सर्जन में वृद्धि हुई है।

आगे का रास्ता –

- भारत को सभी मोर्चों पर राष्ट्रीय स्थिरता प्रयासों को फिर से दोगुना करने की आवश्यकता है।
- इसे स्थिरता के मुद्दों की एक व्यापक स्पेक्ट्रम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, हवा और पानी की गुणवत्ता, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए एक उच्च प्राथमिकता के साथ।

ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020

समाचार –

- यूनेस्को द्वारा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 जारी की गई है।
- यह रेखांकित किया गया कि कोविड–19 ने दुनिया भर में शिक्षा प्रणालियों में असमानताओं को बदतर कर दिया था।

मुख्य निष्कर्ष –

- अप्रैल 2020 में स्कूल बंद होने के दौरान दुनिया भर के लगभग 91% छात्र स्कूल से बाहर थे।
- निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों के लगभग 40% ने इस संकट के दौरान गरीबों, भाषाई अल्पसंख्यकों और विकलांग लोगों जैसे बहिष्कार के जोखिम पर शिक्षार्थियों का समर्थन नहीं किया है।
- गरीब देशों ने, कम आय वाले 55%, निम्न–मध्यम–आय के 73% और ऊपरी–मध्यम–आय वाले देशों के 93% ने रेडियो और टेलीविजन (टीवी) पाठ, को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों के रूप में चुना।
- इन सभी देशों ने कक्षा निर्देश के लिए कम या अधिक अपूर्ण विकल्प की पेशकश की।
- निम्न और मध्यम आय वाले देशों के 17% अधिक शिक्षक भर्ती करने की योजना बना रहे हैं, 22% कक्षा का समय बढ़ाने के लिए और 68% उपचारात्मक कक्षाओं को लागू करने के लिए जब स्कूल स्थिति से निपटने के लिए फिर से खुलते हैं।
- भारत ने शैक्षिक निरंतरता के लिए सभी तीन प्रणालियों (रेडियो, टीवी और ऑनलाइन प्लेटफार्मों) के मिश्रण का उपयोग किया है।

आगे की चुनौतियां –

- सरकारें तेजी से प्रौद्योगिकी पर भरोसा करती हैं लेकिन डिजिटल विभाजन दृष्टिकोण को सीमित करता है।
- भारत में परीक्षाओं को रद्द करने से छात्रों के शिक्षकों के निर्णयों पर निर्भर स्कोरिंग हो सकता है, जो कुछ प्रकार के छात्रों के रूढ़ियों से प्रभावित हो सकता है।
- उच्च ड्रॉप–आउट दरें भी एक चिंता का विषय हैं।

- स्कूल का बंद रहना विभिन्न वंचित छात्रों के लिए सहायता तंत्र में बाधा उत्पन्न की है।

विश्लेषण –

- कोविड–19 महामारी ने दुनिया भर में शिक्षा प्रणालियों में असमानताएं बढ़ाई हैं।
- जूम, व्हाट्सएप और स्काइप पर कक्षाएं छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए आदर्श बन रही हैं। फिर भी, ऑनलाइन के लिए यह अचानक परिवर्तन कक्षा के अनुभव की अनुपस्थिति के लिए मुश्किल से भरपाई करता है।
- कुछ माता–पिता ऐसे हैं जो स्वयं प्रौद्योगिकी के साथ सहज नहीं हैं। इसलिए, उनके बच्चे भी इसे नकारात्मक रूप से देख सकते हैं। कई बार इंटरनेट की समस्या के कारण कक्षाएं गड़बड़ा जाती हैं।
- एकल परिवारों में, विशेष रूप से, माता–पिता को अपने बच्चों की देखभाल के लिए काम करने से चूकना पड़ सकता है।
- उनमें से कुछ स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर हो सकते हैं, जिन्हें महामारी को कम करने की सख्त जरूरत है। शिक्षकों पर भी दबाव है।
- बड़े पैमाने पर, महत्वपूर्ण परीक्षाओं का संचालन करना, हालांकि, अधिक जटिल होगा। अधिकांश बोर्ड और प्रवेश परीक्षाएं या तो स्थगित या निलंबित कर दी गई हैं, जिससे शैक्षणिक कैलेंडर में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
- जो छात्र अगले वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए स्लेटेड हैं, उदाहरण के लिए, पहले ही अनुदेशात्मक समय खो चुके हैं।
- इस बीच, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से लाखों, खासकर ग्रामीण इलाकों में, तालाबंदी के कारण शिक्षा तक पहुंच भी नहीं होगी।
- भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक के अनुसार, 2017–18 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर, 15% से कम ग्रामीण भारतीय घरों में इंटरनेट है (42% शहरी भारतीय घरों के विपरीत)। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 13% लोगों का सर्वेक्षण किया (पांच वर्ष से ऊपर) – सिर्फ 8.5% महिलाएं – इंटरनेट का उपयोग कर सकती हैं।
- सबसे गरीब घरों में एक स्मार्टफोन या एक कंप्यूटर नहीं हो सकता है।
- सरकारें, गैर सरकारी संगठन और अन्य सार्वजनिक–निजी संगठन इस गंभीर कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।
- जो शिक्षक अब तकनीक से भयभीत हैं, उन्हें अपने सींगों से बैल को निकालना होगा। पारंपरिक कक्षा में योजना और शिक्षण में कुशल होने वाले कई लोगों के लिए, ऑनलाइन सेटिंग की योजना के लिए कुछ फिर से सीखने की आवश्यकता होती है।

आगे की राह –

- सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए फोन डेटा और फोन पर सब्सिडी देने की आवश्यकता है। इसे जल्द से जल्द करने के लिए एक जोरदार धक्का देने की जरूरत है।
- थिंकजोन, ओडिशा का एक स्टार्टअप, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर), शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) और रेडियो का उपयोग कर रहा है ताकि घर में बिना इंटरनेट का उपयोग किया जा सके।
- इसने तीन से 10 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण मॉड्यूल प्रसारित करने के लिए एक स्थानीय रेडियो चैनल के साथ भागीदारी की है।
- गतिविधियां ओडिया, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं।
- देश में स्कूल बंद होने के निहितार्थ केवल शिक्षा के बारे में ही नहीं हैं बल्कि इसके और भी कई आयाम हैं।
- एक अभूतपूर्व सामाजिक आपदा से बचा जा सकता है अगर अधिक से अधिक – सरकारी और निजी संस्थाएँ – इन बच्चों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक भविष्य में इस डिजीटल डिवाइड से बचाए।

व्याभिचार –

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के फैसले की समीक्षा करने से इंकार कर दिया है, जो व्यभिचार का निरापराधीकरण करता है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पांच–न्यायाधीश की समीक्षा पीठ ने संविधान पीठ के सितंबर 2018 के फैसले को बरकरार रखा, जिसने व्यभिचार को दंडात्मक कानून की किताब से बाहर कर दिया था।

IPC धारा 497 क्या है? –

- IPC की धारा 497 के अनुसार, किसी पुरुष का विवाहित महिला के साथ अपने पति की सहमति के बिना संभोग करना दंडनीय अपराध है।
- ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को पांच साल या उससे अधिक की कैद होगी और जुर्माना देने के लिए भी कहा जा सकता है।
- भारत में, व्याभिचार हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा 13 (1) के तहत तलाक के लिए एक आधार था।
- 1971 में भारतीय विधि आयोग की 42 वीं रिपोर्ट और 2003 की आपराधिक कानून सुधारों की मलिमथ समिति ने व्यभिचार कानून में संशोधन की सिफारिश की।
- दोनों रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि आईपीसी की धारा 497 को लिंग–तटस्थ बनाया जाना चाहिए।

संबंधित चिंताएँ –

- इस कानून के बारे में एक बड़ी चिंता यह थी कि यह लिंग–तटस्थ प्रतीत नहीं होता है।
- धारा 497 किसी महिला को अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में सक्षम नहीं बनाती है जब उसने किसी अन्य महिला के साथ संभोग किया हो।
- धारा 49 एक विवाहित महिला को अपने पति के 'संपत्ति' के रूप में मानती है।
- यह प्रावधान 150 साल पहले प्रचलित पुरुषों के सामाजिक प्रभुत्व का प्रतिबिंब है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय –

- 2018 में फैसला केरल निवासी जोसेफ शाइन द्वारा दायर याचिका पर आधारित था, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता कालेश्वरम् राज ने किया था।
- मूल निर्णय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली एक संविधान पीठ द्वारा किया गया था जिसने पाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 (व्याभिचार) दंडात्मक दंड के भय से एक–दूसरे के प्रति वफादार रहने के लिए विवाहित जोड़ों को 'आदेश' नहीं दे सकती है।
- अदालत ने तर्क दिया था कि दावों का समर्थन करने के लिए कोई डेटा नहीं था कि व्यभिचार को अपराध के रूप में समाप्त करने के परिणामस्वरूप 'यौन नैतिकता में अराजकता' या तलाक की वृद्धि होगी।
- न्यायाधीशों ने कहा कि धारा 497 पुरानी लगती है। वास्तव में, यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता प्रतीत होता है।
- व्याभिचार विवाह के विघटन सहित नागरिक मुद्दों के लिए आधार हो सकता है लेकिन यह एक अपराध नहीं हो सकता है।

- खंडपीठ ने यह भी कहा था कि सीआरपीसी की धारा 198 (2), जिसने व्यभिचारी पति को अपनी पत्नी के प्रेमी के खिलाफ मुकदमा चलाने का विशेष अधिकार दिया था, प्रकट रूप से सीआरपीसी की धारा 198 (2) मनमाना था।

व्याभिचार की निरपराधीकरण की हानियाँ –

- यह परिवारों में संघर्षों के लिए अग्रणी गैर–वैवाहिक मामलों को प्रोत्साहित करेगा।
- इससे तलाक की संख्या अधिक हो सकती है।
- पत्नी और पति के बीच अलगाव के मामले में बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- कुछ विशेषज्ञ सोचते हैं कि यह भारत में विवाह और संस्कृति की प्राचीन संस्था को नष्ट कर देगा क्योंकि यह पश्चिमीकरण को बढ़ावा देता है।

सामान्य अध्ययन II
(गवर्नेंस, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय, एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

भारत एवं ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन

समाचार –

- हाल ही में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच पहले वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के साथ कई अन्य महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु –

- भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच जून 4, 2020 को एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
- इस अवसर पर दोनों देशों की तरफ से 'हिंद–प्रशांत समुद्री सहयोग के लिये साझा दृष्टिकोण' नामक एक संयुक्त दस्तावेज जारी किया गया।
- इस सम्मेलन में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।
- साथ ही दोनों देशों के बीच प्रधानमंत्री स्तर की बैठकों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई।

समझौते –

'म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट' –

- इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिये सैन्य अभ्यास एवं साझा गतिविधियों में वृद्धि के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में सहयोग को व्यापक तथा मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की।
- इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों की सेनाएँ एक दूसरे के सैन्य अड्डों का परस्पर प्रयोग कर सकेंगी।
- इससे पहले भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वर्ष 2016 में ऐसे ही एक समझौते 'लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर कर चुका है।
- साथ ही भारत द्वारा कुछ अन्य देशों फ्राँस, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया के बीच ऐसे ही समझौते पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।

व्यापक रणनीतिक साझेदारी –

- इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच वर्ष 2009 की द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में स्थापित किया गया है।
- इसके तहत दोनों देशों द्वारा '22 वार्ताओं' को सचिव स्तर से आगे ले जाते हुए मंत्री स्तर तक बढ़ाया गया है।
- इसके बाद अब दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्री कम–से–कम हर दूसरे वर्ष मिलकर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
- वर्तमान में भारत एवं क्वाड के अन्य दो सदस्यों (USA एवं जापान) के साथ पहले से ही मंत्रिस्तरीय 22 वार्ता की व्यवस्था लागू है।
- भारत ने अब तक यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, वियतनाम एवं संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ ैब्च समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया तीन देशों चीन, इंडोनेशिया एवं सिंगापुर के साथ ैब्च समझौते का हिस्सा है।

ऑस्ट्रेलिया–भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष –

- दोनों पक्षों ने कोविड–19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने एवं अन्य साझा प्राथमिकताओं पर भी कार्य करने के लिये 'ऑस्ट्रेलिया–भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष' के तहत सहयोग बढ़ाने पर बल दिया।
- AISRF की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी, यह कोष भारत एवं ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों पर सहयोग हेतु सहायता प्रदान करता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग –

- इस सम्मेलन में दोनों पक्षों के बीच 'साइबर एवं साइबर–सक्षम महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग पर रूपरेखा व्यवस्था' समझौते के तहत डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा एवं अन्य महत्त्वपूर्ण एवं नवीन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की।
- महत्त्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों का खनन एवं प्रसंस्करण –
  – दोनों पक्षों के बीच महत्त्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों के खनन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
  – इस समझौते के तहत दोनों देशों ने खनिजों के अन्वेषण एवं निष्कर्षण के लिये आवश्यक नवीन तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग करने की सहमति व्यक्त की है।

कृषि क्षेत्र में सहयोग –

- इस सम्मेलन में दोनों पक्षों ने भारत एवं ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व को स्वीकार किया।
- दोनों पक्षों ने फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान एवं कृषि लागत को कम करने के लिये अनाज के प्रबंधन जैसे मुद्दों पर संयुक्त कार्यवाही करने की बात कही।
- साथ ही इस सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों के बीच 'जल संसाधन प्रबंधन पर एक समझौता ज्ञापन'

व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता –

- इस सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2015 से स्थगित भारत–ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता को पुनः शुरू किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

- ज्ञातव्य है कि यह निर्णय तब लिया गया है जब हाल ही में भारत ने आसियान (ASEAN) के नेतृत्व में बने 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' मुक्त व्यापार समझौते से अलग होने का निर्णय लिया है।

अन्य समझौते –

- लोक प्रशासन एवं शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लाभ –

- कोविड–19 महामारी के दौरान भी भारत एवं ऑस्ट्रेलिया द्वारा द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन को विलंबित न करने का निर्णय दोनों देशों के मजबूत संबंधों एवं परस्पर सहयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- रक्षा क्षेत्र में हुए महत्त्वपूर्ण समझौते न सिर्फ दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग में वृद्धि करेंगे बल्कि यह हिंद–प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में दोनों पक्षों की समान विचारधारा को भी मजबूती प्रदान करेगा जिससे इस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।
- खनिज पदार्थों से जुड़े समझौते के माध्यम से भारत को ऑस्ट्रेलिया से दुर्लभ मृदा धातुओं की आपूर्ति संभव हो सकेगी।
- हालाँकि इस सम्मेलन में हाल के दिनों में चीन की बढ़ती आक्रामकता एवं 'मालाबार नौसैनिक अभ्यास' में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने पर कोई चर्चा नहीं की गई।

आगे की राह –

- इस सम्मेलन के दौरान भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा क्षेत्र में हुआ समझौता दोनों देशों के 'एक खुले, स्वतंत्र, समावेशी एवं कानून आधारित हिंद–प्रशांत क्षेत्र' की विचारधारा को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- वर्तमान में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की मजबूती का लाभ उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया से आने वाले निवेश में वृद्धि किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

भारत ने 2021–22 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गैर–स्थायी सदस्य बना –

समाचार –

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर–स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी 55–सदस्यीय एशिया–प्रशांत समूह द्वारा समर्थित थी।
- वैश्विक शांति और सुरक्षा की अपनी खोज में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद में नेतृत्व किया है।
- भारत 1950–51 के बाद से सात बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर–स्थायी सदस्य रहा है।
- कुछ महत्वपूर्ण कारणों से, भारत ने 2021–22 के लिए अपनी उम्मीदवारी का पीछा करने का फैसला किया, अन्यथा, रोटेशन से, यह सीट केवल 2030 के दशक में भारत पहुंच गई।

कारण –

- भारत द्वारा निभाई गई अनूठी भूमिका – वर्तमान परिदृश्य में, स्थायी सदस्यों के बीच लगभग पूर्ण ध्रुवीकरण है, जिसमें एक तरफ यू.एस., और फ्रांस और दूसरी तरफ रूस ओर चीन हैं।
- भारत की दोनों पक्षों के साथ काम करने की क्षमता UNSC के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखती है।
- **भावनात्मक मूल्य** – वर्ष 2022, भारतीय स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष और UNSC में एक स्थान नियोजित समारोहों में शामिल होगा।
- **सामरिक चिंताएं** – भारत ने हाल ही में चीन, अमेरिका और पाकिस्तान से कई व्यापार और सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इसके निवारण के लिए अपनी चिंताओं को दूर करने में सक्षम होगा। इसके अलावा, भारत 2022 में नई दिल्ली में जी–20 बैठक की मेजबानी करेगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद –

- सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्य राज्यों के लिए सिफारिशें करते हैं, केवल सुरक्षा परिषद के पास निर्णय लेने की शक्ति है कि सदस्य राज्यों को चार्टर के तहत लागू करने के लिए बाध्य किया जाता है।
- इसमें 15 सदस्य हैं (स्थायी सदस्य के रूप में 5 और गैर–स्थायी सदस्य के रूप में 10), और प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट है।
- पांच स्थायी सदस्य – चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य।
- स्थायी सदस्यों में से प्रत्येक के पास यूएनएससी के प्रत्येक निर्णय पर वीटो पावर है।
- संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में UNSC का स्थायी निवास।
- परिषद की अध्यक्षता मासिक रूप से घूमती है, जो सदस्य राज्यों के बीच वर्णानुक्रम में चलती है।

गैर–स्थायी सदस्य कैसे चुने जाते हैं?

- प्रत्येक वर्ष महासभा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए पांच गैर–स्थायी सदस्यों (कुल में से 10 में से) का चुनाव करती है।
- 10 गैर–स्थायी सीटों को क्षेत्रीय आधार पर निम्नानुसार वितरित किया जाता है – अफ्रीकी और एशियाई राज्यों के लिए पांच, पूर्वी यूरोपीय राज्यों के लिए एक, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन राज्यों के लिए दो और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए दो।

UNSC के गैर–स्थायी–सदस्यों की शक्तियाँ –

- सुरक्षा परिषद मे कोई भी फैसला तब तक पास नही होता है जब तक कि इसके सात गैर–स्थायी सदस्यों में से कम से कम एक उस फैसले के सर्मथन में ना हो, बावजुद इसके कि स्थायी सदस्यों का रूख क्या है।
- एक गैर–स्थायी सदस्य परिषद की मासिक अध्यक्षता के माध्यम से सुरक्षा परिषद के काम को प्रभावित कर सकता है। सुरक्षा परिषद की कुर्सी का परिषद के मासिक कार्यक्रम को आकार देने में प्रभाव होता है। इसे संगठनात्मक प्रकृति की कई शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।
- गैर–स्थायी सदस्य अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों और विषयगत मुद्दों के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- गंभीर राजनीतिक संकटों के दौरान गैर–स्थायी सदस्यों का महत्व भी बढ़ जाता है, जिसके दौरान स्थायी सदस्य एकमत स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, लेकिन जहां उनके बीच के मतभेद परिषद के काम को पूरी तरह से पंगु बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- अनौपचारिक बैठकों के दौरान सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करने से गैर–स्थायी सदस्यों को अपने हितों की रक्षा करने और उन मुद्दों को रखने का मौका मिलता है जो बातचीत के दस्तावेजों के भीतर उनके लिए महत्वपूर्ण हैं।

- हाल के वर्षों में, गैर–स्थायी सदस्यों ने न केवल दस्तावेजों की सामग्री पर बातचीत की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्होंने समाधान के लिए अपने स्वयं के प्रस्ताव पेश करना भी शुरू कर दिया है।

महत्व –

- यह घटना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान और चीन, दोनों देश जिनके साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत की कूटनीतिक चुनौतियां हैं।
- अगले चरण में, भारत को अंततः UNSC पर गैर–स्थायी सीट जीतने के लिए 193 संयुक्त राष्ट्र महासभा के दो–तिहाई सदस्यों के वोट की आवश्यकता होगी।
- यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की खोज सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और वैध आकांक्षा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव में अपनी सही भूमिका निभा सके।
- इसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकता है –
- भारत संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के मुद्दे को उठाने वाले पहले देशों में से एक था और 1965 में सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन के लिए शुरुआती हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था।
- संयुक्त राष्ट्र में भारत का परमाणु सिद्धांत वैश्विक निरस्त्रीकरण प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
- भारत, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन की मांग करने वाला एकमात्र परमाणु संपन्न राज्य है।
- पिछले 50 वर्षों में शांति निर्माता के रूप में भारत की पहचान सुरक्षा परिषद के विभिन्न मिशनों में भारतीय सेना के सक्रिय योगदान से बनी है।
- भारत के पास विभिन्न लॉंच व्हिकल्स को बनाने के साथ स्वतंत्र तौर पर उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने एवं कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है।
- भारत के पास सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए चार देशों फ्रांस, रूस, युके एवं युएस का सर्मथन प्राप्त है।

जी 7 स्थगित और इसका विस्तार

समाचार –

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया और दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों के समूह 'जी–7' के वर्तमान विन्यास को 'पुराना' कह कर खारिज कर दिया।
- उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को जोड़कर इसे जी–11 बनाना चाहता है।

अन्य देशों की स्वीकृति –

- भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने निमंत्रण का स्वागत किया है। 2014 में क्रीमिया के संबंध में समूह की सदस्यता खो चुकी रूस ने कहा कि 'वह सदस्य बनना पसंद करेगा यदि समान व्यवहार किया जाता है'।
- प्रस्तावित जी–11 समूहीकरण दुनिया के सबसे अमीर देशों में भारत की जगह को मान्यता देगा, और इसकी वैश्विक आवाज को स्वीकार करेगा।
- हालांकि, भारत सरकार को कुछ ऐसे कारकों के साथ प्रस्तावित लाभों को तौलना चाहिए जो अभी भी अस्पष्ट हैं।
- मेजबान के रूप में, यूएसए किसी भी देश को जी–7 में आमंत्रित कर सकता है, लेकिन इसकी संरचना को बदलने के लिए अन्य सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- पहले से ही, रूस पर कुछ चिंताएं हैं, जो पूरी जी–11 योजना को पटरी से उतार सकती हैं, जिससे नई दिल्ली द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय जल्दबाजी वाला साबित हो सकता है।

अमेरिका–चीन संबंध – एक नया COLD WAR

- 16 जून 2020 से चीन के यात्री विमानों को प्रतिबंधित करने के लिए अमेरिकी सरकार का निर्णय देश की उड़ानों को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए चीन के इनकार के जवाब के रूप में था।
- एक व्यापार युद्ध जिसे यूएसए ने 2018 में शुरू किया था, अभी तक पूरी तरह से हल नहीं किया गया है।
- हाल के महीनों में, संयुक्त राष्ट्र ने कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए चीन पर हमला किया था।
- अमेरिका ने विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पेश करने के बीजिंग के कदम के विरोध में हांगकांग के विशेष व्यापार की स्थिति को समाप्त करने का भी फैसला किया है।
- वाशिंगटन और बीजिंग के काउंटर चालों द्वारा चीन को बार–बार निशाना बनाने से ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने एक नए शीत युद्ध में प्रवेश किया है।
- इस तरह के विवादों को बातचीत और सहयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है।
- व्यापार और प्रौद्योगिकी से लेकर महामारी और हांगकांग तक युद्ध की रेखाएँ खींची गई हैं।
- चीन और अमेरिका के बीच संबंध अभी भी उतने बुरे नहीं हैं जितने सोवियत संघ और अमेरिका के बीच थे।
- बीजिंग और वाशिंगटन अभी भी आर्थिक रूप से उलझे हुए हैं।
- दुनिया दो वैचारिक धर्मांधों (पूंजीवाद बनाम साम्यवाद) में विभाजित नहीं है, जैसा कि शीत युद्ध के दौरान हुआ था। सैन्य टकराव की संभावना बहुत कम है।

G7 का विवरण

- 1970 के दशक की शुरुआत में समृद्ध लोकतंत्रों के एक प्रतिबंधित क्लब के रूप में उभरा।
- 1973 अरब–इजरायल युद्ध के ठीक बाद तेल की कीमतें चौगुनी हो गईं।
- पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के सदस्यों ने कनाडा, जापान, नीदरलैंड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ प्रतिबंध लगाया, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को झटका दिया।
- हालाँकि, फ्रांस ने हालात संभाल लिए, लेकिन ओपेक कार्रवाई की सर्द हवाएं दुनिया भर में फैल गईं।
- फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के सबसे विकसित सदस्यों में से पांच के वित्त मंत्रियों को आमंत्रित किया।
- वैश्विक मुद्दों पर अनौपचारिक चर्चा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली एवं यूनाइटेड किंगडम शामिल हुए।
- यह अगले वर्ष से सरकार के प्रमुखों के जी7 शिखर सम्मेलन में बदल गया, जिसमें कनाडा (1976), एवं 1977 में यूरोपीय आयोग / समुदाय (बाद में संघ) को शामिल किया गया था।
- अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पहल पर टोनी ब्लेयर, जी 7 जी 8 बन गया, 1998 में रूसी संघ क्लब में शामिल हो गया।

- 2014 में क्रीमिया की घोषणा के बाद रूस के निष्कासन के साथ यह समाप्त हो गया।
- जब गठित किया गया, तो जी 7 देशों ने वैश्विक जीडीपी के दो–तिहाई के लिए जिम्मेदार था।

जी 7 की सीमाएँ –

- बहुपक्षीय संस्थानों की सफलता इस बात से आंकी जाती है कि उन्होंने उस समय की प्रमुख वैश्विक या क्षेत्रीय चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है या नहीं।
- जी 7, 2007–08 के आर्थिक मंदी का सामना करने में विफल रहा, जिसके कारण जी 20 का उदय हुआ।
- अपने अस्तित्व के कम समय में, जी 20 ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली के पतन को रोकने के लिए, खुले बाजारों एवं प्रोत्साहन को बढ़ावा देकर आत्मविश्वास की एक झलक प्रदान की है।
- जी 7 ने समकालीन मुद्दों, जैसे कि कोविड–19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, दाएश चुनौती एवं पश्चिम एशिया राज्य के पतन के संकटों का सामना अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार नहीं किया है।
- इसने घोषणा की थी कि इसके सदस्य सभी जीवाश्म ईंधन एवं सब्सिडी को समाप्त कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा करने की किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है।
- जी 7 देशों में 59% ऐतिहासिक वैश्विक CO_2 उत्सर्जन ("1850 से 2010 तक") है, एवं उनके कोयले से भरे संयंत्र पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की तुलना में 'दागुना अधिक CO_2' उत्सर्जित करते हैं।
- जी 7 देशों में से तीन, फ्रांस, जर्मनी एवं यूके, शीर्ष 10 देशों में से एक थे, जो दाएश में स्वयंसेवकों का योगदान दे रहे थे, जिनकी संख्या दो साल पहले 22,000–30,000 विदेशी सेनानियों के बीच थी।
- ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद से किसी भी समय पश्चिम एशिया उथल–पुथल की स्थिति में है। इससे एक प्रवासी संकट पैदा हो गया है जिसने यूरोप के कई देशों को अपने पश्चिमी उदारवादी मूल्यों पर कुठाराघात करने के लिए राजी कर लिया।
- इसने भूमध्य सागर को उत्पीड़न एवं अपने जीवन के लिए खतरे के डर से भागने वाले लोगों के लिए मौत का जाल बना दिया।
- चीन के साथ अपनी सीमा के तनाव के बावजूद, भारत को अमेरिका एवं चीन के बीच एक नए शीत युद्ध की संभावना को देखते हुए समूह में शामिल होने के अपने उद्देश्यों पर विचार करना चाहिए।
- अंत में, एक बहुपक्षीय मंच के रूप में जी–7 की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, करना आवश्यक है, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा योगदान, ईरान आदि मुद्दों पर गहन सदस्य मतभेद के चलते अपने 45 वर्ष के इतिहास में पिछले साल फ्रांस में, समूह एक संयुक्त संवाद जारी करने में असमर्थ था।
- भारत वैश्विक मंच पर अपनी जगह के लिए योग्य है, लेकिन इसे जी–11 में शामिल होते समय अपने उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए।

वंशधारा नदी की भौगोलिक अवस्थिति

समाचार –

- वर्ष 2009 से आंध्रप्रदेश तथा ओडिशा राज्य के मध्य उत्पन्न 'वंशधारा जल विवाद' के समाधान को लेकर शीघ्र ही आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा ओडिशा सरकार से वार्ता की बात की गई है।

प्रमुख बिंदु –

- वर्तमान आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र ही वंशधारा एवं नागावल्ली नदी की इंटर–लिंकिंग को भी पूरा किया जाना तथा 'मड्डुवालासा परियोजना' का भी विस्तार किये जाने की योजना बनायी जा रही है।
- मड्डुवालासा परियोजना आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक मध्यम सिंचाई परियोजना है।
- इस परियोजना का जलग्रहण क्षेत्र श्रीकाकुलम एवं विजयनगरम दो जिलों में फैला हुआ है।
- इस परियोजना के जलाशय के लिये पानी का मुख्य स्रोत सुवर्णमुखी नदी की सहायक नदी नागवल्ली नदी में एक इंटरलिंक बनाकर की जा रही है।

विवाद की पृष्ठभूमि –

- ओडिशा राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2009 में 'अंतरराज्यीय नदी जल विवाद' अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत वंशधारा नदी जल विवाद के समाधान के लिये अतंर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण के गठन के लिये केंद्र सरकार को एक शिकायत दर्ज की गई थी।
- ओडिशा सरकार का पक्ष था कि आंध्र प्रदेश के कटरागार में वंशधारा नदी पर निर्मित तेज बहाव वाली नहर के निर्माण के कारण नदी का विद्यमान तल सूख जाएगा जिसके परिणामस्वरूप भूजल एवं नदी का बहाव प्रभावित होगा।
- दोनों राज्यों के मध्य उत्पन्न इस विवाद को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2009 में केंद्र सरकार को जल विवाद अधिकरण को गठित करने के निर्देश दिया अतः सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 में एक 'जल विवाद अधिकरण' का गठन किया गया।
- अधिकरण द्वारा दिये गया निर्णय के विरुद्ध वर्ष 2013 ओडिशा सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई जो अभी लंबित है।

नदी जल विवाद संबंधित संवैधानिक प्रावधान –

- सविधान का अनुच्छेद–262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है।
- इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा दो कानून पारित किये गए हैं –

नदी बोर्ड अधिनयम (1956) तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनयम (1956)

- अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनयम, केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बँटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित दो अथवा दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी विवाद के न्यायनिर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायाधिकरण के गठन की शक्ति प्रदान करता है।
- गठित न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा जो सभी पक्षों के लिये मान्य होगा।

वंशधारा नदी –

- यह नदी ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच प्रवाहित होती है।
- नदी का उद्गम ओडिशा के कालाहांडी जिले के थुआमुल रामपुर से होता है।

- लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह आंध्र प्रदेश के कालापटनम जिले से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है।

आगे की राह –

- विवाद के समाधान के लिये दोनों ही राज्यों को पहल करनी होगी तथा गठित जल विवाद न्यायाधिकरण एवं सर्वोच्च न्यायलय द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय को स्वीकार करना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त दोनों ही पक्षों को वंशधारा परियोजना के चरण–II के लाभ को भी समझना होगा जिसके चलते कम–से–कम दो लाख एकड़ भूमि को सिंचित किया गया है। राज्यों के आर्थिक विकास को पर्यावरण एवं किसानों के हित से भी जोड़ा जाना आवश्यक है।

आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं

समाचार –

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद–32 के तहत दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है।

प्रमुख बिंदु –

- याचिका में तमिलनाडु में मेडिकल पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण नहीं देने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
- याचिका में तमिलनाडु के शीर्ष नेताओं द्वारा वर्ष 2020–21 के लिये 'राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा' में राज्य के लिये आरक्षित सीटों में से 50% सीटें 'अन्य पिछड़ा वर्ग' हेतु आरक्षित करने के लिये केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय –

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद–32 के तहत एक याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में दायर की जा सकती है।
- आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अतः आरक्षण नहीं देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्त्ताओं को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान करते हुए याचिका वापस लेने को कहा है।

आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान –

- यद्यपि भारतीय संविधान के भाग–III के अंतर्गत अनुच्छेद 15 तथा 16 में आरक्षण संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया हैं।
- परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इन अनुच्छेदों की प्रकृति के आधार पर इन्हे मौलिक अधिकार नहीं माना है। इसलिये इन्हें लागू करना राज्य के लिये बाध्यकारी नहीं हैं।
- आरक्षण की अवधारणा आनुपातिक नहीं, बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर आधारित है, अर्थात् आरक्षण का लाभ जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध कराने की बजाय पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये है।

विभिन्न वर्गों के लिये आरक्षण की व्यवस्था –

- वर्तमान में सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिये 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिये 7.5%, अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 27% तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिये 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है ।

रिट की व्यवस्था –

- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को देश में न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों तथा संविधान के संरक्षण का दायित्व प्रदान किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता प्रदान की गई है ।
- इन अनुच्छेदों के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार–प्रच्छा आदि रिट जारी की जा सकती है।

उच्च न्यायालय में रिट की अनुमति क्यों? –

- उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है।
- उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट की सुनवाई से मना नहीं कर सकता जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय सुनवाई के लिये याचिका स्वीकार करने से मना कर सकता है क्योंकि अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है।

निर्णय का महत्त्व –

- चूँकि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है अतः आरक्षण के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत रिट स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है।
- निर्णय के बाद आरक्षण संबंधी मामलों में रिट याचिका सीधे सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालयों में लगानी होगी क्योंकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामले भी शामिल होते हैं।

मतपत्र की गोपनीयता

समाचार –

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मतपत्र की गोपनीयता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला है।
- मतदाता का चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए और मतपत्रों की गोपनीयता का सिद्धांत संवैधानिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण संकेत है।
- 2018 में उत्तर प्रदेश के एक जिला पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव के मतदान को अलग करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला आया।
- उच्च न्यायालय ने पाया कि पंचायत के कुछ सदस्यों ने मतपत्र की गोपनीयता के नियम का उल्लंघन किया था। यह निष्कर्ष सीसीटीवी फुटेज पर निर्भर था कि उन्होंने या तो मतपत्रों को प्रदर्शित किया था या उनके आचरण से पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से मतदान किया था।

गुप्त मतदान/ऑस्ट्रेलियाई मतपत्र –

- सीक्रेट बैलट 'मतदाता द्वारा वोट डालने की प्रक्रिया को इस तरह से संदर्भित करता है कि मतदाता के अलावा किसी को यह पता नहीं चलता कि किसके नाम पर वोट डाला गया है। इसका उद्देश्य राजनीतिक गोपनीयता के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- इसका उद्देश्य मतदाता को डराने–धमकाने, ब्लैकमेलिंग और संभावित वोट–खरीद द्वारा प्रभावित करने के प्रयासों को रोकना है।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय –

- न्यायमूर्ति खन्ना, जिन्होंने निर्णय लिखा, जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 94 का उल्लेख किया, जो मतदाता के विशेषाधिकार को उसकी/उसकी पसंद के बारे में गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है।
- मतदाताओं को मतपत्र की गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करना कानून की नीति है।
- यहां तक कि एक दूरस्थ यह भी है कि एक मतदाता को यह बताने के लिए मजबूर किया जा सकता है कि उसने किसके लिए मतदान किया है, यह सकारात्मक बाधा के रूप में होगा और मताधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता में कमी लाएगा।
- विशेषाधिकार समाप्त हो जाता है जब मतदाता विशेषाधिकार को त्यागने का फैसला करता है और स्वयंसेवकों को यह खुलासा करता है कि उसने किसे वोट दिया है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण

समाचार –

- सिक्किम में, राज्य मंत्रिमंडल ने उन लोगों की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अनुमति देने का फैसला किया जो एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षित श्रेणी में 10 प्रतिशत केंद्रीय आरक्षण में नहीं आते हैं।
- यह उन लोगों के एक वर्ग की एक लंबे समय से लंबित आकांक्षा थी, जो अखिल भारतीय सेवाओं सहित विशेष रूप से राज्य से बाहर रोजगार और शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने से संबंधित थे।
- यह आरक्षण वैज्ञानिक और तकनीकी पदों और अन्य ऐसे पदों पर लागू नहीं होगा जो केंद्रीय सेवाओं के दायरे से बाहर हैं।

शैक्षिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण –

- केंद्र सरकार ने 2019 में एक आदेश जारी किया, 2019 के 103 वें संशोधन अधिनियम को जोड़ते हुए, शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) में 10% आरक्षण प्रदान किया।
- इस आरक्षण का लाभ ईडब्ल्यूएस से संबंधित व्यक्तियों द्वारा लिया जा सकता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की मौजूदा योजनाओं में शामिल नहीं हैं।

सामान्य अध्ययन III

(तकनीक, आर्थिक विकास, जैवविविधता, पर्यावरण, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन)

असम गैस रिसाव की दुर्घटना

समाचार –

- हाल ही में असम के तिनसुकिया जिले में 'ऑयल इंडिया लिमिटेड' के बाघान गैस कुएँ में तेल रिसाव के बाद गैस रिसाव को रोकने के लिये सिंगापुर की एक फर्म को बुलाया गया।

प्रमुख बिंदु –

- दुर्घटना के बाद आसपास के गाँवों के लोगों की निकासी की गई परंतु अनेक प्रकार की मत्स्य प्रजातियों तथा लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन की मृत्यु हो गई है।
- सामान्यतः इस कुएँ से प्रतिदिन 2,700 पाउंड प्रति वर्ग इंच (PSI) दाब के साथ 80,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन (SCMD) गैस का उत्पादन किया जाता है। परंतु वर्तमान में गैस रिसाव दर 4,200 पाउंड प्रति वर्ग इंच (PSI) के दाब के साथ 90,000 मानक घन मीटर (SCMD) गैस प्रतिदिन है।

दुर्घटना का कारण –

- कुएँ में गैस के दबाव को यदि समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो कुएँ में अचानक आघात से विस्फोट हो सकता है।
- दुर्घटना के पीछे कई संभावित कारण जैसे– निरीक्षण की कमी, खराब रखरखाव, तकनीकी कारण आदि हो सकते हैं।

गैस रिसाव के नियंत्रण में समस्या –

- गैस रिसाव को नियंत्रण करना मुश्किल है क्योंकि गैस रिसाव का दबाव बहुत अधिक है। दूसरा गैस भंडार में नियंत्रण कार्य के दौरान किसी भी समय आग लगने की संभावना रहती है।
- इस प्रकार के गैस रिसाव में स्वतरू दबाव कम होने में कई महीनों का समय लगता है अतरू गैस के कुओं में पानी को पंप करना एक कारगर तरीका हो सकता है ताकि गैस में आग न लगे।

गैस रिसाव का प्रभाव –

- लगभग 2,500 से 3,000 लोगों की निकासी करके राहत शिविरों में भेजा गया है। गैस रिसाव से 'नदी डॉल्फिन' तथा अनेक प्रकार की मछलियों की मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने आँखों में जलन, सिरदर्द आदि जैसे लक्षणों की शिकायत की है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि पास में मगुरी–मोटापुंग वेटलैंड (Maguri-Motapung Wetland) है, जिसे एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया (Important Bird Area - IBA) गया है। लगभग 900 मीटर की हवाई दूरी पर डिब्रू–सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों तथा वन्य जीवों की कुछ दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

प्राकृतिक गैस (Natural Gas) –

- प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत है। प्राकृतिक गैस में कई अलग–अलग यौगिक होते हैं। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक मीथेन है। मीथेन के अलावा प्राकृतिक गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि भी पाए जाते हैं।

- इसका उपयोग उर्वरक, प्लास्टिक तथा अन्य व्यावसायिक रूप से महत्त्वपूर्ण कार्बनिक रसायनों के निर्माण, ताप विद्युत गृहों में किया जाता है।

परंपरागत प्राकृतिक गैस –
- जब प्राकृतिक गैस बड़े चट्टानीय रिक्त स्थान के बीच पाई जाती है तो इसे परंपरागत प्राकृतिक गैस कहा जाता है।

शेल गैस –
- जब प्रकृतिक गैस लघु चट्टानीय भागों, शेल, बलुआ पत्थर तथा अन्य प्रकार की अवसादी चट्टान के बीच छोटे छिद्रों (स्थानों) में पाई जाती है तो इसे शेल गैस के रूप में जाना जाता है।

संबंधित प्राकृतिक गैस –
- कच्चे तेल के भंडारों के साथ पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस को 'संबंधित प्राकृतिक गैस' कहा जाता है।

कोल–बेड मिथेन –
- जबकि कोयले के भंडार के साथ पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस को कोल–बेड मिथेन कहा जाता है।

असम के तेल उत्पादन क्षेत्र –
- अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। वर्ष 1956 तक असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। असम में डिगबोई, नहरकटिया तथा मोरान महत्त्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तमिलनाडु का पूर्वी तट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र में अन्य महत्त्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं।

गर्भवती हाथी की हत्या

समाचार –
- हाल ही में, केरल में, एक खाद्य बम के हानिकारक उपयोग के कारण एक गर्भवती हाथी की मौत हो गई, जिससे लोगों में व्यापक रोष रहा।
- भारत में हर साल हाथियों की बड़ी संख्या को मार दिया जाता है क्योंकि उनके रास्ते मनुष्यों को पार कर जाते हैं, लेकिन एक घातक घायल जानवर की छवि दिमाग पर अंकित रहेगी।

मानव–पशु संघर्ष –
- एक दुखद दुर्घटना मनुष्यों एवं जानवरों के बीच बढ़ते संघर्षों की याद दिलाती है जो केवल बढ़ते ही प्रतित होते हैं, क्योंकि वाणिज्यिक दबाव जानवरों के निवास स्थानों को खाते जा रहा हैं।
- भारत में संरक्षण की एक बड़ी विफलता यह है कि किसानों एवं जंगली जानवरों की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं।
- हाथियों की मौत के लिए अपराधियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन यह खो चुकी सीमाओं एवं अवरुद्ध गलियारे के बड़े मुद्दे को कम करने के लिए कम पड़ता है।
- भारत के पास हजारों हाथी हैं – केवल उपलब्ध गणना के अनुसार 30,000 से कुछ कम – लेकिन कोई भी मजबूत विज्ञान–आधारित नीति नहीं है जो नरम परिदृश्य एवं पलायन मार्ग को प्रोत्साहित करती है जो संघर्ष को कम करेगा।
- हाथियों के आवासीय स्थलों का सिकुड़ना गंभीर चिंता का कारण है, क्योंकि जानवर कॉफी, चाय एवं इलायची सम्पदा जैसे जंगलों से सटे नरम परिदृश्य की तलाश करते हैं।
- इनके अभाव में, वे अपने आंदोलन के रास्ते में पड़ने वाले खाद्य–समृद्ध खेतों में भटकते हैं।

चुनौतियां –
- बड़े शिकारियों के अनुपलब्ध होने एवं आसानी से सुलभ खाद्य फसलों, के कारण इन स्थानों पर हिरण, बंदर, सूअर एवं अन्य प्रजातियों की भारी उपलब्धता हो जाती है।
- भारत ग्रामीण लोगों को जानवरों का शिकार करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन उनकी संख्या के बढ़ने पर सरकार इनकी संख्या को नियमित नहीं करती है।
- जबकि सरकार के पास तेजी से बढ़ रहे जानवरों को 'वर्मिन' घोषित करके उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत नियंत्रित करने का प्रावधान हैं यद्यपि बहुत कम ही ऐसा किया जाता है।
- जब ऐसे फैसले लिए जाते हैं मुखर शहरी वन्यजीव कार्यकर्ता समूह आमतौर पर सोशल मीडिया तूफान पैदा करते हैं एवं अदालत में आदेश को चुनौती देते हैं। इन समूहों के पास उन किसानों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है जो हम सभी के लिए भोजन उगाने के दौरान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं।
- इन जानवरों द्वारा फसल के व्यापक विनाश को देखते हुए, किसानों को तत्काल सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है।
- मुआवजा योजनाएं समाधान का एक हिस्सा हैं, लेकिन भारत में यह हमेशा फसल के बाजार मूल्य का एक अंश होता है, जो पहले से ही कम है।
- गरीब किसान इसे पाने के लिए नौकरशाही प्रक्रियाओं को नेविगेट करने में बहुत समय बिताते हैं। एवं इस प्रक्रिया का कोई अंत नहीं है।
- संघर्ष की शुरुआत तब होती है जब पशु आंशिक रूप से कटहल एवं अन्य फसलों/फलों के कारण मानव निवास में प्रवेश करते हैं।

आगे की राह –
- लैंडस्केप जिन्हें खनिजों एवं नकदी फसलों के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधन से ज्यादा कुछ नहीं देखा जाता है, हाथियों एवं अन्य प्राणियों के पास घातक संघर्ष से बचने का बहुत कम मौका है।
- संभावना के बजाय रक्षा करने के लिए एक संस्कृति बदलाव, वास्तव में लोगों को समृद्ध करेगा एवं जैव विविधता को बचाएगा।
- एक नीति स्तर पर, एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु वन विभाग को पुनर्जीवित करना होगा।
- यह समय प्रबंधन के वन्यजीव–प्रादेशिक द्वैधता जो वर्तमान में मौजूद है को दूर करने का है। इसके अलावा कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं हैं।
- संदर्भ के आधार पर समाधान अलग–अलग होते हैं, उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार, लोगों का घनत्व, सामाजिक आर्थिक स्थिति इत्यादि।
- किसानों को मुआवजे के लिए इंतजार करने के बजाय अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए सशक्त या सब्सिडी दी जानी चाहिए या इन चरम, अवैध उपायों का सहारा लेने के लिए मजबूर होना चाहिए।

एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली–मुंबई –

समाचार –
- महाराष्ट्र के सीएम एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की, जिसे 'IFLOWS– मुंबइ' के रूप में जाना जाता है।

IFLOWS-Mumbai विवरण –

- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं बृहन्मुंबई नगर निगम के बीच एक संयुक्त पहल है।
- यह एक निगरानी एवं बाढ़ चेतावनी प्रणाली है।
- प्रणाली में शहर के भीतर शहरी जल निकासी को पकड़ने एवं बाढ़ के क्षेत्रों की भविष्यवाणी करने के प्रावधान हैं।
- इसमें विभिन्न मॉड्यूल शामिल हैं, जैसे डेटा एसिमिलेशन, फ्लड, इनड्यूलेशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क, डिसेमिनेशन एवं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम।
- प्रणाली शहर के विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के लिए बाढ़ की चेतावनी उत्पन्न करने के लिए डिजाइन की गई है।
- यह सारी जानकारी तब अधिकारियों को दी जाएगी।
- इससे मुंबई में चक्रवात एवं भारी बारिश की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करके लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकेगा।
- यह 6 से 72 घंटे के बीच कहीं भी संभावित बाढ़–संभावित क्षेत्रों के अलर्टों को रिले करने में सक्षम होगा जैसे –
  1. बाढ़ का पानी किस ऊँचाई तक आएगा
  2. सभी 24 वार्डों में लोकेशनवार समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान
  3. भेद्यता एवं बाढ़ के संपर्क में आने वाले तत्वों की जानकारी

जोखिम के बारे में चेतावनी के पूर्वानुमान में अलर्ट शामिल होगा –

1. सूचना की जानकारी
2. बाढ़ के पानी का स्तर
3. रहने वाले क्षेत्रों के लिए उछाल से प्रभावित होने की आशंका

यह कैसे काम करता है?

- सिस्टम के बाढ़ आकलन का प्राथमिक स्रोत वर्षा की मात्रा है।
- मुंबई एक तटीय शहर है, यह प्रणाली ज्वार की लहरों एवं तूफान के ज्वार में भी कारक है।

यह मापकर किया जा रहा है –

1. शहर की वर्षा, कितना पानी बाहर निकल गया।
2. भूगोल, भूमि उपयोग, बुनियादी ढांचा विकास
3. जनसंख्या
4. झीलें,
5. सभी नदियों जैसे कि मिठी, दहिसर, ओशीवारा, पॉईसर, एवं उल्हार के आँकड़े

इस प्रणाली में शामिल हैं –

- नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मॉडल
- फील्डभारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, BMC एवं IMD द्वारा स्थापित 165 स्टेशनों के वर्षा गेज नेटवर्क से फील्ड डेटा।

आवश्यकता –

- मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी, समय–समय पर वृद्धि के साथ बाढ़ का सामना कर रही है।
- 26 जुलाई 2005 को बाढ़ के दौरान, जब शहर में 94 सेमी बारिश हुई, तो 24 घंटे की अवधि में 100 साल के ऊंचे शहर ने पूरी तरह से शहर को पंगु बना दिया था।
- 29 अगस्त 2017 को आई बाढ़ ने शहर को एक ठहराव में ला दिया था।
- 2019 में, अक्टूबर के अंत तक मानसून एवं बेमौसम बारिश एवं अरब सागर में दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात थे।
- इनसे मुंबई में तबाही का मंजर बना है।
- शहर में जून से सितंबर तक शहरी बाढ़ आम है, जिसके परिणामस्वरूप यातायात, रेलवे एवं एयरलाइनों की सेवाएँ रूक जाती है।
- बाढ़ आने से पहले की तैयारी के रूप में, IFLOWS– मुंबई प्रणाली नागरिकों को चेतावनी देने में मदद करेगी।
- यह व्यवस्था पाने वाला चेन्नई के बाद मुंबई देश का दूसरा शहर है।
- बेंगलुरु एवं कोलकाता के लिए भी इसी तरह की प्रणाली विकसित की जा रही है।

डार्क वेब पर बिक्री के लिए तैनात एक लाख से अधिक भारतीयों का डेटा

समाचार –

- साइबर इंटेलिजेंस फर्म साइबल के अनुसार, आधार, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट सहित भारतीयों की राष्ट्रीय आईडी की 1 लाख से अधिक स्कैन प्रतियां बिक्री के लिए डार्क वेब पर डाल दी गई हैं।
- ऐसा लगता है कि आंकड़ों किसी तीसरे पक्ष से लीक हुए है, न कि सरकारी तंत्र से।
- साइबर अपराधियों द्वारा लीक किए गए व्यक्तिगत डेटा से विभिन्न नापाक गतिविधियों जैसे पहचान की चोरी, घोटाले एवं कॉर्पोरेट जासूसी का खतरा है। कई अपराधी आईडी में व्यक्तिगत विवरण का उपयोग धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए फोन कॉल पर लोगों का विश्वास जीतने के लिए करते हैं।

भारत में डेटा संरक्षण –

- 2008 में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में इलेक्ट्रॉनिक डेटा की सुरक्षा के प्रावधान हैं।
- पुट्टस्वामी फैसले (2017) में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है एवं व्यक्तिगत डेटा को सूचनात्मक गोपनीयता के आवश्यक पहलू के रूप में संरक्षित करना आवश्यक है।
- हाल ही में, भारतीय संसद ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (पीडीपी) विधेयक, 2019 को पेश किया, जो डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर घरेलू तौर पर कानून बनाने का भारत का पहला प्रयास होगा। विधेयक कुछ व्यक्तिगत डेटा को संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के रूप में वर्गीकृत करता है। इसमें वित्तीय डेटा, बायोमेट्रिक डेटा, स्वास्थ्य डेटा, जाति, धार्मिक या राजनीतिक विश्वास शामिल हैं।

अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उपग्रह आधारित सेवा प्रावधान से लेकर रॉकेट लॉन्च तक की संपूर्ण गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों को मंजूरी दी गई है।
- यह एक नई एजेंसी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र द्वारा लागू किया जाना है।
- भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नत क्षमताओं वाले मुट्ठी भर देशों में से है। इन सुधारों के साथ, इस क्षेत्र को नई ऊर्जा एवं गतिशीलता मिलेगी।
- यह एक बड़ी बात है, डेरेग्यूलेशन के पैटर्न के साथ जो हमने आखिरी बार 1990 के दशक में देखा था।

मुख्य लाभ –

- वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये का चौथा हिस्सा आत्मनिर्भर भारत स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के तहत दिया है, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है।

- न केवल अंतरिक्ष में, बल्कि व्यापक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को उदार बनाना देश के लिए एक आवश्यक शर्त है।
- प्रस्तावित सुधार आत्मनिर्भर भारत विशेष आर्थिक पैकेज का एक हिस्सा हैं एवं ये सुधार अंतरिक्ष परिसंपत्तियों एवं गतिविधियों के सामाजिक–आर्थिक उपयोग को बढ़ाएंगे, जिसमें अंतरिक्ष संपत्ति, डेटा एवं सुविधाओं तक बेहतर पहुंच भी शामिल है।
- इससे न केवल इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा बल्कि भारतीय उद्योग वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकेगा।
- इसके साथ, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार एवं भारत एक वैश्विक प्रौद्योगिकी बिजलीघर बनने का अवसर है।
- नव निर्मित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए एक स्तर का खेल मैदान प्रदान करेगा।
- यह प्रोत्साहित करने वाली नीतियों एवं एक अनुकूल विनियामक वातावरण के माध्यम से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों को हाथ से पकड़ेगा, बढ़ावा देगा एवं मार्गदर्शन करेगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम 'न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड' 'आपूर्ति संचालित' मॉडल की तुलना में 'मांग संचालित' मॉडल से अंतरिक्ष गतिविधियों को फिर से उन्मुख करने का प्रयास करेगा, जिससे हमारी अंतरिक्ष संपत्ति का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- ये सुधार इसरो को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, नई प्रौद्योगिकियों, अन्वेषण मिशनों एवं मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देंगे।
- कुछ ग्रह अन्वेषण मिशन भी 'अवसर की घोषणा' तंत्र के माध्यम से निजी क्षेत्र के लिए खोले जाएंगे।
- आधी सदी पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के गठन के बाद से इस क्षेत्र में यह सबसे महत्वपूर्ण विकास है।

चिंता का विषय है एवं आगे की राह –

- सरकार को मूल बातें सही करने पर ध्यान देना चाहिए। उद्योग कैसे विकसित होता है, इसके लिए नियामक संरचना महत्वपूर्ण है।
- सरकार के लिए केवल यह घोषणा करना पर्याप्त नहीं है कि अंतरिक्ष में निजी निवेश के दरवाजे खुले हैं – यह संकेत देना चाहिए कि सभी निवेशकों के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा एवं इष्ट खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को मध्य–मार्ग में नहीं बदला जाएगा।
- इसका एक विश्वसनीय संकेत वाणिज्यिक गतिविधियों में भाग लेने वालों से शासन में शामिल व्यक्तियों एवं संस्थाओं के संरचनात्मक पृथक्करण से होगा।
- IN-SPACe को एक 'स्वायत्त नोडल एजेंसी' होना है। यह स्वायत्त होगा, लेकिन यह केवल एक नोडल एजेंसी होगी, न कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण।
- IN-SPACe को शुरू से ही दो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसरो एवं न्यूस्पेस के बीच भूमिकाओं एवं संसाधनों के विभाजन की देखरेख करना एवं एक बार ऐसा करना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निजी खिलाड़ियों को सामान्य बुनियादी ढाँचे के लिए गैर–भेदभावपूर्ण पहुँच प्राप्त हो।
- IN-SPACe के लिए एक प्रभावी सूत्रधार, प्रधान मंत्री कार्यालय रहेगा। इसे एक नोडल एजेंसी से परे जाने एवं अधिकार प्राप्त करने के लिए अधिकार देना होगा – शायद प्रतिनिधिमंडल द्वारा – कई मंत्रालयों एवं विभागों से आवश्यक कई लाइसेंस एवं मंजूरी जारी करने के लिए।
- भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भर बनना एवं उस लक्ष्य को हासिल करना है। नई दिल्ली आक्रामक तरीके से एक खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए लड़ने चाहिए। आत्मनिर्भरता का विरोधाभास है कि यह केवल उदार नीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अन्य क्षेत्रों के अलावा अंतरिक्ष के लिए भी ऐसा ही है।

भारत ने चीनी ऐप्स पर रोक लगाई –

समाचार –

- भारत सरकार ने चीनी मूल के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें कई बहुत लोकप्रिय हैं जैसे लघु वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट, एवं कैमस्कैनर आदि
- इन ऐप को ब्लॉक करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के निर्देशों का पालन करने की अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।
- उपयोगकर्ता जल्द ही एक संदेश देखेंगे, जिसमें सरकार के अनुरोध पर ऐप्स तक पहुंच प्रतिबंधित है।

कानूनी कारण –

- सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि उसे इस संबंध में कई शिकायतें मिली हैं।
- कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग की खबरें थीं।
- चोरी एवं चुपके से उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनधिकृत तरीके से उन सर्वरों में संचारित किया जा रहा था जिनमें भारत के बाहर के स्थान हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के तहत प्रतिबंध लागू किये गए है।
- यह किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी के सार्वजनिक उपयोग के लिए अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
- ऐसा भारत के
  1. संप्रभुता एवं अखंडता के हित में
  2. भारत की स्थिति, राज्य की सुरक्षा
  3. विदेशी राज्यों के साथ पूरी तरह से संबंध
  4. गणतंत्र व्यवस्था
  5. किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन को रोकने के लिए, किया गया है।

प्रतिबंध का प्रभाव –

- तरहनए सामाजिक मीडिया जैसे कि हेलो एवं लाईकी तथा वीडियो चैट एप्लिकेशन बिगो लाइव प्लेटफॉर्म उन भारतीयों में जो अंग्रेजी में सहज नहीं हैं, बेहद लोकप्रिय हैं।
- ज्पाज्वा ऐप के देश में 100 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं।
- टिक्टोक के लगभग 30% डाउनलोड भारत से आते हैं।
- लेकिन टिकटोक को सामग्री के निजीकरण एवं समग्र प्रभाव के संदर्भ में अधिक संभावना के रूप में देखा गया था।
- टिक्टोक ने भारत के भीतरी इलाकों में अथक दबाव बनाया। जाहिर है, एप्लिकेशन 15 से अधिक भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है।
- इसने एप्लिकेशन को बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से क्षेत्रीय प्रतिभा पर काम करने में सक्षम बनाया।
- इन उपयोगकर्ताओं को विकल्प की तलाश करनी होगी।
- इसके अलावा, इन प्लेटफार्मों में से अधिकांश में भारतीय निर्माता हैं, जिनमें से कई के लिए यह आय का एकमात्र स्रोत है।
- इनमें से कई ऐप के भारत में कार्यालय एवं कर्मचारी हैं, एवं कुछ हजार नौकरियां अब दांव पर हो सकती हैं।

क्या टिकटोक को पहले प्रतिबंधित किया गया है? –

- मई 2019 में, आम चुनावों के लिए, सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ऐप के डाउनलोड पर 2 सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया।
- न्यायालय ने कहा कि यह बच्चों को ग्राफिक सामग्री या शिकारियों के लिए ऐप पर उजागर कर सकता है।
- टिकटोक ने अपील की थी एवं अदालत ने बाद में अपने फैसले को पलट दिया था।

चीन पर प्रभाव –

- लद्दाख में तनावपूर्ण गतिरोध के बीच चीन के साथ जबरदस्त कूटनीति के अभ्यास के रूप में यह कदम आया है।
- निर्णय एक विशिष्ट रणनीतिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में लिया गया है। हालाँकि, सरकार ने अभी तक, एक कम मूल्य वाली वस्तु – मोबाइल एप्स को उठाया है।
- यह भारत में बड़े चीनी व्यवसायों के लिए एवं स्वयं चीन के लिए एक चेतावनी हो सकती है।
- इसका केवल भारतीय व्यवसायों पर सीमित प्रभाव है।
- यह बड़े पैमाने पर उपभोक्ता खंड में एक बड़ी उपस्थिति है।
- इससे भारत को ऐप स्पेस में दिए गए विकल्पों पर चोट नहीं लग सकती है।
- इसके बजाय, यह कदम प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर केंद्रित है।
- भौतिक वस्तुओं पर प्रतिबंध से चीन के व्यापार पर शायद ही कोई असर पड़ेगा, जबकि भारत के व्यापार एवं अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

MSME क्षेत्र –

समाचार –

- अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यम दिवस 27 जून को 'कोविड 19– द ग्रेट लॉकडाउन एवं लघु व्यवसाय पर इसके प्रभाव' विषय के तहत मनाया जा रहा है।
- MSME मंत्रालय ने सब–ऑर्डिनेट डेट के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की, जिसे MSMEs के लिए 'डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड–सब–ऑर्डिनेट डेट' के रूप में भी जाना जाता है।
- MSME मंत्रालय ने MSME के वर्गीकरण एवं पंजीकरण के लिए 1 जुलाई से प्रभावी होने के लिए समेकित अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना डैडमे के वर्गीकरण या पंजीकरण के संबंध में सभी पूर्व सूचनाओं को सुपरसीड करेगी।

पंजीकरण प्रक्रिया –

- एक MSME को उसके बाद Udyam एवं Udyam पंजीकरण के रूप में पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- पंजीकरण स्व–घोषणा के आधार पर ऑनलाइन दायर किया जा सकता है। प्रमाण के रूप में दस्तावेज, कागजात या प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक नहीं होगा।
- एमएसएमई वर्गीकरण के लिए बुनियादी मानदंड संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण एवं टर्नओवर में निवेश पर होगा।
- पिछले वर्ष के आईटी रिटर्न से जुड़ी किसी भी उद्यम एवं निवेश गणना के टर्नओवर की गणना करते समय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के निर्यात को बाहर रखा जाएगा।
- पंजीकरण एवं उसके बाद उद्यमियों की सुविधा के लिए देश भर में चैंपियंस कंट्रोल रूम को कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया गया है।

MSMEs का वर्गीकरण –

- सूक्ष्म उद्यमों – एक करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं एवं 5 करोड़ रुपये का कारोबार।
- छोटे उद्यम – 10 करोड़ रुपये तक का निवेश एवं 50 करोड़ रुपये तक का कारोबार।
- मध्यम उद्यम – निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं एवं 250 करोड़ रुपये का कारोबार।

एमएसएमई का महत्व –

- देश के भौगोलिक विस्तार में लगभग 63.4 मिलियन इकाइयों के साथ, एमएसएमई विनिर्माण जीडीपी का लगभग 6.11% एवं जीडीपी का 24.63% सेवा गतिविधियों के साथ–साथ भारत के विनिर्माण उत्पादन का 33.4% योगदान देता है।
- वे लगभग 120 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार देने में सक्षम हैं एवं भारत से कुल निर्यात का लगभग 45% योगदान करते हैं।
- लगभग 20% MSME ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर हैं, जो MSME क्षेत्र में महत्वपूर्ण ग्रामीण कार्यबल की तैनाती को इंगित करता है।

इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनेलिसीस (आईडीएसए)

ऑस्ट्रेलिया पर साईबर हमले को समझना –

- कोविड–19 के प्रकोप ने संचार के तरीकों के साथ–साथ लेन–देन के रूप में डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग को भी बढ़ाया है। हालाँकि, पर्याप्त साइबर सुरक्षा उपायों की कमी ने दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताओं के नेटवर्क एवं सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए कई प्रवेश बिंदु खोले हैं।
- हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया में कई सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संगठनों को बड़े पैमाने पर साइबर हमले का सामना करना पड़ा। श्री स्कॉट मॉरिसन (प्रधान मंत्री) के अनुसार, ये हमले 'सरकार, उद्योग, राजनीतिक संगठनों, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवश्यक सेवा प्रदाताओं एवं अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के ऑपरेटरों के सभी स्तरों सहित कई क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलियाई संगठनों को लक्षित कर रहे हैं।'
- हमलों में इस्तेमाल किए गए मालवेयर जिस पर संदेह है, को एरिया–बॉडी के रूप में जाना जाता है, इसे एक चीनी साइबर–क्राइम ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है जिसे Naonon कहा जाता है।
- एरिया–बॉडी में हैकर को कंप्यूटर का नियंत्रण सौंपने की खतरनाक क्षमता होती है, जिसमें फाइलों तक पहुंच, ईमेल का उपयोग एवं क्या टाइप किया जा रहा है यह देखना शामिल है।

साइबर हमला क्या है? –

- कंप्यूटर एवं कंप्यूटर नेटवर्क में किसी हमले का खुलासा करने, बदलने, अक्षम करने, नष्ट करने, चोरी करने या किसी संपत्ति का अनधिकृत उपयोग करने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का प्रयास है। ऑस्ट्रेलिया साइबर अपराध के तीन डीएस का अनुभव कर रहा है, अर्थात डिसरप्ट, डिनाय एवं डिस्ट्रॉय।

हमले का रूप –

- हमलावरों ने आम 'कॉपी–पेस्ट कॉम्प्रोमाईसेस' का उपयोग किया है, जो साइबर एक्टर के 'प्रूफ–ऑफ–कॉन्सेप्ट' के एक्सप्लॉईट कोड, वेब शेल एवं ओपन सोर्स से कॉपी अन्य उपकरणों के भारी उपयोग से प्राप्त किए जाते हैं।

- हमलावर मुख्य रूप से देश के नेटवर्क एवं सिस्टम को लक्षित करने के लिए 'रिमोट कोड निष्पादन भेद्यता' का उपयोग कर रहे हैं। यह साइबर हमलें का एक सामान्य रूप है जिसमें अपराधी अपने स्वयं के सॉफ्टवेयर कोड को सर्वर या डेटाबेस जैसे कमजोर सिस्टम में डालने की कोशिश करता है। यह प्रयास, अनुकूलित 'स्पीयर फिशिंग' तकनीकों जैसे पासवर्ड हारवेस्ट करने के लिए लक्षित लिंक्स पर दुर्भावनापूर्ण फाईल्स को भेजना शामिल है।

संदिग्ध –

- ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान ने पाया कि हमले के पैमाने एवं तीव्रता को देखते हुए इसके '95 प्रतिशत या अधिक' संभावना चीन से लॉन्च होने की है। ऑस्ट्रेलियाई जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि हमलावर अतीत में चीन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कोड एवं तकनीकों का इस्तेमाल करते थे।
- ये हमले ऐसे समय में हुए जब दोनों देश कोरोनोवायरस की उत्पत्ति के मुद्दे पर आमने–सामने थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने वायरस की उत्पत्ति में चीन की भूमिका की संयुक्त राष्ट्र जांच शुरू करने का प्रयास किया था।
- दोनों देशों के बीच व्यापार, यात्रा सहित कई मुद्दों पर तनाव बढ़ रहा है एवं हाल ही में, एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक कर्म गिलेस्पी को मौत की सजा दी गई, जो कथित रूप से एक ड्रग तस्कर था।
- चीन ने साइबर हमले में किसी भी भूमिका से इनकार किया है। चीन ने कुछ ऑस्ट्रेलियाई आयातों पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं एवं ऑस्ट्रेलियाई सामानों के बहिष्कार की धमकी दी है।

भारतीय संदर्भ –

- एक साइबर सिक्योरिटी फर्म, सायफर्मा ने भी चीन के साथ चल रहे तनाव के मद्देनजर संभावित बड़े पैमाने पर साइबर हमले के खिलाफ भारत को चेतावनी दी है। 19 जून को, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने भारत के साथ बड़े पैमाने पर फिशिंग हमले अभियान के बारे में एक सलाह जारी की।
- सायफर्मा ने डार्क वेब पर चीनी हैकर फोरम में हो रही बातचीत के आधार पर जानकारी एकत्र की थी। फर्म ने सूची को अपने स्रोतों में वापस खोजा एवं दो हैकिंग समूहों, गोथिक पांडा एवं स्टोन पांडा के लिंक पाए। इन समूहों को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) से सीधा जुड़ाव बताया जाता है।
- इसके बाद, 23 जून को, महाराष्ट्र साइबर, राज्य पुलिस साइबर विंग ने कहा कि 'भारतीय साइबरस्पेस में संसाधनों पर पिछले चार–पांच दिनों में कम से कम 40,300 साइबर हमलों का प्रयास किया गया'। इस बीच, भारत ने कथित तौर पर चीनी सरकार से जुड़े 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है एवं जबरदस्ती के लिए डेटा निष्कर्षण में शामिल है।

निष्कर्ष –

- ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि वह विदेश में मध्यस्थता एवं जासूसी के संदेह के कारण तनाव के बीच देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 500 अतिरिक्त साइबर भर्ती कर रही है।

पाकिस्तान का सीपेक जुनून – लाभ या हानि?

- अपनी स्थापना के बाद से, चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपेक) ने दुनिया भर के नीति निर्माताओं, विश्लेषकों एवं रणनीतिकारों के बीच बहुत रुचि पैदा की है। जबकि पाकिस्तान में सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग इसे एक वरदान मानता है जो पाकिस्तान के भविष्य को बदल देगा, कई विश्लेषकों ने इसे पाकिस्तान को एक स्थायी उपनिवेश, एक किराएदार–सह–ग्राहक राज्य में बदलने की चीनी खेल–योजना के रूप में देखा है। पाकिस्तान के अन्य लोगों ने इसे कर्ज का जाल एवं चॉकलेट का प्याला कहा है।

इसमें विवादास्पद क्या है?

- सीपेक को वित्तपोषित करने के लिए विशेष रूप से ब्याज की दर एवं चीनी ऋणों की अन्य शर्तों की गोपनीयता इस परियोजना को विवादास्पद बनाती है।
- संघीय सरकार का आशावाद पंजाब के अलावा बाकी प्रांतों द्वारा साझा नहीं किया गया है।
- यह खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को लगभग दरकिनार कर देता है एवं अपने लोगों को लाभ दिए बिना बलूचिस्तान के संसाधनों का फायदा उठाने का प्रयास करता है।

निवेश या ऋण जाल?

- 2013 में शुरू हुआ, CPEC, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत एक प्रमुख परियोजना को अप्रैल 2015 में एक बड़ी सफलता मिली जब चीन ने शुरू में 15 वर्ष की अवधि में परियोजना कार्यान्वयन के लिए 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया। बाद में इसे बढ़ाकर 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया।
- इसका एक बड़ा हिस्सा (यूएस $35 बिलियन) पाकिस्तान की मौजूदा 4.5 गीगावॉट की ऊर्जा कमी को पूरा करने में मदद करने के लिए, ऊर्जा उत्पादन पर (कुल लगभग 17 गीगावॉट एवं 2020 तक 10 गीगावॉट) चिह्नित किया गया था।
- पांच साल बाद, पाकिस्तान के पास अपने कोयला आधारित संयंत्रों से प्राप्त 5.918 गीगावॉट की अतिरिक्त ऊर्जा है, एवं यह आंशिक रूप से पनबिजली, सौर एवं पवन ऊर्जा से भी है। पाकिस्तान योजना आयोग द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार, कुल व्यय लगभग अमेरिकी 9.309 बिलियन डॉलर है, जिसमें से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) के आंकड़ों के अनुसार, चीन ने 2015–2020 के दौरान 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर का निवेश किया है। अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में, मुख्य रूप से सड़कें शामिल हैं जिसमें लगभग 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है।
- हालांकि देश अब ऊर्जा अधिशेष है, स्थानीय लोगों के लिए बिजली उत्पादन की इकाई लागत बहुत अधिक है। बिजली कंपनियां उच्च कीमत पर बिजली बेच रही हैं, खासकर कराची में जहां यह पाकिस्तानी रुपया या पीकेआर 17.69 प्रति यूनिट है।
- पाकिस्तानी पर्यवेक्षकों का मानना है कि CPEC चीनी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए एक उपहार के रूप में आया है। उन्हें कर में छूट से लाभ होता है एवं संप्रभु गारंटी के माध्यम से सीपेक परियोजनाओं से अच्छे रिटर्न का आश्वासन दिया गया है। बैंकिंग सुविधाओं एवं अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से वित्तीय पूंजी तक उनकी पहुंच भी आसान है। इसलिए, स्थानीय उद्योगों ने अपने चीनी समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल पाया है।

- चीन के लिए, सुनिश्चित रिटर्न के साथ इस तरह के निवेशों के अलावा, बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर बंदरगाह तक काराकोरम कॉरिडोर का विस्तार महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रासंगिकता है। यह पश्चिमी चीन में शिनजियांग के ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्र को इस बंदरगाह के माध्यम से पश्चिमी एशिया में ऊर्जा संपन्न क्षेत्रों से जोड़ता है।
- इस प्रकार, ग्वादर को CPEC का 'प्रवेश द्वार' कहा जा रहा है एवं एक सरकारी स्वामित्व वाली चीनी कंपनी, ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने इस बंदरगाह को 40 वर्षों के लिए लीज पर लिया है। यह अपने समुद्री परिचालन से 91 प्रतिशत से अधिक राजस्व एवं आसन्न मुक्त क्षेत्र के प्रबंधन से राजस्व का 85 प्रतिशत से अधिक रखेगा।
- हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने एवं खाड़ी देशों से तेल की निर्बाध आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए देश की गहरे समुद्री बंदरगाह तक पहुंच काफी महत्वपूर्ण है।
- इसके अलावा, चीनी भी कथित तौर पर अपने हजारों नागरिकों को ग्वादर पोर्ट में बसाने की दिशा में काम कर रहे हैं। चीन–पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ग्लोबल, एक निर्माण कंपनी है जिसने बंदरगाह क्षेत्र में अचल संपत्ति विकसित करने का काम किया है, उसने पहले ही 3.6 मिलियन वर्ग फुट का इंटरनेशनल पोर्ट सिटी खरीद लिया है एवं वह चीनी पेशेवरों के लिए ग्वादर में प्रस्तावित एक नये वित्तीय जिले में 150 मिलियन डॉलर की एक गेटेड कम्युनिटी बनाएगा।

विकास का मिथक –

- शुरुआती वर्षों में, सीपेक परियोजनाओं ने घरेलू खपत में वृद्धि के कारण पाकिस्तान के विकास में योगदान दिया।
- उदाहरण के लिए, ऊर्जा एवं सड़क अवसंरचना परियोजनाओं पर काम के कारण सीमेंट, छोटी मशीनरी एवं अन्य उत्पादों की मांग बढ़ी। लेकिन इससे आयात बिल में भी वृद्धि हुई क्योंकि बड़ी मशीनरी एवं अन्य सामान आयात किए गए, जिससे भुगतान संतुलन में कमी आई।
- आयात–संचालित अर्थव्यवस्था, कृत्रिम रूप से, रुपये के मूल्य को मजबूत रखती है। एक बार जब यह चरण समाप्त हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था भारी तनाव में आ जाएगी।
- पाकिस्तान के विकास में 2018–19 के दौरान लगभग 1.9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। विश्व बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2020–21 में पाकिस्तान के लिए नकारात्मक –1 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है।
- सरकार को मुद्रा के अवमूल्यन करने एवं राहत पैकेज के लिए आईएमएफ तक पहुंचने के लिए मजबूर किया गया है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा है कि वह चीन को दिए गए कर्ज को स्पष्ट करे क्योंकि वह नहीं चाहता था कि चीनी ऋण चुकाने के लिए राहत पैकेज का इस्तेमाल किया जाए।

निष्कर्ष –

- दुनिया भर में विश्लेषकों द्वारा व्यक्त की गई आलोचनाओं एवं चिंताओं के कारण, पाकिस्तान एवं चीनी अधिकारी अब अरबों की लागत वाली नई अवसंरचना परियोजनाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं, जिसमें रेलवे परियोजना ML–1 शामिल है जिसकी अनुमानित लागत 7.2 बिलियन डॉलर है।
- यहां तक कि डायमर–भाषा बांध (डीबीडी) परियोजना में निवेश के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, इन ऋणों को चुकाना मुश्किल होगा। केंद्र सरकार का बाहरी ऋण जून 2019 में पीकेआर 11 ट्रिलियन से बढ़कर इस साल फरवरी में पीकेआर 11.23 ट्रिलियन हो गया है।
- विश्व बैंक के अनुसार, इस साल मार्च में रुपये में 7.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई एवं वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 1.3 प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान है। जीडीपी से सार्वजनिक ऋण का अनुपात 72.1 प्रतिशत था।
- इन सभी का भविष्य में पाकिस्तान की ऋण स्थिति में निहितार्थ होगा। आज पाकिस्तानी सीपैक के अपने उत्साह को आर्थिक दुःस्वप्न में बदलते हुए देख सकते हैं।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सामरिक क्षमता का लाभ उठाने का समय

- हाल के वर्षों में, भारत ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को बदलने के उद्देश्य से एक सक्रिय नीति अपनाई है, जो एक त्रि–सेवा कमान है, एक आर्थिक केंद्र एवं अपनी रक्षा एवं सुरक्षा रणनीति के प्रमुख केंद्रों में से एक है। द्वीपों के लिए एक केंद्रित विकास योजना से हिंद महासागर क्षेत्र में देश के भू–राजनीतिक लाभ में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।
- अब तक, सामरिक विचारों के कारण द्वीपों को अलग करने के पक्ष में पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक विकास के बीच संतुलन खो दिया गया था। इस कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की आर्थिक क्षमता काफी हद तक अप्रयुक्त रह गई थी।
- जैसा कि द्वीप समूह भारत को बंगाल की खाड़ी में एक कमांडिंग भूस्थैतिक उपस्थिति एवं दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच प्रदान करते हैं, द्वीपों के लिए एक केंद्रित विकास योजना हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में देश के भू राजनीतिक लाभ को बढ़ाने की उम्मीद है।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने बंगाल की खाड़ी के साथ भारत के क्षेत्रीय जुड़ाव को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।
- यह नीति संक्षेप में अधिक से अधिक नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस), जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं फ्रांस जैसी अन्य नौसेनाओं के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को खोलने की सिफारिश करती है।

रणनीतिक संदर्भ –

- रणनीतिक रूप से स्थित, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अपने आप में कई द्वीप देशों से बड़ा है, भारत की रक्षा एवं रणनीतिक गणना में एक संपत्ति है।
- द्वीप ने डंकन मार्ग एवं टेन डिग्री चैनल तक फैला है। प्रेपारिस चैनल एवं सिक्स डिग्री चैनल द्वीप श्रृंखला के उत्तर एवं दक्षिण में स्थित हैं।
- ये सभी मार्ग दक्षिण–पूर्व एवं पूर्वी एशिया के लिए किसी भी शिपिंग के लिए महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग हैं। 572 द्वीप, जिनमें से केवल 38 बसे हुए हैं, में भारत का 30 प्रतिशत विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) शामिल है।
- अंडमान सागर में छह डिग्री एवं दस डिग्री चैनल जो मलक्का जलडमरूमध्य की ओर जाते हैं, संचार (एसएलओसी) की समुद्री गलियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका एवं प्रशांत के बीच ऊर्जा व्यापार सहित वैश्विक वाणिज्य प्रवाह होता है।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर एवं दक्षिण चीन सागर के चौराहे पर हैं, एवं आगे प्रशांत महासागर तक, जो इंडो–पैसिफिक की रणनीतिक अवधारणा का एक महत्वपूर्ण आधार है।

अंडमान एवं निकोबार कमान तक पहुंच –

- अंडमान एवं निकोबार त्रि–सेवा कमान उत्तरोत्तर बंगाल की खाड़ी एवं अंडमान सागर में भारत की क्षेत्रीय समुद्री गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरा है। विभिन्न बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय समुद्री जुड़ाव अर्थात बंगाल की खाड़ी में बहु–क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए पहल, अभ्यास की MILAN श्रृंखला, समन्वित गश्त, एवं बंगाल की खाड़ी में अंचल एवं अंडमान सागर के साथ द्विपक्षीय अभ्यासों ने इस उद्देश्य में योगदान दिया है।
- जबकि दक्षिणपूर्वी एशियाई देशों की क्षेत्रीय नौसेनाएँ पोर्ट ब्लेयर, अन्य प्रमुख नौसेनाओं के लिए नियमित पोर्ट कॉल कर रही हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाई, जापानी एवं फ्रांसीसी ने पोर्ट कॉल एवं अभ्यास के लिए अंडमान द्वीप पर जाने में रुचि दिखाई है।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप एवं ऑस्ट्रेलिया के कीलिंग (कोकोस) द्वीप समूह के सहयोगात्मक उपयोग के माध्यम से मलक्का, सुंडा, लोम्बोक एवं ओम्बाई वेटार स्ट्रेट्स की समन्वित निगरानी के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं।
- इसी तरह, हिंद महासागर में सहयोगी पनडुब्बी रोधी युद्ध (एएसडब्ल्यू) प्रयासों के बारे में भी कुछ सिफारिशें की गई हैं जिसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

संस्थागत अनिच्छा –

- अन्य नौसैनाओं के दौरो के बावजूद, सामान्य रूप से इन विदेशी नौसेनाओं को अंडमान एवं निकोबार द्वीपों पर डेरा डालने देने की अनुमति देने में कुछ पारंपरिक संस्थागत अनिच्छा मौजूद है। इस तरह के एक स्टैंड की उत्पत्ति अतीत से संबंधित हो सकती है जब भू राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से अलग थी।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीपों को अन्य प्रमुख नौसेनाओं के लिए खोलने के खिलाफ व्यापक तर्क निम्न विचारों पर आधारित हो सकते हैं –

  (ए) यदि नौसेना पोत एवं अन्य प्रमुख नौसेनाओं के सैन्य विमान अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर नियमित रूप से आगंतुक बन जाते हैं तो यह चीन के साथ 'मलक्का विवाद' को बढ़ा सकता है। भारत–चीन द्विपक्षीय संबंधों की जटिलता को देखते हुए, दोनों देशों के बीच दुश्मनी को आगे बढ़ा सकती है।

  (बी) युद्धपोतों एवं सैन्य विमानों द्वारा यात्राओं के माध्यम से बातचीत को बढ़ाना एक 'फिसलन भरी ढलान' हो सकती है जो भारत के प्रत्यक्ष रणनीतिक हितों के दायरे से परे अन्य आकस्मिकताओं के लिए नौसेना एवं सैन्य परिसंपत्तियों की संयुक्त तैनाती के माध्यम से रणनीतिक सहयोग के लिए एवं अधिक जटिल मांगों को जन्म दे सकता है।

  (सी) भारत को चीन के खिलाफ एक सहयोगी ढांचे के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है जिसमें अन्य देश पहले से ही एक घोषित सैन्य गठबंधन में हैं, उदाहरण के लिए, यूएस– ऑस्ट्रेलिया, यूएस–जापान, आदि

  (डी) यदि भारत अन्य प्रमुख शक्तियों की यात्राओं के लिए एक उदार दृष्टिकोण रखता है तो विशेष रूप से अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया के संबंध में एक व्यापक क्विड प्रो क्वो होना चाहिए।

विचारों का विश्लेषण –

- प्रमुख शक्तियों – मित्र शक्तियों एवं भागीदारों सहित – की नौसेना की संपत्ति की अनुमति देने के सवाल पर संपूर्ण दृष्टिकोण भारत–चीन की गतिशीलता पर इसके अनुमानित प्रभाव पर भविष्यवाणी करता प्रतीत होता है। यह केंद्रीय आरक्षण प्रतीत होता है।
- भारत के निर्णय के लिए चीन–केंद्रित दृष्टिकोण निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है –

  (एं) भारत के पास अपने क्षेत्र पर संपूर्ण संप्रभुता, क्षेत्रीय नियंत्रण एवं अधिकार हैं। यह पूरी तरह से भारत को तय करना है कि कौन सी विदेशी नौसेनाएं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की यात्रा कर सकती हैं। मलक्का जलडमरूमध्य एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। सैकड़ों देश जापान, कोरिया गणराज्य एवं अन्य सहित उन जल के माध्यम से अपने नौसैनिक एवं व्यापारी जहाजों को संचालन करते हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से चीन द्वारा नहीं किया जाता है, एवं न ही चीन के पास अपने सामरिक महत्व को परिभाषित करने पर कोई धारणा है। केवल इसलिए कि यह एक संभावित चोक–बिंदु है, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत या किसी भी विदेशी नौसैनिक पोत की ओर से कोई इरादा है कि भारत उस जलमार्ग के माध्यम से चीन के व्यापार एवं ऊर्जा प्रवाह को खतरे में डालने के लिए ए एंड एन द्वीप पर जाने की अनुमति देता है। वैसे भी विदेशी नौसेनाएँ नियमित रूप से मलक्का जलडमरूमध्य एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समुह के आसपास के अंर्तराष्ट्रीय जल पर यातायात कर रही है।

  (बी) अपनी ओर से, चीन हिंद महासागर में अपनी तैनाती में भारत की संवेदनशीलता के लिए कोई चिंता नहीं दिखाता है, न कि अपने आस–पास के क्षेत्र में जाने पर भी। यह भारत द्वारा A&N द्वीपों तक पहुँचने के लिए, मामला–दर–मामला आधार पर, विदेशी नौसेनाओं के अनुरूप नहीं है। चीन के तत्काल आसपास के क्षेत्र में ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। भारत को तथाकथित चीन कारक (चीन के 'मलक्का विवाद') से ए एवं एन द्वीप समूह के लिए अनुकूल नौसेनाओं के दौरे को अलग–अलग देखने की जरूरत है।

  (सी) मामला–दर–मामला आधार पर A & N द्वीप पर जाने के लिए विदेशी नौसैनिक जहाजों की अनुमति देना 'फिसलन भरी ढलान' के समान नहीं है। यह पूरी तरह से विदेशी नौसेनाओं द्वारा भविष्य के अनुरोधों का आकलन करने के लिए भारत पर निर्भर है एवं यह तय करता है कि रणनीतिक सहयोग के लिए अनुरोध करने के लिए – संयुक्त अभ्यास के प्रस्तावों सहित – मामले के आधार पर, भारत अपने सामरिक हितों या संचालन के क्षेत्रों से आगे जाने वाली किसी भी गतिविधि को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

  (डी) जहाज यात्रा मैत्रीपूर्ण देशों के बीच नौसेना के सहयोग का एक सामान्य एवं प्राकृतिक हिस्सा है। इससे इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता है कि दौरा करने वाली नौसेना की शक्ति में रक्षा साझेदारी है या तीसरे देशों के साथ गठबंधन है। चीन ने हिंद महासागर में पाकिस्तान के साथ एवं हाल ही में ईरान एवं रूस के साथ फारस की खाड़ी में एवं दक्षिण अफ्रीका एवं रूस के साथ पश्चिमी हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास किया है। भारत की चिंताएं चीन के लिए कोई कारक नहीं हैं।

  (ई) यदि भारत अमेरिकी नौसेना या किसी अन्य नौसेना को ए एंड एन द्वीप समूह की यात्रा करने की अनुमति देता है, तो वास्तव में, एक अच्छी तरह से माना जाने वाला समर्थक होना चाहिए।

सहयोगात्मक रणनीतिक एएसडब्ल्यू की आवश्यकता –

- प्रशांत महासागर से हिंद महासागर तक पहुंच, विभिन्न चोकप्वाईंट्स जिसमें मलक्का, सुंडा, लोम्बोक एवं ओम्बाई वेटर स्ट्रेट्स शामिल हैं से होकर गुजरती है। विदेशी नौसेना के जहाजों, विशेष रूप से चीनी युद्धपोतों एवं पनडुब्बियों की आवाजाही की निगरानी के लिए इन चोकोपॉइंट्स के आसपास निगरानी आवश्यक है।
- चीन के बढ़ते आर्थिक एवं सामरिक हितों को देखते हुए, IOR में चीनी नौसेना की उपस्थिति में वृद्धि होने की उम्मीद है,

जिसमें चीनी परमाणु पनडुब्बियों द्वारा नियमित फोर्सेस शामिल हैं।

- ध्वनि निगरानी सेंसर (एसओएसयूएस) श्रृंखला एवं लंबी दूरी की समुद्री गश्ती (एलआरएमपी) विमान के संयोजन के माध्यम से प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका एवं जापान का रणनीतिक एएसडब्ल्यू में एक मजबूत सहयोग है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका के बीच सहयोग के माध्यम से हिंद महासागर में रणनीतिक एएसडब्ल्यू निगरानी के लिए एक समान दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, ऐसे सुझाव भी हैं कि भारत एवं ऑस्ट्रेलिया भारत के अंडमान द्वीप एवं ऑस्ट्रेलिया के कीलिंग (कोकोस) द्वीपों से अपने एलआरएमपी विमानों की एक सहयोगी तैनाती पर विचार कर सकते हैं।

योजना

आत्मनिर्भरता का पोषण

- विश्व एक अभूतपूर्व उथल–पुथल का सामना कर रही है। महामारीयाँ सदियों से आती एवं जाती रही है, लेकिन इसने कभी भी दुनिया भर के लोगों एवं संसाधनों को सामूहिक रूप से गंभीर रोजगार संघर्षों एवं संघर्षपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का ऐसा रूप पेश नही किया जैसा हम हाल ही में देख रहे हैं।
- आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य योजना इसलिए एक उचित समय में परिकल्पित की गई है। आत्मनिर्भर योजना के पाँच स्तंभ – अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, जनसांख्यिकी एवं मांग का उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों पर समान दृष्टि डालने से है। देश की पहचान के रूप में अवसंरचना, प्रणाली, प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को लाने के लिए– वाइब्रेंट डेमोग्राफी एवं, संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से मांग–आपूर्ति श्रृंखला का दोहन।
- पिछले कुछ वर्षों में की गई पहल एवं योजनाओं ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा की यात्रा में पहले ही मार्ग प्रशस्त किया है। चाहे वह लाभों को आखिरी मंजिल तक पहुँचाने के लिए लाया गया जेएएम ट्रिनिटी हो या युवा उद्यमियों के लिए इकोसिस्टम बनाने के लिए मेक इन इंडिया या स्टार्ट–अप इंडिया हो।

आत्मनिर्भर भारत –

- एक आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर नागरिकों द्वारा बनाया जाएगा। भारत 130 करोड़ भारतीयों का परिवार है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है एवं इस तरह राष्ट्र निर्माण होता है, फिर हमारी जनसंख्या हमारी सामूहिक ताकत बन जाती है न कि कमजोरी। एक व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है यदि उसके पास कौशल है या वह अपनी आजीविका कमा सकता है।

रोजगार के माध्यम से समावेशी विकास –

- एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का अर्थ हमारी आबादी के प्रत्येक सदस्य के लिए आत्मनिर्भरता से है। तो एक विकास रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है वह समावेशी विकास है।
- रोजगार सृजन समावेशी विकास के लिए केंद्रीय है। जब परिवार में एक व्यक्ति को औपचारिक क्षेत्र में नौकरी मिलती है, तो पूरा परिवार आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विकसित होता है।
- इसके अलावा, परिवार के एक सदस्य के लिए इस तरह के औपचारिक क्षेत्र के रोजगार से भविष्य की पीढ़ियों की गतिशीलता में योगदान होता है क्योंकि बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं एवं इस तरह वे खुद का उत्थान करते हैं। श्रम बल के बड़े अंशों को अप्राप्य छोड़ना अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अक्षम है क्योंकि वे जिस उत्पादन में योगदान दे सकते हैं वह अप्रयुक्त रहता है।

निजी एवं सरकारी उद्यम के माध्यम से धन एवं कौशल –

- आत्मनिर्भरता का अर्थ निजीएवं सरकारी क्षेत्र की पूरक भूमिकाओं को पहचानना है। बाजार की ताकतों को पहचानने के बिना आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की जा सकती है एवं निजी उद्यम सामान्य समय के दौरान हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं।
- इसलिए, निजी उद्यम को बढ़ावा देना आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए। "शुभ–लाभ" (समृद्धि एवं लाभ) का विचार यह है कि लाभ पराए नहीं है, लेकिन मानव प्रयास के मूल में है एवं यह कि सामाजिक–समृद्धि एवं व्यवसाय–लाभ एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते।
- विशेष रूप से, आत्मनिर्भरता के निर्माण के लिए सरकार को निम्नलिखित तरीकों से ऋद्धि एवं सिद्धि के विकास का समर्थन करना चाहिए –
  1. हमारे नागरिक कौशल सीखते हैं, जो कि सिद्धि है।
  2. हमें अपने एमएसएमई एवं एसएमई को कुशल श्रम प्रदान करके उनका समर्थन करना चाहिए। श्रमिकों की सिद्धि एमएसएमई एवं श्रमिकों दोनों के लिए रिद्धि बनाएगी।
  3. हमें डिजिटल अर्थव्यवस्था, चिकित्सा अनुसंधान जैसे अनुसंधान एवं विकास एवं नवाचार में निवेश करना चाहिए।
  4. हमें पृथ्वी के संसाधनों का सार्थक उपयोग करके नई तकनीकी ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।
  5. हमें रिद्धि एवं सिद्धि दोनों के माध्यम से बाकी दुनिया की मदद करने का लक्ष्य रखना चाहिए।

पिरामिड के निचले हिस्से के लिए उत्पादन –

- आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि भारतीय फर्म ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो हमारी विशाल आबादी की जरूरतों को पूरा करती हैं।
- भारतीय कंपनियों ने गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो व्यावसायिक मॉडल तैयार किए हैं, वे उन्हें एशिया में कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बाजारों में टैप करने में सक्षम कर सकते हैं।
- गरीब उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने वाले विकास मॉडल बनाकर, आत्मनिर्भर भारत दूसरों की मदद कर सकता है एवं इस तरह एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अपने सही स्थान को प्राप्त कर सकता है।

आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि का महत्व –

- भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए कृषि महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा में सुधार एवं भुगतान संतुलन (कम खाद्य आयात एवं निर्यात में वृद्धि), कृषि–प्रसंस्करण, कृषि आदानों का निर्माण, एवं खेती पर आधारित सेवाएँ अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करने एवं आय में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। कृषि वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के अवसर हैं, यह परिवर्तन उच्च–मूल्य वर्धित फसलों की पहचान कर सकता है जिसकी कहीं ओर मांग हो।
- इसके अलावा, कृषि तकनीकी रूप से बहुत उन्नत हो सकती है, जो सीखने के आधार के रूप में सेवारत है, जिसमें कुछ ऐसे कौशल हैं जो अन्य क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं।
- सफल कृषि परिवर्तन से शहरी प्रवास से उत्पन्न होने वाले दबाव में कमी आएगी।

आत्मनिर्भरता का यह अर्थ नही है कि स्वयं सब कुछ करना –

- चाहे वह व्यक्ति हो या राष्ट्र, आत्मनिर्भरता का यह अर्थ नही है कि वह सब कुछ स्वयं कर सकता है। इसी तरह, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण का मतलब अलगाव में अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं है।
- आत्मनिर्भरता का तात्पर्य यह है कि जब हम आज मदद के लिए दूसरों पर निर्भर हैं तो आगे चलकर हम उसमें आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
- इस प्रकार, आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है, जहां भारत खुद को दुनिया के बाकी हिस्सों से काट देता है एवं इस तरह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा करने से बचता है एवं उनके खिलाफ खुद को बेंचमार्क करता है। इसके बजाय, आत्मनिर्भरता के लिए ऐसे क्षेत्रों का परिसीमन करना आवश्यक है जो सामरिक रूप से राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हैं एवं इन क्षेत्रों में निवेश करे ताकि कमजोर समय के दौरान हमारी निर्भरता कम से कम हो।

जेएएम (जनधन–आधार–मोबाईल) ट्रिनिटी –

- सरकार कोविड–19 संकट के दौरान नीति कार्यान्वयन, आवश्यक संचालन एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने एवं राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्लेटफार्मों को स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। शासन के एक उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी ने कोविड–19 महामारी से पहले ही भारत में सार्वजनिक भलाई के वितरण में कई क्षेत्रों को बदल दिया था।
- महामारी में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के दो मुख्य स्तंभ – सार्वजनिक वस्तुओं की निगरानी एवं वितरण। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप द्वारा निगरानी संभव हो गई है जिसने विश्व स्तर पर ऐप के स्विफ्ट वॉल्यूम डाउनलोड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
- जेएएम ट्रिनिटी (जन धन बैंक खाते से वंचित–आधार संख्या– मोबाइल टेलीफोनी) का उपयोग, एक बड़े पैमाने पर शासन में प्रौद्योगिकी को गले लगाने के लिए अब भी अपने सबसे कठिन परीक्षण के माध्यम से चलाया गया है। महामारी के दौरान तेजी से कार्यवाही की आवश्यकता के खिलाफ सरकारी लाभ एवं धन की आसान पहचान एवं हस्तांतरण के के लिए सुविधा का परीक्षण किया गया है।

जेएएम ट्रिनिटी इतना शक्तिशाली क्यों है?

- भारत में 38 करोड़ (380 मिलियन) से अधिक जन धन बैंक खाते हैं जिनका उपयोग सरकारी लाभों को स्थानांतरित करने के लिए किया गया है।
- सभी भारतीयों के 99% से अधिक को कवर करते हुए 1 बिलियन से अधिक आधार नंबर जारी किए गए हैं। 2019 में, भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या 500 मिलियन को पार कर गई। जेएएम ट्रिनिटी देश के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम (डीबीटी) के लिए 'एनबलर' भी है जो सरकारी कल्याण योजनाओं के तहत नकद हस्तांतरण के वितरण को कारगर बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक विधि का उपयोग करता है।
- लॉकडाउन के साथ समाज के कई वर्गों के घरेलू बजट पर भारी दबाव पड़ा, JAM ट्रिनिटी एक सुरक्षा जाल के रूप में काम कर रही है एवं लाखों लोगों की मदद कर रही है जिन्हें तत्काल मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है।
- मुख्य लाभ जो JAM को एक अनिवार्यता के रूप में उजागर करते हैं –

  1. वर्तमान समय जेएएम ट्रिनिटी ने डीबीटी कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है एवं आंशिक से सर्वव्यापी तक इसके कवरेज का विस्तार किया है। आधार ने वैध डेटाबेस की सुविधा दी है जबकि जन–धन ने सभी के लिए बैंक खातों की पेशकश की है।

  2. बिचौलियों की जरूरत को खत्म करके, जेएएम ने भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, गलत कामों एवं तीर्थयात्राओं को कम करने में मदद की है। इसलिए इसने व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा दिया है।

  3. कोविड–19 के प्रसार को कम करने के लिए भौतिक गड़बड़ी की आवश्यकता को देखते हुए, JAM लाभार्थियों के बीच ऑनलाइन लेनदेन को बढ़ावा दे रहा है, बैंकों में भौतिक यात्राओं के बजाय एटीएम एवं भुगतान कार्ड का उपयोग कर रहा है।

  4. दीर्घावधि में, JAM जैसी DBT योजनाएं ग्रामीण आबादी को 'बचत' की अवधारणा से परिचित कराएंगी एवं इस प्रकार यह पूरे देश की जीडीपी में योगदान देगा।

शासन में डिजिटल प्रौद्योगिकी –

- सरकार नीति कार्यान्वयन, आवश्यक संचालन एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सक्रिय रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्लेटफार्मों की स्थापना को बढ़ावा दे रही है।
- सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस संकट के दौरान प्रमुख माध्यमों के रूप में सामने आए हैं जो नागरिकों को सरकारों से जोड़ते हैं एवं सभी उपयोगकर्ताओं को सबसे विश्वसनीय जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देते हैं।
- इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रौद्योगिकी न केवल स्वास्थ्य सेवा एवं आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा दे रही है, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला एवं सार्वजनिक वितरण नेटवर्क पर लगाए गए दबावों को भी कम कर रही है।
- कोविड–19 की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग देश भर में न केवल आरोग्य सेतु (11 भाषाओं में उपलब्ध) के माध्यम से किया गया है, बल्कि राज्य स्तर पर पंजाब (कोवा पंजाब) सहित हिमाचल प्रदेश में भी किया जा रहा है। (कोरोना मुक्त हिमाचल), उत्तराखंड (उत्तराखंड कोविद–19 ट्रैकिंग सिस्टम), छत्तीसगढ़ (रक्षा सर्व, स्टार्ट–अप मोबकोडर), गुजरात (एसएमसी कोविद –19 ट्रैकर), महाराष्ट्र (महाकवच), गोवा (टेस्ट योरसेल्फ गोवा – विथ इनोवैकेयर एवं कोविड लोकेटर), ओडिशा (ओडिशा कोविड डैशबोर्ड), पुदुचेरी (टेस्ट योरसेल्फ पुदुचेरी), तमिलनाडु (कोविड– 19 संगरोध मॉनिटर), कर्नाटक (कोरोना वॉच), केरल (GoK Direct-Kerala)।
- प्रौद्योगिकी के अन्य उपयोगों में रोग की व्यापकता पर सर्वेक्षण चलाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की 1921 टेलीफोन सेवा, कोविड–19 खिलाफ फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का प्रशिक्षण iGOT (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के DIKSHA मंच पर एवं लाइव SWAYAM प्लेटफॉर्म का उपयोग करके केंद्रीय–सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय विद्यालयों के लिए पाठों का प्रसारण, शामिल है।

कोविड–19 से लड़ने के लिए राहत एवं सुधार –

- एक मजबूत डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे ने रुपये का नकद हस्तांतरण सक्षम किया है। वित्तीय सहायता योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत 31 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 28,256 करोड़ स्थांनांतरित किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के माध्यम से 6.93 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया गया।
- 19.86 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को उनके खाते में 500 रुपये प्राप्त हुए।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत लगभग 2.82 करोड़ वृद्ध, विधवा एवं विकलांग लोगों को 400 करोड़ रु वितरित किए गए।
- 2.16 करोड़ निर्माण श्रमिकों को राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित भवन एवं निर्माण श्रमिक कोष से वित्तीय सहायता मिली।

निष्कर्ष –

- न केवल तैनाती बल्कि बल्कि कि भारत में नोवेल कोरोनावायरस के काउंटर के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाना भी रिकॉर्ड स्तर पर रहा है– उदाहरण के लिए, आरोग्य सेतु ऐप 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गया है।
- इस अवसंरचना ने कोविड–19 स्थिति के दौरान, सीधे एवं तुरंत गरीबों एवं जरूरतमंदों को धन हस्तांतरित करने में, करोड़ों परिवारों को लाभ पहुंचाने में सरकार की मदद की है।

ग्रामीण विकास –

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण आबादी के लिए, विशेष रूप से, यह कहीं अधिक प्रभावशाली रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आगमन, विशेष रूप से कृषि में, भारी परिवर्तन देखा गया है एवं इस प्रकार, किसानों के बीच वैज्ञानिक जागरूकता लाने में।
- चाहे मृदा विज्ञान हो, एन्टोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, पशुपालन, या पैथोलॉजी, कृषि विज्ञान की किसी भी शाखा का नाम हो, प्रयोगशालाओं से अनुसंधान एवं विकास समाचार किसानों तक बहुत जल्दी पहुंचता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लाने से मृत्यु दर में कमी आई है, एवं स्वस्थ जीवन शैली इस प्रकार देश में उभरती देखी जा सकती है।
- ग्रामीण क्षेत्र के भीतर नए रोजगार के अवसरों एवं नए व्यवसाय का निर्माण ग्रामीण विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सकारात्मक हस्तक्षेप की पहचान रहा है।
- सटीक मौसम पूर्वानुमान ने हमारे ग्रामीण आबादी के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे दिन हवा हो गए हैं, जब प्राकृतिक आपदाएँ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विनाश करती थीं। उन्नत जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय को इन प्राकृतिक आपदाओं से निकलने वाले जोखिमों को कम करने के लिए विभिन्न एस एंड टी मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करने में मदद करती है।
- सोशल मीडिया अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में एसएंडटी विकास के सहयोगी के लिए एक ओर शक्तिशाली माध्यम है। 'विज्ञान प्रसार' के पास एक समर्पित समूह है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अपडेट का प्रबंधन करता है एवं उन्हें ग्रामीण आबादी के पास समय पर एवं प्रभावी रूप से पहुँचाता है।

लचीली स्वास्थ्य प्रणालियाँ

- भारत ने वर्षों से मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों एवं बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने में निरंतर प्रगति का प्रदर्शन किया है। यह प्रभावी एवं कुशल स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के निर्माण एवं सभी विकास के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करने के लिए, सभी उम्र में, एक निवारक एवं प्रचारक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से सभी विकासात्मक नीतियों में, एवं अच्छी गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य के जो बिना वित्तीय कठिनाई के उपलब्ध हो के सार्वभौमिक पहुंच, के लिए प्रतिबद्ध है।
- कोविड–19 महामारी ने दुनिया भर में लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश के महत्व को बल दिया है। किसी भी समृद्ध एवं उत्पादक राष्ट्र के दुर्जेय आधार बनाने वाले स्वास्थ्य की महत्वत्ता के बारे में राष्ट्रों को फिर से याद दिलाया गया है।
- भारत ने वर्षों से मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों एवं बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने में निरंतर प्रगति का प्रदर्शन किया है।
  1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया।
  2. 2014 में मिशन इन्द्रधनुष को लॉन्च किया गया।
  3. 2016 में, जापानी एन्सेफलाइटिस, रूबेला, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) एवं रोटावायरस से संबंधित टीके जोड़े गए।
  4. 2017 ने न्यूमोनिया से निपटने के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (पीसीवी) को जोड़ा।
  5. पांच एंटीजन (डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाईप बी, एवं हेपेटाइटिस बी) के साथ पेंटावैलेंट वैक्सीन का विस्तार सभी राज्यों में किया गया था।
- मिशन के विभिन्न चरणों में, इसने ग्राम स्वराज अभियान एवं विस्तारित ग्राम स्वराज के कार्यान्वयन को भी देखा। इसने प्रमुख मिशन के साथ सामुदायिक भागीदारी एवं व्यक्तिगत जुड़ाव को बढ़ाया।
- जबकि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ASHA) ने लाभार्थियों को जुटाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, प्रेरित सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) ने पिछले छह वर्षों में सात चरणों में लगभग 37.6 मिलियन बच्चों एवं 9.46 मिलियन गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए।
- हालांकि भारत सरकार ने इस पहल की अगुवाई की, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को मजबूत योजना बनाने, फ्रंटलाइन वर्कर्स की क्षमता निर्माण, त्वरित व्यवहार परिवर्तन संचार में पैंतरे को बढ़ाने एवं कार्यक्रम की निगरानी, एवं मूल्यांकन के लिए लगाया गया।

eVIN

- टीकों एवं आपूर्ति की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने प्रभावी ढंग से स्वदेशी रूप से विकसित eVIN (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) की शुरुआत की, जो तकनीकी समाधानों के माध्यम से टीकों एवं कोल्ड चेन रखरखाव की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
- यह देश के सभी 27,000 कोल्ड चेन सेंटर पर टीके स्टॉक एवं प्रवाह, एवं भंडारण तापमान (2–8 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए रखा जाना) पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है।

आयुष्मान भारत योजना

- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम–जेएवाई) भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य माध्यमिक एवं तृतीयक स्तर पर अपने निचले 40% गरीब एवं कमजोर आबादी को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। इसे भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था।

मुख्य विशेषताएं

1. पीएम–जेएवाई एक स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जो पूरे भारत में 10.74 करोड़ परिवारों को शामिल करती है या लगभग 50 करोड़ भारतीयों को शामिल करती है।
2. यह सार्वजनिक एवं निजी दोनों तरह के अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख का कवर प्रदान करता है।
3. यह अपने लाभार्थियों को सेवा के बिंदु पर, अर्थात अस्पताल में कैशलेस एवं पेपरलेस सेवा प्रदान करता है।
4. सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) के अभाव एवं व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर पात्र लाभार्थियों को कार्ड प्रदान किए जाते हैं।
5. परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
6. पिछले सभी चिकित्सा शर्तों को योजना के तहत कवर किया गया है।
7. इसमें अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन एवं अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन पश्चात्, नैदानिक देखभाल एवं दवाओं पर खर्च शामिल हैं।
8. यह योजना पोर्टेबल है एवं एक लाभार्थी अपने राज्य के बाहर एवं देश में कहीं भी किसी भी पीएम–जेएवाई अस्पताल में चिकित्सा का लाभ उठा सकता है।
9. केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोनावायरस का मुफ्त परीक्षण एवं उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है।

आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र

- आयुष्मान भारत (एबी) निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, पुनर्वास एवं उपशामक देखभाल के लिए व्यापक सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक चयनात्मक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य देखभाल की ओर बढ़ने का एक प्रयास है। इसके दो घटक हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं।

  1. इसके पहले घटक के तहत, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल देने के लिए 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HWCs) बनाए जाएंगे, जो वेलनेस पर ध्यान केंद्रित करने एवं नजदीकी सेवाओं की विस्तारित रेंज की डिलीवरी के साथ, उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वभौमिक एवं निःशुल्क है।

  2. दूसरा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम–जेएवाई) है, जो माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल की मांग के लिए 10 करोड़ से अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है।
- HWC की परिकल्पना विस्तारित रेंज सेवाओं को देने के लिए की गई है जो गैर–संचारी रोगों, उपशामक एवं पुनर्वास संबंधी देखभाल, ओरल, आई एवं ईएनटी देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य एवं आपात स्थिति एवं आघात सहित पहली स्तर की देखभाल के लिए मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से परे हैं।

प्रजनन बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) –

- मातृ एवं बाल स्वास्थ्य में सुधार भारत सरकार की शीर्ष स्वास्थ्य प्राथमिकताओं में से एक रही है।
- इसे देखते हुए, द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ (RCH) 1 कार्यक्रम 15 अक्टूबर, 1997 को देश में शुरू किया गया था।
- पूरे RCH कार्यक्रम के दूसरे चरण यानी RCH–II को 1 अप्रैल, 2005 को लॉन्च किया गया था।
- कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में शामिल परिणामों को साकार करने के लिए मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों यानी कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए एक बदलाव लाना था।
- आरएमसीएच + ए दृष्टिकोण 2013 में शुरू किया गया है एवं यह अनिवार्य रूप से महिलाओं एवं बच्चों के बीच मृत्यु दर के प्रमुख कारणों के साथ–साथ स्वास्थ्य देखभाल एवं सेवाओं तक पहुंचने एवं उपयोग करने में देरी को संबोधित करता है।
- इसे जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को शुरू किया गया है।
- पहचान एवं सेवा प्रावधान में देरी उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा रही है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान (PMSMA)

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल, निःशुल्क प्रदान करना है।
- PMSMA नामित सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में गर्भावस्था के अपने 2/3 तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं के न्यूनतम पैकेज की गारंटी देता है।

कार्यक्रम के लिए तक –

- डेटा इंगित करता है कि भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) वर्ष 1990 में बहुत अधिक था, 5585 महिलाओं के साथ प्रति वर्ष बाल जन्म के दौरान मरने वाली महिलाएं 385 / लाख जन्मों के वैश्विक MMR की तुलना में।
- आरजीआई–एसआरएस (2011–13) के अनुसार, भारत का एमएमआर अब 216/लाख जीवित जन्मों (2015) के वैश्विक एमएमआर के मुकाबले 167/लाख जीवित जन्मों तक गिर गया है। भारत ने 44% की वैश्विक गिरावट की तुलना में 1990 एवं 2015 के बीच एमएमआर में 70% की गिरावट दर्ज की है।
- जबकि भारत ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में काफी प्रगति की है, हर साल लगभग 44000 महिलाएं गर्भावस्था से संबंधित कारणों से मर जाती हैं एवं जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर लगभग 6.6 लाख शिशुओं की मृत्यु हो जाती है।
- यदि गर्भवती महिलाओं को उनके प्रसवकाल के दौरान गुणवत्ता की देखभाल प्रदान की जाती है एवं उच्च जोखिम वाले कारक जैसे गंभीर एनीमिया, गर्भावस्था से प्रेरित उच्च रक्तचाप आदि का समय पर पता लगाया जाता है एवं अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है तो इनमें से कई मौतों को रोका जा सकता है एवं कई लोगों की जान बचाई जा सकती है।

पीएमएसएमएका लक्ष्य –

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान प्रजनन एवं मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच + ए) रणनीति के हिस्से के रूप में निदान एवं परामर्श सेवाओं सहित एंटेनाटल केयर (एएनसी) की गुणवत्ता एवं कवरेज में सुधार करने की परिकल्पना करता है।

PMSMA की मुख्य विशेषताएं –

- PMSMA इस आधार पर आधारित है – कि अगर भारत में प्रत्येक गर्भवती महिला की जांच एक चिकित्सक द्वारा की जाती है एवं PMSMA के दौरान कम से कम एक बार जांच की जाती है एवं फिर उचित रूप से इसका पालन किया जाता है – इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हमारे देश में मातृ एवं नवजात की मौत की संख्या में कमी हो सकती है।
- सरकारी क्षेत्र के प्रयासों के पूरक के लिए निजी क्षेत्र के डॉक्टरों के समर्थन से ओबीजीवाई विशेषज्ञों/रेडियोलॉजिस्ट /चिकित्सकों द्वारा प्रसवपूर्व जांच सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चिन्हित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं (PHCs / CHCs, DHs / शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं आदि) में हर महीने के 9 वें दिन लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुविधा / आउटरीच में नियमित एएनसी के अलावा प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं (जांच एवं दवाओं सहित) का एक न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाएगा।
- एकल खिड़की प्रणाली के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, यह परिकल्पना की गई है कि जांच का एक न्यूनतम पैकेज (गर्भावस्था के दूसरे तिमाही के दौरान एक अल्ट्रासाउंड सहित) एवं IFA की खुराक, कैल्शियम की खुराक आदि जैसी दवाएं PMAMA क्लीनिक में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाएंगी।
- जब लक्ष्य सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंच जाएगा, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के रूप में उन महिलाओं तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे जिन्होंने एएनसी (छूटे हुए एएनसी) के लिए पंजीकरण नहीं किया है एवं जो पंजीकृत हैं, लेकिन एएनसी सेवाओं का लाभ नहीं लिया है।
- निजी क्षेत्र के ओबीजीवाई विशेषज्ञ / रेडियोलॉजिस्ट / चिकित्सकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जहां सरकारी क्षेत्र के चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं या अपर्याप्त हैं।
- गर्भवती महिलाओं को मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड एवं सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका दी जाएगी।
- अभियान के महत्वपूर्ण घटकों में से एक उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान करना एवं उनका पालन करना है। प्रत्येक यात्रा के लिए MCP कार्ड पर गर्भवती महिलाओं की स्थिति एवं जोखिम कारक को दर्शाने वाला एक स्टिकर जोड़ा जाएगा –

  – **ग्रीन स्टीकर**– बिना किसी जोखिम वाले कारक वाली महिलाओं के लिए

  – **रेड स्टीकर** – उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए
- PMSMA के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल एवं एक मोबाइल एप्लिकेशन निजी / स्वैच्छिक क्षेत्र की सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित किया गया है।
- 'IPldgeFor9' अचीवर्स अवार्ड व्यक्तिगत एवं टीम की उपलब्धियों का जश्न मनाने एवं भारत भर के राज्यों एवं जिलों में PMSMA के लिए स्वैच्छिक योगदान को स्वीकार करने के लिए तैयार किए गए हैं।

आने वाले प्रवासियों का कौशल संवर्धन –

- कोविड–19 महामारी के प्रतिक्रियास्वरूप लगाए गए लॉकडाउन के तहत व्यवसाय के बंद होने से सैकड़ों हजारों प्रवासियों को बिहार वापस घर जाना पड़ा।
- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग (BSDMD) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, राज्य के संगरोध केंद्रों (ठैक्डक, 2020) में राज्य को 1.5 मिलियन से अधिक रिटर्न प्राप्त हुए, एवं आने वाले सप्ताहों में संख्या बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि अब सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध हैं। ।
- प्रवासियों में से कई नए सीखे हुए कौशल के साथ लौट रहे हैं, जो उन शहरों में सीखा है जहाँ वे मूल रूप से आजीविका अर्जित करने के लिए निवास करते रहे हैं।
- आत्मनिर्भर भारत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए बुनियादी ढांचे एवं समर्थन को विकसित करने पर केंद्रित है। जल स्वच्छता, पोषण, एवं ग्रामीण विकास जैसे स्पष्ट सामाजिक विकास उद्देश्यों के साथ सरकारी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से आत्मनिर्भर समुदाय के विकास में एक लंबा रास्ता तय होता है।

आगे की राह –

- इन लौटने वाले प्रवासियों को अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता होगी।
- बिहार सरकार के पास राज्य को विकसित करने की दिशा में इस अचानक उपलब्ध जनशक्ति का लाभ उठाने के लिए दोतरफा रणनीति है।
- अल्पावधि में, राज्य मौजूदा सामाजिक विकास योजनाओं के लिए श्रम के लिए श्रमशक्ति की भर्ती करना चाहता है।
- दीर्घावधि में, राज्य एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना चाहता है जो राज्य के भीतर बड़े एवं विकेंद्रीकृत औद्योगिक अवसरों की स्थापना का समर्थन करता है, जो कि उपलब्ध जनशक्ति को धारण करने के लिए है।
- इसलिए, राज्य की सरकार निम्न बिंदुओं पर कार्य कर रही है –

  1. सभी आने वाले प्रवासियों के कौशल की पहचान – जिला स्तर पर, सभी आने वाले प्रवासियों के लिए कौशल मानचित्रण का संचालन यह समझने के लिए किया जाता है कि मांगों को पूरा करने के लिए क्या आपूर्ति योजनाएं मौजूद हैं, एवं रोजगार की जरूरतों का अनुमान क्या है।

  2. व्यापक जिला रोजगार योजना विकास – बिहार सरकार जिला रोजगार योजनाओं को विकसित करने पर काम कर रही है जिसमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं अन्य विकास परियोजनाओं के तहत मजदूरी रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों के अवसरों का विवरण शामिल होगा।
- मौजूदा विकासात्मक गतिविधियों में प्रवासियों के श्रम को शामिल करना बिहार सरकार की बड़ी परियोजनाएं हैं, जिनमें बेहतर स्वच्छता, कम रुग्णता, घर पर नल का पानी की उपलब्धता, मिट्टी की नमी की उपलब्धता एवं समग्र पर्यावरण के संरक्षण के रूप में जनसंख्या के लिए लाभ हैं।
- जल जीवन हरियाली (JJH) पर्यावरणीय स्थिरता में निवेश के जरिए वनों की कटाई, जलस्रोतों के पुनरुद्धार एवं वर्षा जल संचयन के लिए एक आपदा से बचाने वाले बिहार को मजबूत बनाता है।
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (एलएसबीए) में कुशल श्रमिकों के रोजगार के अवसर प्रदान करने की क्षमता है।
- बिहार सरकार भी एलएसबीए (स्वच्छ भारत मिशन) के तहत परिवर्तन गतिविधियों में लगी हुई है, जिसमें शौचालय के उपयोग को बनाए रखने की संभावना है। घर के सभी सदस्यों द्वारा इस नियमित शौचालय का उपयोग घरों को शौचालय के कार्यात्मक रखने में निवेश करने एवं इसे किसी बिंदु पर अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

- बिहार सरकार राज्य में सभी घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करने के लिए, जल जीवन मिशन (JJM) की राष्ट्रीय छतरी के तहत महत्वाकांक्षी योजना– हर घर नल का जल भी लागू कर रही है। इसके लिए पूरे राज्य में एक लाख से अधिक मिनी जलापूर्ति योजनाएँ स्थापित करने की आवश्यकता है। इन गाँव एवं कस्बों स्तर की योजनाओं के लिए उन्हें प्रशिक्षित रखने के लिए प्रशिक्षित प्लंबर एवं यांत्रिकी की आवश्यकता होती है। इसलिए ये योजनाएं कुशल एवं लौटने वाले प्लंबर एवं यांत्रिकी के लिए घर के करीब नौकरियों को खोजने एवं संभावित रूप से छोटे व्यवसायों को स्थापित करने का सही अवसर प्रदान करती हैं जो जेजेएम के लक्ष्यों के साथ अपनी गतिविधियों को संरेखित कर सकते हैं।

प्रगति इतनी दूर –

- जब प्रवासियों के कौशल की मैपिंग की जाती है, संगरोध केंद्रों पर पुल प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है एवं उनकी सेवाओं का उपयोग विभिन्न विकास पहलों में किया जाता है।
- प्रशिक्षण अक्सर लक्षित प्रतिभागी समूह में मौजूदा कौशल का लाभ उठाने एवं उन्हें जोड़ने के लिए नए उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के लिए जोड़ने पर केंद्रित होते हैं।
- उदाहरण के लिए, पोल्ट्री एवं बकरी पालन पर प्रशिक्षण, प्यूमा प्रवासियों में शुरू किया गया है, जिन्हें शायद निर्माण में मौजूदा अनुभव था एवं श्रम कार्य को आवश्यक चिनाई कार्य करने के लिए धनुष पर प्रशिक्षण दिया गया था। यह एक विशेष रुचि से सभी द्वारा किया गया प्रयास है।
- यह पहल जीविका के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी एवं प्रशिक्षित या पहले से ही कुशल प्रवासियों को पहले ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGS) के तहत काम करने के लिए JJHM एवं LSBY के लिए तैनात किया जा चुका है।

औद्योगिक क्लस्टरों का विकास –

- स्थानीय एवं निरंतर उद्योगों को विकसित करने के लिए 2016 की नीति के हिस्से के रूप में, राज्य ने महत्वपूर्ण लाभकारी रोजगार के लिए संभावित चार उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की –
  1. फूड प्रोसेसिंग
  2. चमड़ा
  3. टेक्सटाइल
  4. सूचना एवं तकनीक, नवाचारी तकनीक आधारित सेवाएँ, एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण।

निष्कर्ष –

- बिहार, शेष भारत की तरह, युवा एवं युवा वयस्क आबादी का एक बड़ा हिस्सा है – जो उद्यमियों एवं व्यवसायों के एक समुदाय के निर्माण के लिए अनुकूल है, जो बदले में राज्य में नौकरियों की उपलब्धता बढ़ा सकता है।
- इसलिए, जबकि राज्य के पास पहले से ही औद्योगिक विकास में निवेश के लिए एक पहचानी गई नीति है, राज्य अनिश्चित समय के लिए घर पर आने वाले कुशल प्रवासियों की आजीविका की जरूरतों को पूरा करने वाली पूरक नीतियों को विकसित करने के लिए जगह तलाश सकता है।
- बिहार को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की संभावना, पहुंच में है, यह देखते हुए कि सभी हितधारक – सरकार, नागरिक समाज संगठन, निजी खिलाड़ी – प्रवासियों को एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र की पेशकश करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा

- जिस तरह से प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, एक नया अनुशासन, जिसे शैक्षिक प्रौद्योगिकी (ईटी) कहा जाता है, उभरा है। देश में आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की पहुंच में भारी अंतर को देखते हुए, किसी भी तकनीक की मध्यस्थता वाले समाधानों को पहले डिजिटल डिवाइड को पाटना होगा। प्रौद्योगिकी में नवाचारों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में हाल के नवाचार –

- प्रभा, जिसमें 32 डीटीएच शैक्षिक टीवी चैनलों का एक गुलदस्ता शामिल है, नई दिल्ली में जुलाई 2017 में शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का चौबीसों घंटे प्रसारण करना था।
- स्कूल शिक्षा के लिए की गई सभी तकनीकी पहलों में से, SWAYAM प्रभा कोविड–19 महामारी के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंचने की चुनौतियों का सामना करने में सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरी है।
- देश में आईसीटी अवसंरचना की पहुंच पर्याप्त नहीं है। एनएसएस 75 वें दौर के अनुसार, देश में केवल 10.7% परिवारों (ग्रामीण एवं शहरी दोनों संयुक्त) के पास कंप्यूटर थे, जबकि 23.5% परिवारों के पास इंटरनेट कनेक्शन थे।
- जाहिर है, लॉकडाउन के दौरान छात्रों तक पहुंचने के लिए कोई भी पहल जो इंटरनेट एवं कंप्यूटर पर निर्भर थी, उसकी गंभीर सीमाएँ हैं।
- इसलिए, सरकार ने इन चैनलों (विशेषकर स्कूली शिक्षा से संबंधित, अर्थात NCERT एवं NIOS द्वारा संचालित) को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए निजी सेवा प्रदाताओं में तेजी से कदम बढ़ाया।

प्रौद्योगिकी संचालित सिस्टम – कोविड के दौरान ऑनलाइन शिक्षा –

- SWAYAM PRABHA DTH उन लोगो के लिए चैनलों का प्रसारण करता है जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। स्कूली शिक्षा के लिए 3 चैनल पहले से ही निर्धारित थे, अब 12 और चैनल जोड़े जाने हैं।
- स्काईप के माध्यम से घर से विशेषज्ञों के साथ इन चैनलों पर लाइव इंटरएक्टिव सत्रों के प्रसारण के लिए प्रावधान किए गए हैं।
- साथ ही इन चौनलों की पहुंच बढ़ाने के लिए टाटा स्काई एंड एरियल जैसे निजी डीटीएच ऑपरेटरों के साथ शैक्षिक वीडियो सामग्री को प्रसारित करने के लिए करार भी किए गए हैं।
- राज्यों ने, शिक्षा से संबंधित सामग्री का प्रसारण करने के लिए SWAYAM PRABHA चैनलों पर दैनिक 4 घंटे का समय साझा करने का समन्वय किया है।
- मार्च 24, 2020 के बाद से DIKSHA प्लेटफॉर्म में 61 करोड़ हिट हैं।
- ePathshala में 200 नई पाठ्यपुस्तकों को जोड़ा गया है।
- सरकार का 'वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग' के ज्ञान साझाकरण (DIKSHA) कार्यक्रम के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। DIKSHA ऐप 2017 में लॉन्च किया गया था।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा देश में शिक्षा में प्रौद्योगिकी एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चिंताओं की पहचान करता है। इस तरह की एक चिंता दूरस्थ स्थानों पर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को हल करने एवं बनाए रखने में स्थानीय विशेषज्ञता की उपलब्धता है। जैसे, यह स्कूलों में तकनीकी मुद्दों के प्रबंधन के लिए स्थानीय प्रतिभाओं को तैनात करने की सिफारिश करता है। इस तरह, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के लिए प्रभावी है।

CHAHAL ACADEMY

Chahal Academy has pan India presence

VISIT US AT

N New Delhi: 982-155-3677
Corporate Office
Office No.B-7, Lower Ground floor, Apsara Arcade Near Karol Bagh, Metro Gate No. 7, New Delhi - 110060

M Mumbai Branch: 990-911-1227
415, Pearl Plaza Building, 4th Floor, Exactly opp Station Next to Mc Donalds. Andheri West, Andheri West, Mumbai, Maharasthra,-

K Kolkata : 728-501-1227
31/3, Bankim Mukherjee Sarani, New Alipore, Block J- Siddharth Apartment, 3rd Floor, Opposite Corporation Bank, Kolkata - 700053, West Benga

A Ahmedabad: 726-599-1227
Office No. 104, First Floor Ratna Business Square, Opp. H.K.College, Ashram Road, Ahmedabad - 380009

A Anand: 720-382-1227
Head Office
T9-3rd Floor Diwaliba Chambers,Vallabh Vidyanagar, Near ICICI Bank, Bhai Kaka Statue, Anand - 388120

B Bhubaneswar : 720-191-1227
1899/3902, First Floor, Lane No. 2, Near Laxmi Narayan Temple, Nilakantha Nagar, Nayapalli, Bhubaneswar - 751006, Odisha.

C Chandigarh : 726-591-1227
2nd Floor, SCO-223, Sector-36-D, Above Chandigarh University Office, Chandigarh - 160036.

D Dehradun Branch: 721-119-1227
Near Balliwala Chowk, General Mahadev Singh Road, Kanwali, Dehradun, Uttarakhand- 248001.

G Gandhinagar: 6356061801
Office No. 122 , 1st Floor , Siddhraj Zori , KH, O, Sargasan Cross Road, Gandhinagar, Gujarat 382421

K Kanpur : 720-841-1227
2nd Floor, Clyde House, Opposite Heer Palace Cinema, The Mall Road, Kanpur Cantonment, Kanpur - 208004, Uttar Pradesh.

P Patna : 726-591-1227
3rd Floor, Pramila mansion, Opposite Chandan Hero Showroom, Kankarbagh Patna - 800020, Bihar

R Raipur Branch: 728-481-1227
D-117, first floor, Near Shri Hanuman Mandir, Sector-1, Devendra Nagar, Raipur, Chattisgarh- 492009.

R Rajkot Branch: 762-401-1227
3rd Floor,Balaji House 52 Janta Society Opp LIC Of IndiaTagore Road Rajkot 360001

R Ranchi: 728-491-1227
3rd Floor, SMU Building, Above Indian Overseas Bank, Purulia Road, New Barhi Toli, Ranchi - 834001, Jharkhand.

S Surat: 720-391-1227
Office No. 601, 6th Floor, 21st Century Business Centre, Besides World Trade Centre, Near Udhna Darwaja, Ring Road Surat - 395002

V Vadodara: 720-390-1227
102-Aman Square, Besides Chamunda Restaurant, Behind Fatehgunj Petrol Pump, Vadodara, Gujarat- 390002

COMING SOON : BENGALURU| GUWAHATI |HYDRABAD | JAIPUR | JAMMU | KOCHI | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE

Write us at: chahalacademy@gmail.com | www.chahalacademy.com

Follow us at: YouTube Linked in